7th DIALOGUE INDIA
Academia - Industry Conclave
2023

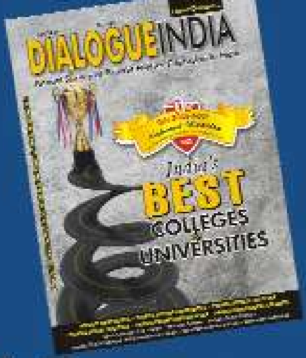

9th DIALOGUE INDIA
International Academia Awards
2023

मूल्य 30/-   जुलाई, 2023

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की राह

तीन मोर्चे
तीन गठजोड़

नये मुद्दे – नये साथियों पर जोर

अमेरिका हुआ 'मोदीमय'

DIALOGUE INDIA

... Dialogue for Change in Education

In association with

PHD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

PRESENT

9th DIALOGUE INDIA International Academia Awards (For Private Higher Education Institutions in India) 2023

7th DIALOGUE INDIA Academia - Industry Conclave 2023

6th Business Connect

"ROLE OF RESEARCH, INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP & ACADEMIA - INDUSTRY CONNECT IN INDIAN HIGHER EDUCATION FOR SELF-RELIANT INDIA"

CHIEF GUEST & KEYNOTE SPEAKER

Sh.Pushkar Singh Dhami Ji
Chief Minister
Uttrakhand

Arjun Ram Meghwal
Minister of Law and Justice , GoI

Padma Vibhushan
Smt. Sonal Mansingh ji,
Member of Rajya Sabha

Inaugural Session

Mr. Saurabh Sanyal
, Secretary General, PHD Chamber of commerce and Industry

Prof (Guru) Pawan Sinha Jee
is a spiritual preceptor, motivator, philosopher, writer and an educationist.

Sh. U P Singh
Formal Secretary Government of India (Textile & Water Resources) Chairman, Natinal Transport Safety Board,GoI

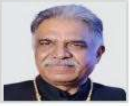

Commander VK Jaitly
National Coordinator Youth4Nation, Board Member, IIT Bhubaneswar, Ex President IIT Kharagpur Alumni Foundation India.

Smt. Nutan Sharma
Ex. Chief Commissioner Income Tax

Sh. Anuj Agarwal
Founder & Group Editor Dialogue India

Dr. Sanjeev Sharma
Editorial Advisor Dialogue India

Mr.Abhishek Dubey
CEO
Business Connect Magazine

Panel Discussion - I
TOPIC - Is India lacking in research & innovation?

C. Rajasekhar, IFS
OSD (States) Ministry of External Affairs, GoI

Commander VK Jaitly
National Coordinator Youth4Nation, Board Member, IIT Bhubaneswar, Ex President IIT Kharagpur Alumni

Prof. Priyaranjan Trivedi
Chairman,IIEE, President Confederation of Indian Universities

Dr. Parmeet Singh Chaddha
Global Chairman- World Sikh Chamber of Commerce
CEO - World Exports (India) Partner- World Ventures

Dr Manpreet Singh Manna
Pro Vice Chancellor Chandigarh University,Mohali Ex. Director All India Council for Technical Education

Sh.Siddharth Jain
Secretary General at FLARE, Advisor EPSI & FICCI

Rakhi Agarwal
Associate Professor & Dean Academic Affairs National Forensic Sciences University Delhi

Panel Discussion - II
TOPIC- World Economic Forum report on employment; threats of climate change; new field of innovation and employment.

Mr. Pradhyumn Lawania
Seasoned Cloud, Cyber Security and

Smt. Nutan Sharma
Ex. Chief Commissioner Income Tax

Prof (Guru) Pawan Sinha Jee
is a spiritual preceptor, motivator, philosopher,

Dr. Deepak Jain
DG
Federation of Indian Industry

Sh. Niraj Kumar
Director
GoI

Sh.Amit Tyagi
Executive Editor
Dialogue India

Panel Discussion - III
TOPIC- G20 & Fourth industrial revolution: Role of Foreign Universities campuses/collaboration in India to enhance contemporary skills, knowledge and Academia - Industry connect.

Mr.Himadrish Suwan
Chairperson
CYL, DG, IIGL

H.E. Freddy Svane
Ambassador
Embassy of Denmark in India

H.E. Hugo Javier Gobbi
Ambassador
Embassy of Argentina

H.E. Chang Jae-bok
Ambassador
Embassy of South Korean

H.E. Naor Gilon
Ambassador
Embassy of Israel

H.E. Emmanuel Lenain
Ambassador
Embassy of France

Dr. J P Pandey
Vice Chancellor
Dr APJ Abdul Kalam Technical University

CHIEF GUEST & KEYNOTE SPEAKER

Gen. V K singh Ji
Minister
Road Transport and Highways

Smt. Meenakshi Lekhi Ji
Minister of State for External Affairs, GoI

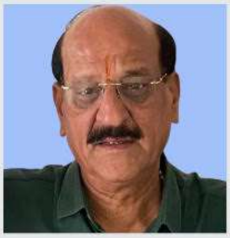

Subodh Uniyal
Minister of forest & technical edu.
Gov. of Uttarakhand

on July 8th 2023, 2 pm to 10 pm.

PHD HOUSE, SIRI INSTITUTIONAL AREA, NIPCCD, HAUZ KHAS, NEW DELHI -16

Our Business & Industry Partner

GTTCI Global Trade & Technology Council of India
FICCI Federation of Indian Industry
WSCC World Sikh Chamber of Commerce

Our Associates

ASMA
FLARE
CYL
GEM MINES
Group Excel India
Excel India Publishers

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की चाह संवाद की राह

जुलाई, 2023

06 अमेरिका हुआ 'मोदीमय'

14 प्रिगोजिन की खुली बगावत : क्या सचमुच यह 'अंत की शुरुआत' है

16 प्लास्टिक से हो रहा पर्यावरण निरंतर बीमार

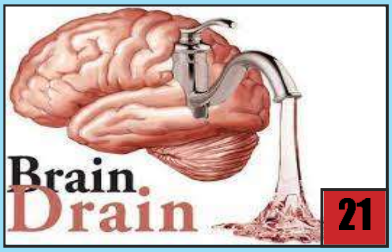

21 कैसे रुके डॉक्टरों का ब्रेन ड्रेन ?

22 अमृतकाल में भारतीय आर्थिक दर्शन के सहारे आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था

28 उच्च शिक्षा : न्यू नार्मल में एब्नार्मल

35 तीन मोर्चे तीन गठजोड़ नये मुद्दे, नये साथियों पर जोर

48 ऑनलाइन गेमिंग एप पर धर्मांतरण का खतरनाक खेल

58 सदी की भीषणतम ट्रेन दुर्घटना

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह संवाद की राह

वर्ष- 14 **अंक- 11**

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक
अमित त्यागी

संपादकीय सलाहकार
संजीव शर्मा, मयंक मधुर एवं सिद्धार्थ जैन

विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, डॉ. अर्चना पाटिल
आदित्य गोयल, डॉ. यशवंत चौधरी

मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)
सम्यक अग्रवाल एवं निर्भय कुशवाहा

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
उत्तराखंड - जितेंद्र गुप्ता
बिहार - नंद शर्मा
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह
गौतमबुद्ध नगर - मनीष गुप्ता
गाजियाबाद - घनश्याम शर्मा

डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक, रजत

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्लेटेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

जुलाई, 2023 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

आग लगती रहेगी , कोचिंग चलते रहेंगे

- अनुज अग्रवाल

देश में कोचिंग के सबसे बड़े हब दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में शार्ट सर्किट से लगी आग से बड़ा हादसा हो गया। दर्जनों छात्र घायल हो गए और अनेक गायब हैं जिनके बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही। कल रात भर हजारों छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया जो अभी भी जारी है। कुछ कोचिंग संस्थानों की आपसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा भी हो सकती है यह आग। बाकी सच तो जांच में ही सामने आएगा और हो सकता है न भी आए।

देश की सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था को बचाने की ज़िम्मेदारी वास्तव में कोचिंग संस्थानों पर ही है। शिक्षा संस्थानो में 90 प्रतिशत में न छात्र पढ़ने आते हैं न अध्यापक पढ़ाने आते हैं। बस वे डिग्री बांटते और बेचते हैं। देश में कोचिंग संस्थान ही एक मात्र ऐसी जगह है जहां शिक्षक पढ़ाने आते हैं और छात्र पढ़ने आते हैं। हां यह सच है कि इन कोचिंग संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर व सेफ्टी नॉर्म्स क़ानून के मापदंडों के अनुरूप नहीं होता। अधिक लाभ के लालच में संस्थान एक बड़े हाल में पाँच पाँच सौ तक बच्चे ठूंस देते हैं। मगर कोई भी छात्र कुछ नहीं बोलता न ही उसके अभिभावक, जबकि सब प्रतिष्ठित परिवारों से होते हैं। चुप्पी इसलिए भी रहती है क्योंकि प्रश्न सुरक्षित भविष्य का होता है जो डिग्री से नहीं कोचिंग के ज्ञान से हो पाता है। अब यह दूसरी बात है कि बिना नियम कायदे से चलने वाले इन संस्थानों से निकलने वाले छात्र आगे चलकर आईएएस/पीसीएस अफसर बन देश के कानून बनाते हैं और देश को कानून से चलाने की बात भी करते हैं। मगर सच्चाई यह भी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के बाद अधिकांश टॉपर अपना रिजल्ट इन संस्थानों को बेचकर करोड़ों कमाते हैं फिर शादी में भी मोटा दहेज लेते हैं और अक्सर नेताओं, नौकरशाह व अरबपतियों के परिवारों में शादी करते हैं और जब तक ट्रेनिंग के बाद नौकरी शुरू करते हैं तब तक छोटे मोटे कारपोरेट खुद ही बन जाते हैं। न जाने कितने नौकरशाह और यूपीएससी के मेंबर व अध्यक्ष रिटायर होने के बाद इन संस्थानों में नौकरी करते दिखते हैं।

इस खेल पर कोई रोक नहीं, सब मौन हैं, सरकार भी, यूपीएससी भी और न्यायालय भी। मेरा देश तो ऐसे ही चला है और ऐसे ही चलेगा, काश कोई बदल पाता यह सब।

गाल बजाता विपक्ष

देश की राजनीति में विचित्र तरह की हलचल है। समूचा विपक्ष मानो मोदी सरकार के तख्तापलट को तैयार बैठा हो। लेकिन विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी तो शरद पवार को उनके भतीजे अजित पवार ने जी तरह बीच मझधार में छोड़ एनडीए का दामन थामा उससे इनके नेतृत्व पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए।लोकसभा चुनाव पास आते देख यह हलचल होना स्वाभाविक भी है। लगातार दो बार मात खाया विपक्ष किसी भी कीमत पर सत्ता वापसी के लिए संघर्ष करता दिख भी रहा है मानो यह आर पार की लड़ाई हो। तो एनडीए भी हर कीमत पर तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ताल ठोक रहा है।हाल ही में पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जुटे 16 -17 विपक्षी दलों ने अनेक आपसी मतभेद और सत्ता संघर्ष के बीच भी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की चिंता कांग्रेस पार्टी के तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से गहरे मतभेद सामने आ ही गए। सैद्धांतिक रूप से साथ लड़ने की कसमें खाने के बाद अब जुलाई में बैंगलोर में कांग्रेस पार्टी की पहल और नेतृत्व में विपक्षी जुटान होगा। बहुत सारे विपक्षी दल नीतीश कुमार की इस पहल से दूर रहे तो उधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अपने विस्तार की तैयारी में जुटा दिख रहा है। कुल जमा अभी विपक्ष औपचारिक गठजोड़, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और नेतृत्व इन सभी मुद्दों पर आत्ममंथन और चिंतन कर रहा है। हाँ यह स्पष्ट दिख रहा है कि वे सब भाजपा के प्रखर राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद की राजनीति से घबराए हुए हैं किंतु इसकी कोई काट या तोड़ उनके पास दिखाई नहीं दी और वे सेकुलरवाद व तुष्टिकरण के नारे पर ही टिके हुए हैं।

विपक्ष का अनेक दलों में बंटा रहना, आपस में विलय कर एक दल न बना पाना, एक सर्वमान्य नेतृत्व न ढूँढ पाना तो उनकी असफलता के सर्वमान्य लक्षण हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से खांसी बहस हो चुकी है किंतु विपक्ष का उससे भी बड़ा संकट है बदलते समय और परिस्थितियों से तालमेल न बैठा पाना। विपक्षी दल पिछले नौ सालो में देश में हुए विकास व केंद्र सरकार की प्रत्येक पहल में व्यापक जन सहभागिता को समझ ही नहीं पा रहा। हमेशा नकारात्मक व आलोचनात्मक रहना, देश विदेश में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश करना, देश में अल्पसंख्यकवाद व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, बिना राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर तुरंत लाभ के लिए गलत नीतियों को अपने शासित राज्यों में लागू करना, राष्ट्रवाद व हिंदुत्व के मुद्दों का मौखल उड़ाना आदि आदि। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि अब देश में अल्पसंख्यकवाद और सेकुलर पंथी 'बाँटो और राज करो' की राजनीति सिकुड़ रही है और राष्ट्रवाद, विकास की राजनीति बहुसंख्यकवाद व नरम हिंदुत्व तेजी से जगह बना चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पर्याय बन चुके हैं। विपक्ष ने पिछले नौ सालो में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जीएसटी, नोटबंदी, किसानों व पेंशन जैसे अनेक मुद्दों पर भ्रमित करने वाला जमीनी संघर्ष किया किंतु जनता ने अंततः मोदी सरकार का साथ दिया। जनता बदलाव चाहती है और इसलिए वह हर रोज नई पहल करने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। युवाओं के देश भारत की जनता अनेक विसंगतियों व चुनौतियों के बाद भी हमेशा सकारात्मकता व हर कीमत पर आगे बढ़ते रहने को तैयार रहती है , इसलिए उसने कोविड जैसे महामारी को भी झेलकर देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पूर्व की स्थिति में खड़ा कर दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत को वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है। हाल के अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी एक 'महानायक' बनकर उभरे हैं।जो सम्मान, समर्थन और महत्व उनको मिला वह अविस्मरणीय है। अमेरीका की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में जैसा भव्य स्वागत हुआ और अमेरिकी संसद में उनके संबोधन को जिस तरह सराहा गया, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि दोनों देशों के संबंध एक नए युग में पहुंच रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों के संबंध एक लंबे समय से प्रगाढ़ हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरीका में शायद ही इतनी महत्ता मिली हो।

लेकिन भारत का विपक्ष इस बड़ी उपलब्धि पर देश के साथ खड़ा नहीं दिखता। अमेरीका एवं भारत के बीच बढ़ती प्रगाढ़ता से चीन पर भारत की निर्भरता न्यूनतम हो जायेगी। चीन की दादागिरी उसके लिये कितनी नुकसानदेय साबित हो रही है कि एक बड़ा बाजार चीन के हाथ से निकल रहा है। अगर विपक्ष को देश की मुख्यधारा की राजनीति में रहना है तो उसको भी अपना दृष्टिकोण, चिंतन, कार्योजना व शैली सब बदलने होंगे। इसके साथ ही आपसी विलय कर एक दल के रूप में सामने आना होगा और मोदी जी के समकक्ष उतना ही योग्य प्रतिद्वंदी खड़ा करना होगा अन्यथा उनकी सारी रेस अपने अस्तित्व को जैसे तैसे बचाने की रह जाएगी, देश की सत्ता में तो वे आने से रहे।

निश्चित रूप से अनेक राज्यों में विपक्ष भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है और विपक्ष के पास अनेक क्षेत्रीय कद्दावर नेता हैं जिनकी अपने अपने प्रदेश में व्यापक लोकप्रियता और विश्वसनीयता है किंतु कोई एक भी राष्ट्रीय स्तर की सोच और व्यक्तित्व वाला नहीं है। इसी कारण आज की केंद्र की राजनीति की दिशा और मुद्दे भाजपा ही तय करती है और विपक्ष उसका मात्र पीछा करता दिखता है। कश्मीर से धारा 370 कि हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो या अब समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात, भाजपा अपने मूल एजेंडे से कभी नहीं भटकी। अब शीघ्र पाक अधिकृत कश्मीर पर भी कब्जे की हुंकार देश के रक्षा मंत्री कर रहे हैं तो नए पेंशन बिल को भी लाने की तैयारी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पिछले कुछ समय में अपनी सरकार के नौ साल पूरे होने पर सैकड़ों रैली कर चुका है, हजारों योजनाएं पूरी कर लागू की जा रही हैं और विपक्ष बस एकता के नाम पर गाल बजा रहा है।

अनुज अग्रवाल
संपादक

अमेरिका हुआ 'मोदीमय'

● अशोक श्रीवास्तव

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की शुरुआत अमेरिका की या यूं कहें कि दुनिया की वाणिज्यिक राजधानी न्यूयोर्क से होगी, जहां वो करीब सवा दिन बिताने के बाद वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जायेंगे। न्यूयोर्क में मोदी यूएन हेडक्वार्टर में योग करेंगे, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका के रिश्तों का नया इतिहास रचा जायेगा।

हम पत्रकार अति उत्साह में कई बार किसी एक शब्द को इतनी बार प्रयोग में ले आते हैं कि जब वास्तव में सही परिप्रेक्ष्य में इसके इस्तेमाल का वक्त आता है तब हमें वो शब्द छोटा लगने लगता है। नरेंद्र मोदी की इस बार के इस बार के अमेरिका दौरे को लेकर मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका दौरे पर आये थे, तब से लेकर अब तक वो 7 बार यहां आये हैं और मुझे उनकी ज्यादातार यात्राओं की रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला है, और इन 7 यात्राओं में से मोदी की कई अमरीकी यात्राओं को हम पत्रकार ऐतिहासिक करार कर चुके हैं, इसलिए इस बार जब मोदी अमेरिका आये हैं तो उनकी इस यात्रा के लिए ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग करना कुछ हल्का लग रहा है। लेकिन इसमें मेरे जैसे पत्रकारों का ज्यादा दोष भी नहीं है। दरअसल 2014 से लेकर अब तक मोदी ने अपनी अमरीकी यात्राओं में पहले नए नए रिकॉर्ड बनाये और फिर अपने ही बनाये रिकॉर्ड सुधारे या तोड़े। मुझे याद है कि 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के करीब 4 महीने बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका आये, यहां आने से पहले उन्होंने भारत में जीत का एक रिकॉर्ड बनाया था, जब तीन दशक में पहली बार भारत में किसी एक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को अपने बूते पर बहुमत मिला था। इसके बाद मोदी जब न्यूयोर्क आये तो ये दौरा इसलिए बहुत बड़ी खबर बना क्यूंकि इससे पहले यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका ने उन्हें वीजा न देकर अपने देश आने नहीं दिया था, और करीब एक दशक बाद इन्हीं नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया है। भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में मनमोहन सिंह के आलावा भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को अमेरिका ने राजकीय यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया, न पंडित जवाहर लाल नेहरू को, न श्रीमती इंदिरा गांधी को और न ही राजीव गांधी को। अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी निवास व्हाइट हॉउस में जब मोदी पहुंचेंगे तब उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उनके सम्मान में व्हाइट हॉउस में स्टेट बैंक्वेट दिया जायेगा।

साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका आये तो सचमुच वो यात्रा तब ऐतिहासिक हो गयी जब मोदी ने न्यूयोर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में करीब 19 से 20 हजार भारतवंशियों को सम्बोधित किया, क्यूंकि इससे पहले भारत क्या शायद किसी भी देश के राजनेता ने विदेशी धरती पर जाकर अपने देश के मूल निवासियों की इतनी विशाल जनसभा को कभी सम्बोधित नहीं किया था। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पर नरेंद्र मोदी अमेरिका में इतनी जल्दी इतिहास को दोहराएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था पर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अगले ही साल मोदी ने कैपीफोर्निया के बे-एरिया में पहुंच कर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का इतिहास दोहरा दिया। इन दौरों के साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस एक साल में भारत की विदेश नीति में डायस्पोरा डिप्लोमेसी के एक नए आयाम को जोड़ दिया, फिर साल 2019 में नरेंद्र मोदी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर इतिहास रच दिया जब ह्यूस्टन में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50 हजार भारतवंशी जुड़े और अब मोदी जब 9 साल में अपनी 8वीं अमेरिका यात्रा पर आये हैं तो फिर इतिहास बनने जा रहा है। 75 वर्षों में अमेरिका के राजकीय मेहमान बनकर आने वाले वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं तो साथ ही साथ 22 जून को नरेंद्र मोदी जब अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे तो ऐसा करने वाले वो भारत के पहले राजनेता हो जायेंगे, और दुनिया के पांचवें। इसके साथ-साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते आज जितने सहज,

उपलब्धियों भरा रहा अमेरिका दौरा, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मिला नया आयाम

भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी से जुड़ी उम्मीदों को व्यक्त किया। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों देश 21वीं सदी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री का यह दौरा कई उपलब्धियों से भरा रहा जिसमें रक्षा वाणिज्य और रणनीतिक तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी।

विवेक देवराय और आदित्य सिन्हाः पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हुए हैं। इस दौरान वाणिज्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी के स्तर पर दोनों देश में व्यापक सहयोग बढ़ा है। अपने पहले कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की द्विपक्षीय रिश्तों को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाल में प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय अमेरिकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में यह नई ऊंचाई प्रत्यक्ष रूप से नजर आई। इसमें वे कड़ियां स्पष्ट रूप से दिखीं जो दोनों देशों के लोगों को बहुत मजबूती से जोड़ती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति बाइडन द्वारा दिए गए राजकीय भोज और अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने के अवसर ने इस दौरे को यादगार एवं ऐतिहासिक बना दिया। ऐसा मौका केवल अमेरिका के बेहद निकट सहयोगी मित्रों को मिलता है। कुछ साझा वैश्विक चिंताओं और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देशों की संवेदनशीलता ने भारत-अमेरिका रिश्तों को नया आयाम दिया है। दोनों देशों ने वाणिज्य और रक्षा उपकरणों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। अमेरिका भी भारत के साथ रिश्तों को रणनीतिक एवं सकारात्मक निहितार्थों के नजरिए से देखता है।

भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी से जुड़ी उम्मीदों को व्यक्त किया। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों देश 21वीं सदी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री का यह दौरा कई उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें रक्षा, वाणिज्य और रणनीतिक तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। इसी दौरान दिग्गज अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन ने भारत में निवेश और अपनी प्रस्तावित गतिविधियों का एलान किया। यह अमेरिका और भारत के बीच परस्पर नवाचार और आर्थिक गठजोड़ के भविष्य का संकेत करता है।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस दौरान रक्षा, तकनीक और निवेश के स्तर पर बहुत सकारात्मक संकेत मिले। सबसे पहले रक्षा की बात करें तो हालिया रुझानों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की आधुनिक रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए रूस पर निर्भरता उचित नहीं। ऐसे में अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी बिल्कुल सही समय पर आगे बढ़ रही है। इससे भारत की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी होने के साथ ही दोनों देशों के बीच सामरिक गठजोड़ भी मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अत्याधुनिक ड्रोन्स की खरीद का एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ। इससे सेना, नौसेना और वायुसेना की निगरानी एवं मारक क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिकी दिग्गज जीई और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ समझौता भी बड़े महत्व का है। इससे भारत की सामरिक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा बदलाव आएगा जो रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए मूल रूप से रूस पर निर्भर रही है। इससे आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण भी होगा।

तकनीकी मोर्चे पर उपलब्धियों की बात करें तो भारत और अमेरिका रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग, सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसर तलाशने की दिशा में आगे बढ़े हैं। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े आर्टेमिस अनुबंध को लेकर सहमति जताई और मानव अभियान के लिए भी नासा के साथ साझेदारी की है। अमेरिकी कंपनी भारत में विविधीकृत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए भी तैयार हुई है। खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत को जोड़ने पर भी अमेरिका ने अपना समर्थन जताया है। साथ ही एड्वांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और क्वांटम इन्फोर्मेशन साइंस को लेकर भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक ढांचा भी स्थापित किया है।

पूंजी निवेश इस समय भारत की एक बड़ी आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख अमेरिकी उद्यमियों से इस मुद्दे पर आवश्यक मंत्रणा की। प्रधानमंत्री के इस दौर ने अमेरिकी निवेशकों के बीच भरोसे और नीतियों को लेकर आश्वासन भरा ऐसा परिवेश बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई कंपनियां भारत में निवेश करने और अपने निवेश को बढ़ाने के लिए तत्पर हुई।

मिसाल के तौर पर गूगल ने डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इसी तरह एमेजोन ने 26 अरब डालर के निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात कही है। आने वाले समय में अमेरिका से भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के इस दौर ने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नया क्षितिज प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई।

अमेरिका प्रवास को लेकर भारतीयों को पेश आने वाली मुश्किलों का हल भी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर निकाला गया। इसके अंतर्गत अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को अपना एच1बी वीजा नवीनीकरण के लिए भारत आना जरूरी नहीं रह जाएगा। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अतिरिक्त, वीजा प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए अमेरिका बेंगलुरु एवं अहमदाबाद में नए काउंसलेट स्थापित करने की योजना बना रहा है। वहीं, भारत भी इस वर्ष सिएटल के अतिरिक्त दो अन्य अमेरिकी शहरों में काउंसलेट स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसे दौर में जब भारत तेज आर्थिक वृद्धि के पथ पर अग्रसर है तब प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और उनकी रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सक्रियता ने वैश्विक स्तर पर भारत के कद को बढ़ाया है। यह प्रगति भारत को एक ऐसे जीवंत एवं गतिशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करती है, जो वैश्विक विमर्शों को आगे बढ़ाने, साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक ढांचे के भविष्य को आकार देने में सक्षम है।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर-निजी सचिव अनुसंधान हैं)

मोदी ने बताया 'AI' का नया मतलब, कहा- ये अमेरिका-इंडिया है

प्रधानमंत्री मोदी ने आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि आज का दौर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का है। मैं आपको आज एक और AI से अवगत कराता हूं। इस AI को मैं अमेरिका और इंडिया कहकर बुलाता हूं।

हमने 200 वर्षों में आपसी मूल्यों को बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमने 200 वर्षों से आपसी विश्वास को बढ़ाया है। दोनों ही देशों पर महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर का असर है। दो सदी तक हमने एक-दूसरे को प्रभावित किया है। भारत और अमेरिका के लिए लोकतांत्रिक मूल्य मायने रखते हैं।

साल में बहुत कुछ बदला

PM मोदी ने बताया कि यहां मैं 7 वर्ष पहले आया था, उस दौरान में मैंने कहा था कि इतिहास की हिचक कभी हमारे साथ चलती थी, अब हम नई राह पर खड़े हैं। 7 साल पहले से लेकर अबतक काफी कुछ बदला है। लेकिन भारत-अमेरिका के बीच दोस्ती बरकरार है।

उन्होंने कहा कि भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं। एक हजार से ज्यादा भाषाएं हैं। हर 100 मील पर खानपान बदल जाते हैं। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है। भारत का विकास दूसरे देशों को प्रेरित करता है।

ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन में हो रहे खून-खराबे को रोकने के लिए हर तरह से कोशिश करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि ये दौर युद्ध का नहीं है।

ये दौर कूटनीति और बातचीत का है। प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में चीन पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा, ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान ये हुआ है कि सप्लाई चेन सीमित हो गई है। हम मिलकर कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन भी डी-सेंट्रलाइज्ड हो और लोकतांत्रिक हो।

प्रधानमंत्री मोदी ने की ग्लोबल CEOs से मुलाकात, कंपनियों ने किया निवेश का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन सिलिकॉन वैली के कुछ सबसे पावरफुल CEOs से मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनके साथ थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

मुलाकात में अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और एप्पल के CEO टिम कुक शामिल थे।

भारत की आकांक्षाओं को आगे ले जाने का बड़ा अवसर - PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय प्रतिभा और अमेरिकी तकनीकी प्रगति के साथ आने से बेहतर भविष्य की गारंटी होगी। उन्होंने आगे कहा कि ये राष्ट्रपति बाइडेन के विजन और क्षमताओं और भारत की आकांक्षाओं और संभावनाओं को आगे ले जाने का बड़ा अवसर है।

बाइडेन प्रशासन चीन के साथ तनाव के चलते भारत पर खास फोकस कर रहा है। कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन में रुकावटें आई हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी को लेकर भी चीन के साथ चिंताएं बढ़ी हैं। बाइडेन ने कहा कि हमारे देश इनोवेशन और को-ऑपरेशन को नए स्तर पर लेकर जा रहे हैं।

दुनिया की नजर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों, भारत अमेरिका पर - PM मोदी

PM मोदी ने कहा, 'तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में दुनिया की नजर हम दोनों सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है। हमारी मित्रता वैश्विक शांति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखने वाले देशों के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। मुझे भरोसा है हम दोनों ही पूरी दुनिया के सामर्थ्य को बढ़ाने में कहीं अधिक सफल होंगे।'

क्यों खास है PM मोदी का दौरा

प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है, अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में भारत एक डिप्लोमैटिक और मिलिट्री संतुलन देता हैं। चीन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसके बिना अमेरिका का भी काम चलना मुश्किल है, अब चीन से अपनी दूरियां बढ़ा रहा है।

चीन नहीं तो कौन? या चीन प्लस वन पॉलिसी में उसके सामने विकल्प के रूप में भारत है, इसलिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों के लिए ये मुलाकात काफी खास है। दोनों ही देश चीन को खतरे के रूप में देखते हैं।

बीते कुछ समय में एक तरफ बाइडेन चीन के एक्सपोर्ट पर लगाम कस चुके हैं तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भी सीमा तनाव के चलते सैकड़ों चीनी ऐप पर बैन लगा चुके हैं।

रेगुलेटरी दिक्कतों को दूर करना प्राथमिकता!

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि दोनों देशों के एजेंडे में व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी दिक्कतों को दूर करना प्राथमिकता है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जो बाइडेन किसी भी सूरत में नहीं चाहते है कि चीन को एडवांस चिप्स और दूसरी टेक्नोलॉजी मिले, वो हर हाल में ऐसी स्थिति को रोकना चाहते हैं।

यही वजह है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि जब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, लचीली सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों की बात आती है तो भारत के मुकाबले दूसरा कोई अहम भागीदार नहीं है। किर्बी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 'हम जानते हैं कि भारत आने वाले दशकों के लिए एक रणनीतिक साझेदार बनने जा रहा है'

डिफेंस सेक्टर तक फैल रहा तकनीकी सहयोग

अमेरिका के साथ तकनीकी सहयोग का दायरा अब डिफेंस सेक्टर में भी फैल रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स मोदी की यात्रा के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए दोनों पक्षों के पास एक फ्लेक्सिबल लाइसेंसिंग समझौता होगा।

अमेरिका हर किसी के साथ अपनी सैन्य तकनीक को साझा नहीं करता है। अमेरिका स्थित काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एक वरिष्ठ फेलो मंजरी चटर्जी मिलर ने कहा-'GE को भारत में जेट इंजन बनाने की अनुमति देने वाला सौदा ये दिखाएगा कि अमेरिका साझेदारी को कितनी गंभीरता से ले रहा है।'

नया डिजिटल कानून लाने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका यात्रा भारत के तकनीकी इकोसिस्टम के लिए एक बेहद जरूरी वक्त पर हुई जहां गूगल, मेटा और ट्विटर जैसे बड़े नामों के सलाह से और कभी-कभी विवाद के बीच एक नया डिजिटल कानून तैयार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ हफ्तों में ये मसौदा ये निर्धारित करने में मदद करेगा कि भारत विदेशी कंपनियों के लिए कितना बड़ा मौका दे सकता है।

स्पेस से डिफेंस तक, वकरूमोदी की अमेरिका यात्रा से क्या हासिल हुआ?

दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। PM नरेंद्र मोदी के पहले अमेरिकी राजकीय दौरे ने दोनों देशों के रिश्ते में कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। इस यात्रा के दौरान डिफेंस, स्पेस, ॥-1B वीजा के नियमों में ढील और व्यापार समेत अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान हुए हैं।

अब तक भारत को क्या हासिल हुआ?

- टेक्नोलॉजी (Technology Partnerships)
- सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करना
- माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में 6,760 करोड़ रुपये (825 million) का निवेश करेगी। कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबली का निर्माण करेगी।
- Applied Materials चिप सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर सेंटर बनाएगी।
- मिनरल (Critical minerals partnership)
- दोनों देश के बीच एनर्जी मिनरल्स सप्लाई चेन के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है।
- भारत की एप्सिलॉन कार्बन लिमिटेड ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री में . 650 मिलियन का निवेश करेगी।
- स्पेस के क्षेत्र में (Space Exploration)
- भारत ने चंद्रमा, मंगल और उससे आगे की खोज के लिए 26 अन्य देशों के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- NASA और ISRO 2024 में ISS के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं।
- Quantum, Advanced Computing and Artificial Intelligence
- दोनों देश ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटी रिसर्च के लिए Indo-U.S. Quantum मैकेनिज्म स्थापित करने की सहमति दी है।
- स्टार्ट-अप (Startup Collaboration)
- भारत-अमेरिका के बीच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और हाईटेक अपस्किलिंग पर चर्चा इनोवेशन हैंडशेक का काम करेगी.
- फाइबर ऑप्टिकल (Fiber Optics Investments)
- भारत की स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने कोलंबिया के पास ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए . 100 मिलियन का निवेश किया है जो भारत से ऑप्टिकल फाइबर के सालाना एक्सपोर्ट में 150 मिलियन का मदद करेगा।
- रक्षा के क्षेत्र में (Next-Generation Defense Partnerships)
- हथियारबंद ड्रोन
- भारत द्वारा जनरल एटॉमिक्स के MQ-9 रीपर हथियारबंद ड्रोन की खरीद पर मेगा डील का ऐलान हुआ है. ये एक ऐसा कदम है, जो न केवल हिन्द महासागर में, बल्कि चीन के साथ सीमा पर भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करेगा
- जनरल इलेक्ट्रिक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने संयुक्त रूप से स्न -414 जेट इंजन का उत्पादन भारत में करने का प्रस्ताव दिया है।
- अमेरिकी नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में LXT शिपयार्ड के साथ एक मास्टर शिप रिपेयर समझौता किया है।
- ग्लोबल हेल्थ, स्थायी विकास
- भारत का VSK एनर्जी LLC अमेरिका में सौर पैनल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए . 1.5 बिलियन तक का निवेश करेगा, जिसमें कोलोराडो में 2.0 गीगावॉट मॉड्यूल-एंड-सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल है।
- JSW स्टील USA ओहियो में अपने स्टील प्लांट में . 120 मिलियन का निवेश करेगा
- अमेरिका, भारत एक भुगतान सुरक्षा तंत्र (payment security mechanism) बनाएंगे जो भारत में 10,000 मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा।
- अमेरिका, भारत अवैध दवाओं के अवैध उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए एक व्यापक, काउंटरनारकोटिक्स फ्रेमवर्क विकसित कर रहे हैं।

कूटनीति

दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में दो नए वाणिज्य दूतावास (कॉन्स्यूलेट) खोलेगा, जबकि भारत सिएटल में एक मिशन स्थापित करेगा।

H-1 वीजा

अमेरिका अब ऐसा ॥-1ऱ वीजा पेश करने के लिए तैयार है, जिसे देश में रहकर ही रिन्यू किया जा सकेगा। ये एक अहम फैसला है, जो अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीय पेशेवरों को अपने वर्क वीजा के नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा की परेशानी के बिना अपनी नौकरी जारी रखने में मदद करेगा।

भारत पर अमेरिका क्यों लट्टू हो रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है। जहां आज उनके सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट-हाउस में राजकीय रात्रिभोज दिया जाएगा, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह आठवीं अमेरिका यात्रा है, जो ऐसे समय पर हो रही है, जब दोनों देश तेजी से बदलती दुनिया में अवसरों के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

बीते 75 वर्षों में जब भी किसी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की, तब दोनों के भीतर हलचल बढ़ना सामान्य बात रही है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा, अमेरिका के राजनीतिक और नीतिगत समुदाय में दो कारणों से अभूतपूर्व हो गई है। एक- अमेरिकी संसद में दोनों सदनों के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार, कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण मिला है। उनसे पहले अमेरिका ने यह सम्मान केवल दो बार ब्रितानी प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और दो इजराइली प्रधानमंत्रियों (नेतन्याहू-राबिन) को दिया था। दूसरा- बाइडेन प्रशासन के ढाई वर्ष के कार्यकाल में इस प्रकार का उच्चतम राजनयिक स्वागत (राजकीय भोज सहित), फ्रांसीसी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपतियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। यह आदर-सत्कार केवल व्यक्तिगत नहीं, अपितु एक राष्ट्र के रूप में भारत के प्रति आए आमूलचूल वैश्विक परिवर्तन को रेखांकित करता है।

अमेरिका घोषित रूप से विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत- दुनिया की सबसे तेज आर्थिक प्रगति के साथ ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जर्मनी को पछाड़ने के मार्ग पर प्रशस्त है और दुनिया की बड़ी सामरिक ताकतों में से एक है। विदेशी आक्रांताओं के घृणा प्रेरित चिंतन और गुलाम मानसिकता से ग्रस्त पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को तिलांजलि देकर नया भारत, बाह्य मापदंड-एजेंडे के अनुरूप चलने के बजाय अपने हितों को केंद्र में रखकर शेष विश्व के लगभग सभी सभ्य देशों (अमेरिका सहित) से अपनी शर्त पर संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। अमेरिका प्रदत्त वैश्विक प्रतिबंधों के बाद भी अप्रैल 2022 से भारत न केवल रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, साथ ही वह देश का दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता भी बन गया है। इस वर्ष मई में भारत ने रूस से 19.6 लाख बैरल तेल का आयात किया था, जो अप्रैल की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

यक्ष प्रश्न है कि जिस अमेरिका ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई पाबंदियां थोपी थी, वह उसके साथ निकटता बढ़ाने को क्यों व्याकुल है? क्या इसका एकमात्र कारण दोनों देशों का विस्तारवादी चीन के साथ हालिया गतिरोध है? वर्ष 2000 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौर से दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिला है। वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ। फिर वर्ष 2009 में राष्ट्रपति ओबामा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को अपने प्रशासन के पहले राजकीय आगंतुक के रूप में आमंत्रित किया। इसके अगले वर्ष भारत यात्रा में आए ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया, बाद में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (वासेनार) में भारत की सदस्यता पर सफलतापूर्वक काम भी किया।

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर ओबामा वर्ष 2015 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ट्रंप प्रशासन में अन्य उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सफलताओं के बीच भारत-अमेरिका के संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए। वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान केंद्रित क्वाड को नए स्तर पर पहुंचाकर आई.टू.यू.टू. (भारत, इजराइल, यूएई, यूएस) नामक नए बहुपक्षीय मंच का गठन किया, जिसमें भारतीय हितों को स्वीकार्यता मिली। इसी वर्ष 7 मई को अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) ने इसी समूह के अंतर्गत अपनी पहली बैठक की थी। इससे पहले, 31 जनवरी को भारत-अमेरिका एनएसए ने वाशिंगटन में इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसेट) का विमोचन किया था, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नए स्तर पर पहुंचा दिया। इस समय भारत-अमेरिका किसी भी अन्य गैर-संबद्ध देशों की तुलना में अधिक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। बीते डेढ़ दशक में भारत, अमेरिका से 20 अरब डॉलर से अधिक की रक्षा आपूर्ति खरीदने का अनुबंध कर चुका है, तो अब वह तीन अरब डॉलर के सशस्त्र ड्रोन आपूर्ति को अंतिम रूप देना चाहता है। दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और जीई जेट इंजन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु समझौते पर भी काम कर रहे है।

भारत-अमेरिका के संबंध रणनीतिक- विशेषकर आर्थिक केंद्रित है। वर्ष 2022 में दोनों देशों का व्यापार 191 अरब डॉलर पहुंच गया था, जोकि 2014 की तुलना में दोगुना है। जहां अमेरिकी कंपनियों ने उत्पादन से लेकर दूरसंचार तक भारत में 60 अरब डॉलर का निवेश किया है, तो भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी, दवाइयों और अन्य क्षेत्रों में क्षेत्र में 40 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इससे कैलिफोर्निया से जॉर्जिया तक सवा चार लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। फरवरी में एयर इंडिया ने 200 से अधिक बोइंग विमानों की खरीद की घोषणा की थी, जिससे अमेरिका के 44 राज्यों में दस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

कुछ अमेरिकी सांसद नाटो प्लस में भारत को शामिल करने का सुझाव दे रहे है। भारत की वर्तमान विदेश नीति, रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर आधारित है, इसलिए भारत के लगभग सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। जहां भारत क्वाड का सदस्य है, तो वह शंघाई सहयोग संगठन का भी हिस्सा है। भारत को जी7 बैठक में निमंत्रित किया जाता है, तो वह ब्रिक्स का भी अंग है। वास्तव में, नाटो प्लस का दांव, एशिया में विस्तारवादी चीन पर अंकुश लगाने हेतु भारत का मात्र एक साधन बनाने का उपक्रम है, जिससे भारतीय नेतृत्व अवगत है। साथ ही आतंकवाद जैसे अत्यंत गंभीर विषय पर अमेरिका के दोहरे मापदंडों (गुड-बैड तालिबान सहित) से भी, भारत परिचित है।

- बलबीर पुंज, लेखक वरिष्ठ स्तंभकार, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय-उपाध्यक्ष हैं।

स्वाभाविक और सशक्त हो गए हैं, वैसे आज से पहले कभी नहीं थे।

अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब अमेरिका भारत से रिश्तों को हमेशा पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश के साथ नाप-तौल कर देखता था, और भारतीय भी भारत के नेताओं से हमेशा ये उम्मीद करते थे कि जब भी वो अमरीका के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान की शिकायत जरूर करें, लेकिन आज भारत अमेरिका रिश्तों में पाकिस्तान का 'बैगेज' कहीं नहीं है। बल्कि अमेरिका अब एशिया में नेतृत्व, इंडो पैसिफिक रीजन में संतुलन और जलवायु परिवर्तन में लीडर के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका देख रहा है, दोनों देश सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार हो गए हैं। अमेरिका ने भारत को ऐसे स्ट्रेटजिक पार्टनर का दर्जा दिया है जो उसने दुनिया के किसी भी गैर नाटो देश को नहीं दिया। रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका हमेशा अति संवेदनशील रहा है और रक्षा सौदे बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ही करता रहा है, पर उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे में अमेरिका भारत के लिए अपनी इस कसम को भी तोड़ देगा।

जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है 2022-23 ऐसा लगातार दूसरा साल रहा जब अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। तो इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि 22 जून को जब व्हाईट हाउस में जो बाइडन और नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो अगले एक दशक के लिए भारत अमेरिका के संबंधों का रोडमैप तय कर देंगे।

और ये सब देखने के लिए बीते 3 दिन से मैं अमेरिका में हूं, और यहां व्हाईट हाउस के अस पास लहराते तिरंगे झंडे देखा कर लोगों को भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते सुनकर आज 2023 में मुझे 2003 की बरबस ही याद आ रही है, तब मैं पहली बार अमेरिका आया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके दौरे की रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन तब ये देखकर बहुत निराशा हुई कि अमेरिका का सत्ता प्रतिष्ठान, अमरीकी मीडिया और अमरीकी लोग भारत के प्रधानमंत्री के दौरों को बहुत हलके में लेते हैं। डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल में 8 बार अमेरिका दौरों पर आये लेकिन ऐतिहासिक परमाणु संधि करने के बाद भी वो अमरीकी सोच को नहीं बदल सके, लेकिन आज अमरीका के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, अमरीकी मीडिया नरेंद्र मोदी के अमरीका आने पर फ्रंट पेज पर हेडिंग लगाता है कि अमरीका में भारत के प्रधानमंत्री का रॉकस्टार जैसा स्वागत हुआ और इसीलिये नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरों को मैं हमेशा ही ऐतिहासिक कहता हूं और तब तक कहता रहूंगा जब तक मुझे इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा शब्द नहीं मिल जाता।

● ● ● ●

एक दूसरे की आर्थिक क्षमताओं का इस्तेमाल - प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा?

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करने के साथ साथ, तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के दरवाजे खोलने वाला है।

भारत, अमेरिका, व्यापारिक संबंध, व्यापार, रफ्तार, वित्त वर्ष, कोविड-19, चीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), साझीदारी, विदेशी निवेश, FDI, C+v, निर्माण, सेवा, निर्यात, आयात, सरप्लस

पिछले दो वर्षों के दौरान, भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों ने काफी रफ़्तार पकड़ी है। अब इसके पीछे कोविड-19 महामारी का हाथ था या नहीं, इस बात पर बहस हो सकती है। लेकिन, तरक्की का ये दौर महामारी के असर से उभरती हुई दुनिया के साथ साथ चला है। वित्त वर्ष 2021-22 से अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन गया है। उसने कुल व्यापार मूल्य के मामले में चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे भारत के पारंपरिक व्यापारिक साझीदारों को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत और अमेरिका के बीच 80.51 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1195 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी एक साल में दोनों देशों के आपसी व्यापार में 48.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मोटे अनुमान के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2022-23 में भी दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोत्तरी की ये रफ़्तार बनी रही है और इसमें 7.65 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है। भारत जिन गिने चुने बड़े देशों के साथ सरप्लस व्यापार (आयात से ज़्यादा निर्यात) करता है, उनमें अमेरिका के साथ उसका सरप्लस सबसे ज़्यादा है।

इस तरह निर्यात, आयात और ट्रेड सरप्लस के मामले में अमेरिका के साथ भारत का सामानों का व्यापार, लगातार हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जिसे हम चित्र 2 में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 202-21 के दौरान, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी 81.72 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान 17.94 अरब डॉलर के योगदान के साथ अमेरिका, भारत में दूसरा सबसे बड़ा FDI निवेशक बनकर उभरा है। यहां इस बात पर ध्यान देना दिलचस्प होगा कि ये सारी उपलब्धियां उस वक़्त हो रही हैं, जब China+v (C+v) रणनीति के उभार के साथ, वैश्विक व्यापार के मंजर में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज जब कारोबारी अपने निर्माण और उत्पादन के स्रोत के लिए विविधता लाते हुए चीन पर जरूरत से ज़्यादा निर्भरता को कम कर रहे हैं, तो C+1 की रणनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इस नजरिए के तहत, चीन के अलावा भारत जैसे देशों में उत्पादन के वैकल्पिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे चीन पर बहुत अधिक केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलों के जोखिमों को कम करने के साथ साथ, नए और उभरते हुए बाजारों तक पहुंच के रास्ते बनाए जा सकें।

चीन+1 का माहौल और भारत-अमेरिका के व्यापार के लिए संभावनाएं

भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध ऐसे वक़्त में गहरे हो रहे हैं, जब वैश्विक बाजार अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से हटाकर, उसके आस-पास के दूसरे उभरते बाजारों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों बातों का मेल इस बात का स्पष्ट इशारा देता है कि C+1 रणनीति ने भारत के लिए कितने अच्छे अवसर उपलब्ध कराए हैं। अपने ग्राहकों के विशाल बाजार, हुनरमंदर कामगारों और निवेशक के लिए मुफीद नीतियों के कारण भारत, निर्माण और सेवा के क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प के तौर पर उभरा है।

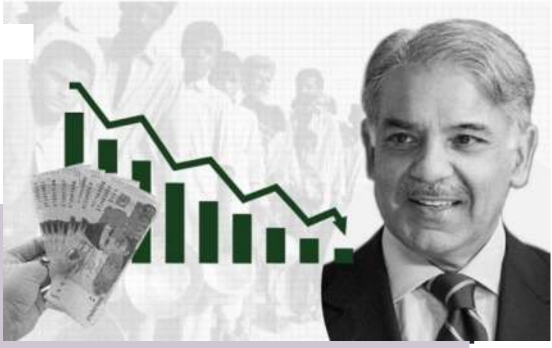

पाकिस्तान में जिन्ना का घर स्वाहा

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में जितना योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रहा है, पाकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्ति में उसी स्तर का योगदान कायदे आजम अर्थात् मौहम्मद अली जिन्ना रहा है, यही कारण है कि दोनों ही व्यक्तित्व को अपने-अपने देश में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। दोनो ही महानुभावों ने अंग्रेजो के विरूद्ध संघर्ष में अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग किया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के पश्चात, जनता का पाकिस्तानी फौज के विरूद्ध जो आक्रोश हुआ, वह अचम्भित करने वाला था। जनता के इस विद्रोह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनता फौज को तनिक भी क्षमा करने पक्ष में नहीं है। अपने इसी आक्रोश में उसने अपने जन्मदाता, मौहम्मद अली जिन्ना का घर अग्नि में स्वाहा कर दिया।

सम्भवतया पाकिस्तान के आर्मी कमाण्डर, असीम मुनीर ने यही सोचा था कि इमरान को बंदी बनाने से जनता का आक्रोश एक-दो दिन के पश्चात शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा। तत्पश्चात वे इमरान के विरुद्ध जो 100 से ज्यादा वाद विभिन्न न्यायालयों में दायर किए हैं, उनमें से किसी में भी सजा के पश्चात इमरान की पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाकर इमरान का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, परन्तु असीम मुनीर की नीति उनकी योजना के विपरीत परिणाम लेकर आई। सम्भवतया इमरान और उनके अधिकारियों ने भी आर्मी कमाण्डर की योजना को भांप लिया था, जिस कारण इमरान समर्थक और सेना के मध्य विरोध बढ़ता चला गया।

पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय जो प्रारम्भ से ही इमरान खान के समर्थन में है, उसने, सरकार को आदेश दिया कि वह 11.05.2023 को इमरान को न्यायालय में उपस्थित करे। इमरान के न्यायालय में उपस्थित होने पर कुछ कानूनी कार्यवाही के पश्चात, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। उनके बंदीगृह से मुक्ति के पश्चात आशा यह थी कि जनता का आन्दोलन समाप्त हो जायेगा, परन्तु फौज और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विरूद्ध यह आन्दोलन और भी तीव्र गति से प्रारम्भ हो गया और सम्पूर्ण पाकिस्तान अपने इतिहास में प्रथम बार आग कि लपटों में जलने के लिए विवश हो गया। स्थिति इतनी भवावह हो गई है कि जनता, आर्मी कमाण्डर और शहबाज शरीफ के सहयोगियों के घरों को चुन-चुनकर आग हवाले कर रही है और वहां पर सिविल वार की उपस्थिति उत्पन्न हो गई है।

शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पाकिस्तान की स्थिति पूर्व की अपेक्षा अत्यधिक निम्न स्तर की हो चुकी है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की पूर्ति बाधित हो रही है। पश्चिमी देश तथा अरब देशों से भी सहायता नहीं मिल पा रही है, अमेरिका से भी मिलने वाली सहायता बंद हो गई है और चीन भी अपनी भावी योजनाओं पर पैसा लगा रहा है, अतः वह किसी की भी मदद करने का इच्छुक नहीं है। इस प्रकार पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति से, भारत को अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि पाकिस्तान में हालात शीघ्र ही नहीं सुधरे तो, पाकिस्तानी फौज के पास एक ही मार्ग शेष रहेगा कि वो भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे और अपनी जनता को युद्ध के नाम पर भ्रमित कर शांत रहने और आपसी भेदभाव भुलाकर भारत के समकक्ष विकास के लिए प्रार्थना करें।

योगेश मोहन

इससे, अमेरिका जैसे बड़े साझीदारों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी।

अमेरिका, भारत के सर्विसेज के निर्यात का एक बड़ा बाजार रहा है। और अब C+1 रणनीति के उभरते हुए माहौल से इन व्यापारिक अवसरों को और भी बढ़ावा मिलेगा।

C+1 की रणनीति से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उत्पादन की सुविधाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत स्थानांतरित करने में दोनों ही देशों के लिए संभावनाओं के अभूतपूर्व अवसर दिखते हैं। मीडिया की ख़बरों के मुताबिक, अपने विदेशी मिशनों के माध्यम से सरकार ने क़रीब 1000 ऐसी अमेरिकी कंपनियों से संपर्क साधा है, जो अपना निर्माण केंद्र चीन से हटाना चाहते हैं। भारत, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा उद्योग और ऑटोमोटिव जैसे तमाम क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल उन अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कर सकता है, जो अपना कारोबार चीन से हटाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ, 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, अमेरिका के घरेलू उत्पादन और निर्माण को मजबूती देने की कोशिशों से मेल खाती हैं। इनसे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए एक मजबूत बुनियाद मिलेगी।

इसके अलावा, अमेरिका और भारत के बीच ये तालमेल वस्तुओं के व्यापार से भी आगे जाता है। IT आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट और बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट जैसी सेवाएं, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार का अभिन्न अंग रही हैं। अमेरिका, भारत के सर्विसेज के निर्यात का एक बड़ा बाजार रहा है। और अब C+1 रणनीति के उभरते हुए माहौल से इन व्यापारिक अवसरों को और भी बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे की पूरक शक्तियों और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साझा प्रयासों के जरिए, भारत और और अमेरिका सेवा क्षेत्र में भी और नजदीकी संबंध क़ायम कर सकते हैं, जिससे दोनों ही देशों में प्रगति और नौकरियों में बढ़ोत्तरी के नए अवसर पैदा होंगे।

भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों का विस्तार भविष्य के लिए काफी संभावनाओं से भरा है। आज जब अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बनकर उभर रहा है, तो दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होने तय हैं। चीन+1 के मंजर की वजह से जो अवसर पैदा हुए हैं, उनके साथ साथ तमाम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मिलकर, दोनों ही देशों के लिए लाभकारी व्यापारिक संबंधों की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे का एक और अहम पहलू नवीनीकरण योग्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का है। भारत और अमेरिका दोनों ही जलवायु

परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ भविष्य केक लिए जरूरी बदलाव लाने को प्राथमिकता देने की अहमियत समझते हैं।

हालांकि, विकास की इस गति को टिकाऊ बनाने के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान खोजना होगा। व्यापार में बाधाएं, बौद्धिक संपदा के अधिकार, नियमों में तालमेल और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों का समाधान सकारात्मक वार्ताओं और संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए। एक संतुलित और निष्पक्ष व्यापारिक माहौल से भरोसा और विश्वास जगेगा, जिससे कारोबार जगत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकेगा।

भारत अमेरिका के बीच व्यापार को मजबूत बनाना : प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा

इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का मौजूदा अमेरिका दौरा, भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दौरा मौजूदा साझेदारियों को मजबूत बनाने और सहयोग के नए अवसरों की स्थापना के लिए एक मंच का काम करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी नेताओं के बीच बातचीत में तकनीकी सहयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा संबंध और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

तक़नीकी क्षेत्र में, भारत और अमेरिका में खूब फल-फूल रहा तक़नीकी इकोसिस्टम है, और दोनों ही देश इनोवेशन के मामले में अगुवा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग से इस साझेदारी को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। इससे साझा अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां, तकनीक का लेन-देन और निवेश के प्रवाह और मुकाबला कर पाने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। तकनीकी क्षेत्र के इन आविष्कारों और खूब तरक्की कर रहे डिजिटल इकॉनमी के क्षेत्र का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में (सस्ती स्वास्थ्य सेवा और दवाओं के मामले में) और शिक्षा (दोनों देशों के शिक्षण संस्थानों के बीच आपस में और रिसर्च के काम में) भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक सहयोग के सेक्टर में भी काफी सहयोग बढ़ सकता है।

रक्षा सहयोग, भारत और अमेरिका के रिश्तों का आधार रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार में काफी वृद्धि होती देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, रक्षा संबंधों को और गहरा बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसमें रक्षा उपकरणों की ख़रीद, साझा युद्ध अभ्यास और तकनीक का लेन-देन शामिल है। भारत और अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद का समझौता होने की संभावना है- ऐसे सहयोग न केवल रक्षा क्षमताओं में इजाफा करते हैं, बल्कि साझा उद्यमों और दूसरे तरीकों से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

प्रधानमंत्री के दौरे का एक और अहम पहलू नवीनीकरण योग्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का है। भारत और अमेरिका दोनों ही जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ भविष्य केक लिए जरूरी बदलाव लाने को प्राथमिकता देने की अहमियत समझते हैं। नवीनीकरण योग्य ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, मिलकर उत्पादन और उनके इस्तेमाल के क्षेत्र में साझा प्रयास, काफी कारोबारी अवसर पैदा कर सकते हैं और पर्यावरण के साझा लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हरित परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ ईंधन की परियोजनाओं में निवेश, तकनीक का आदान-प्रदान और ज्ञान को साझा करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

निश्चित रूप से भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के लिए भू-राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से टकराव का स्रोत चीन ही है। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरान इस बात को मजबूती देने वाला है कि द्विपक्षीय संवाद के साथ साथ बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत के भी दोनों देशों के लिए फायदेमंद नतीजे निकलने आवश्यक हैं। एक तरफ तो भारत के निर्यात को अमेरिका की शक्ल में एक तैयार बाजार मिलता है, जो मोटे तौर पर 'खपत वाली अर्थव्यवस्था' (यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी खरीदने की क्षमता और खपत करने की क्षमता और आदत बहुत अधिक हो) है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारत में सस्ती मजदूरी और प्रचुर मात्रा में खपाने के लिए बाजार उपलब्ध होता है, जिसमें काफी संभावनाएं हैं। भारत की आबादी वाली बढ़त सस्ते हुनरमंद कामगारों की शक्ल में दिखती है, जहां मजदूरी की लागत चीन की तुलना में केवल दस प्रतिशत है। वहीं दूसरी तरफ, भारत के भौतिक मूलभूत ढांचे में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए बड़े पैमाने पर बदलाव ने कारोबार करने की लागत को काफी कम कर दिया है।

बाइडेन प्रशासन द्वारा की गई आर्थिक पहल हिंद प्रशांत आर्थिक फोरम (IPEF) में भारत समेत 14 संस्थापक देश शामिल हैं। अगर इस मंच को एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते की रूप-रेखा में बदला जा सके, तो ये मंच भारत के लिए एक बड़ा मौका उपलब्ध कराता है।

बाइडेन प्रशासन द्वारा की गई आर्थिक पहल हिंद प्रशांत आर्थिक फोरम (IPEF) में भारत समेत 14 संस्थापक देश शामिल हैं। अगर इस मंच को एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते की रूप-रेखा में बदला जा सके, तो ये मंच भारत के लिए एक बड़ा मौका उपलब्ध कराता है। इसके दो कारण हैं: पहला, इस मंच में चीन शामिल नहीं है तो ये चीन से मुक्त क्षेत्रीय व्यापार समझौता होगा; दूसरा, अगर ये लागू हो जाता है, तो इससे भारत के उस नुक़सान की भरपाई हो जाएगी, जो उसके रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमिक पार्टनरशिप (RCEP) से अलग होने की वजह से हुआ था। RCEP के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इससे अपने MSME सेक्टर को नए बाजारों तक पहुंच बनाने देने का मौका भारत के हाथ से निकल गया।

हमने इस लेख में जिन विषयों की चर्चा की, उससे व्यापार और निवेश के रूप में अमेरिका और भारत के बीच एक दूसरे के आर्थिक पूरक की भूमिका साफ तौर पर नजर आती है। चीन+1 के माहौल की वजह से जो अवसर पैदा हुए हैं, उनका लाभ उठाते हुए और संतुलित एवं निरपेक्ष व्यापारिक माहौल को पोषित करके, दोनों देश एक ताक़तवर साझेदारी विकसित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और उनके व्यापक सामरिक हितों को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया अध्याय शुरू हुआ है। अब दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच खूब फलते फूलते व्यापारिक संबंध का माहौल बिल्कुल तैयार है।

ORF से साभार

देबोस्मिता सरकार

निलंजन घोस

प्रिगोजिन की खुली बगावत से पूतिन की साख पर जबर्दस्त चोट

क्या सचमुच यह 'अंत की शुरुआत' है

● रंजीत कुमार

रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के प्रमुख यवगेनी प्रिगोजिन ने 24 जून को जिस तेवर में रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था, उससे लगने लगा था कि रूस की राजनीति में सुनामी आने ही वाला है। लेकिन यह बवंडर तक ही सीमित रह गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन इस बवंडर से हालांकि निकल आए हैं, मगर उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है।

उनकी स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है और निश्चित रूप से उनके मनोबल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।

यह यूक्रेन और उनके समर्थकों देशों का रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प और मजबूत करेगा, क्योंकि अब यह माना जाएगा कि पूतिन सत्ता पर अधिक दिनों तक काबिज नहीं रह सकते।

कहां से आया भस्मासुर

पूतिन क्या, किसी भी रूसी ने नहीं सोचा होगा कि रूस में सत्तारूढ़ दल के आला नेताओं या सेना के कमांडरों से अलग, बाहर का कोई गुट सत्ता हथियाने के लिए ऐसे क्रेमलिन पर चढ़ाई कर सकता है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव ने तो साफ-साफ कह दिया, 'रूसी राष्ट्रपति पूतिन के अंत की यह शुरुआत है।' साफ है कि इस प्रकरण से अपने देश के भीतर पूतिन की निजी प्रतिष्ठा पर आंच आई है और यह रूस पर शासन करने के मंसूबे पालने वाले अन्य नेताओं या सैन्य जनरलों को सत्ता हथियाने की साजिश तेज करने को प्रेरित करेगा।

पूतिन के लिए भी इस सचाई को हजम करना मुश्किल हो रहा होगा कि अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जिस प्राइवेट आर्मी को उन्होंने 2014 में खड़ा किया था, उसका मुखिया अचानक भस्मासुर की तरह बर्ताव करते हुए अपने गुरु की ही कुर्सी छीनने पर उतारू हो गया। बहरहाल खबरों के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात कर उन्हें लड़ाई से पीछे हटने को मना लिया, लेकिन हकीकत यही है कि प्रिगोजिन अच्छी तरह समझ रहे थे कि मास्को पर चढ़ाई के दौरान दोनों ओर से भारी गोलाबारी होगी और रूसी सेना किसी भी कीमत पर वैगनर की सेना को परास्त करेगी। पूतिन प्रिगोजिन की जान बख्शने के समझौते का कब तक आदर करेंगे, यह कहना भी मुश्किल है। बहरहाल, पूतिन से जुड़े प्रिगोजिन के अतीत पर एक नजर डालनी खासी दिलचस्प हो सकती है।

डाके के आरोप में 12 साल जेल की सजा काटने के बाद प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक कॉफी-रेस्तरां खोला था।

वहां तब के डेप्युटी मेयर व्लादिमीर पूतिन अक्सर जाते थे। तभी से दोनों की दोस्ती की बात स्थापित हुई। दोस्त पूतिन की प्रेरणा से प्रिगोजिन ने बाद में मीडिया बिजनेस में भी हाथ डाला।

उन्हीं के आशीर्वाद से प्रिगोजिन ने एक सुरक्षा कंपनी खोली, जिसने देश-विदेश में पांव जमाए।

वैगनर कंपनी के सैनिकों और एजेंटों का पूतिन ने नॉन स्टेट ऐक्टर यानी गैर राजकीय गुट की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखल भी शामिल है। अफ्रीका और पश्चिम एशियाई देशों में भी वैगनर सक्रिय रहा।

प्रिगोजिन के कोई राजनीतिक विचार नहीं हैं। वह ज्यादा शिक्षित भी नहीं हैं।

स्वाभाविक ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह चिंता की बात है कि अगर प्रिगोजिन जैसा कोई छुटभैया नेता रूस की सत्ता पर काबिज हो जाता है तो एक बड़ी परमाणु और मिसाइल ताकत के प्रबंधक के तौर पर वह बाकी विश्व नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करेगा।

वैगनर की प्राइवेट सेना में करीब 50 हजार सैनिक हैं जिनमें से करीब 25 हजार यूक्रेन में लड़ने भेज दिए गए। वैगनर ने रूसी जेलों में

वाहनों पर सवार इस विद्रोही मिलिशिया के काफिले को प्रिगोजिन ने मास्को से 200 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, जिससे राष्ट्रपति पूतिन को सांस लेने का मौका जरूर मिल गया। लेकिन यह मामला यहां खत्म हुआ नहीं माना जा सकता।

आगे की मुश्किलें

इस घटना के बाद से पूतिन खुद को और असुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत संभव है कि वह अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ तनाव और बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं की आड़ लेने और इस तरह अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करने का विकल्प चुनें। लेकिन ऐसा हुआ, तो साथी नेताओं और सैन्य कमांडरों के बीच उनके प्रति असंतोष और बढ़ेगा। इससे यूक्रेन के खिलाफ सैन्य हमला कर रहे रूसी सैन्य कमांडरों के मनोबल पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यूक्रेन के भीतर तैनात रूसी और वैगनर जवानों के बीच आपसी मतभेदों का लाभ भी यूक्रेन की सेना को मिलेगा।

साफ है कि पूतिन की आगे की राह आसान नहीं है। प्रिगोजिन ने भले ही रूसी राष्ट्रपति को सत्ताच्युत करने का विफल प्रयास किया, लेकिन इससे यूक्रेन के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का मनोबल जरूर बढ़ेगा। ■

सजायाफ्ता कैदियों को माफी दिलवाने का वादा कर यूक्रेन के भीतर जाने के लिए राजी किया। प्रिगोजिन का आरोप था कि रूसी रक्षा मंत्री सर्जेई शोएगू और सेना प्रमुख वेलेरी जिरासोमोव की वजह से यूक्रेन में लड़ाई के दौरान वैगनर के जवानों को वक्त पर गोला-बारूद और अन्य जरूरी रसद नहीं मिलती थी। इससे करीब दस हजार वैगनर सैनिकों की मौत हो गई। प्रिगोजिन ने वैगनर और सरकारी सेना के सैनिकों के बीच भेदभाव का भी आरोप लगाया। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर भी प्रिगोजिन ने सवाल उठाए। पूतिन का सीधा जिक्र किए बिना प्रिगोजिन ने उन पर निशाना साधा और उन्हें सत्ता से बेदखल करने की परोक्ष चेतावनी भी दी। 24 जून की सुबह को उनके कमांडरों ने यूक्रेन में लड़ रहे 25 हजार सैनिकों का विशाल काफिला लेकर मास्को की ओर कूच कर दिया। चाहे जिस वजह से भी हो, मगर टैंकों और बख्तरबंद

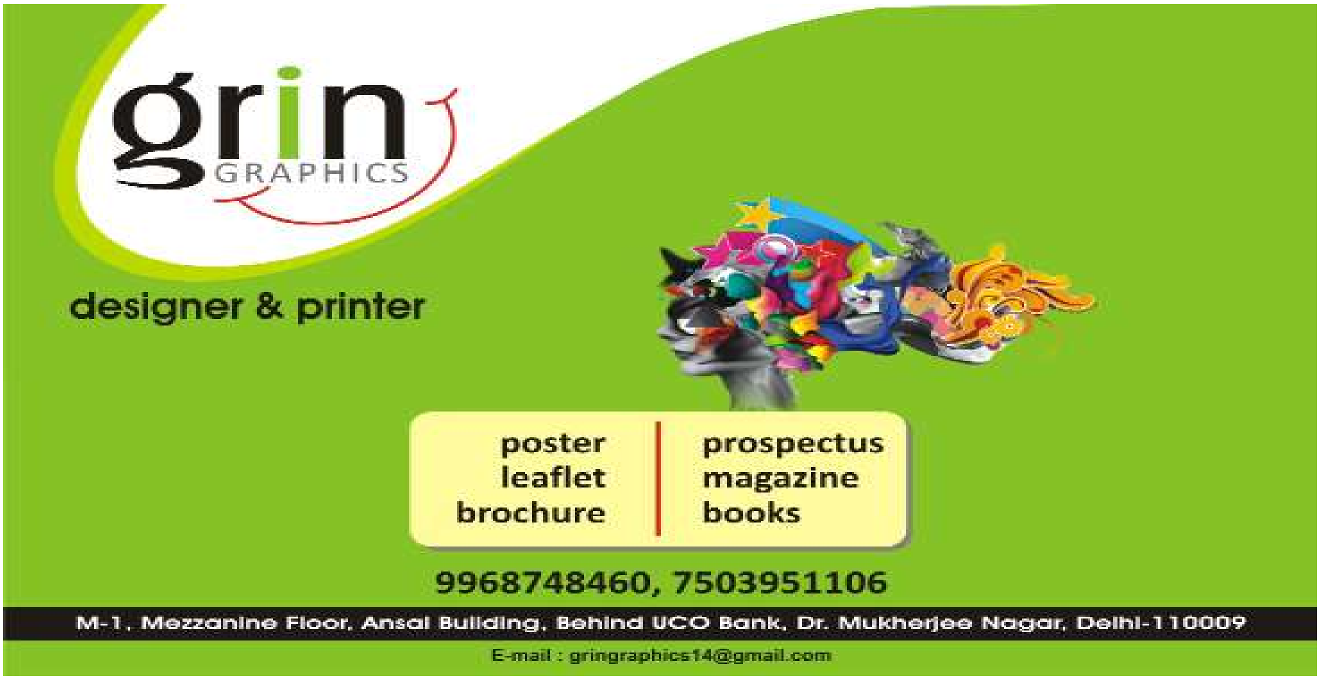

प्लास्टिक से हो रहा पर्यावरण निरंतर बीमार

● **सुनील कुमार महला**

बढ़ती आबादी और विकास के बीच अब धीरे धीरे पहाड़ों के स्वास्थ्य को लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पहाड़ों में अंधाधुंध कटान, जंगलों की आग (दावानल) और शहरों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण की सेहत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। मिट्टी, पानी और हवा पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। कटते पहाड़ों से जहां भूस्खलन जोन बढ़ रहे हैं। वहीं, प्रदूषण से धरती की आबोहवा दूषित होने के साथ ही आग भी हमारे ईको सिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) को लगातार प्रभावित कर रही है। प्लास्टिक कचरा पहाड़ों के लिए एक अन्य बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण यहां बहुत से लोग हर साल घूमने फिरने के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद हिल स्टेशन ही होते हैं। वास्तव में सच तो यह है कि आजकल पहाड़ प्रदूषण मुक्त क्षेत्र नहीं रह गये हैं और समय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बहुत अधिक होने के का कारण प्रदूषण भी बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी कचरा जमा होने लगा है। आज यदि देश के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नजर दौड़ाएं तो हम यह पाएंगे कि पर्यटन स्थलों पर आज सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा है। हैरत यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आज कोई भी गंभीर नजर नहीं आता हैं। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उत्तराखंड में भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, लेकिन गंभीर है कि प्लास्टिक का कचरा पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। यह जानकारी देना चाहूंगा कि देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी का मतलब इन चीजों को बनाना, आयात करना, जमा करना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनकी सेल करना, इस्तेमाल करने आदि पर रोक है। वास्तव में इन सामानों की उपयोगिता कम है और तुरंत फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक को अमूमन लोग इस्तेमाल के बाद यत्र यत्र यूं ही खुले में फेंक देते हैं और इससे शहरों की नालियां, सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जब बारिश होती है तो यह पानी के साथ बहकर नदी-नालों में जमा हो जाता है। इससे जल प्रदूषण होता है। प्लास्टिक की विघटन प्रक्रिया में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए जब प्लास्टिक हो भूमि के अंदर दबा दिया जाता है तो यह विघटित नहीं हो पाता है और जहरीली गैसें और पदार्थ छोड़ता रहता है। इस कारण वहां की भूमि बंजर हो जाती है। वहां अगर कोई फसल पैदा भी होती है तो उसमें जहरीले पदार्थ मिले होने से यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्लास्टिक से ज्यादातर वस्तुएं ऐसी बनाई जाती हैं जो मानव द्वारा इस्तेमाल करने के बाद फेंक दी जाती हैं। इनमें पानी की बोतलें, खिलौने, टूथ ब्रश, पैकिंग का सामान, पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक के बॉक्स आदि। प्लास्टिक को खुले में फेंकने पर इसमें आवारा कुत्तों व अन्य जानवरों, पशुओं द्वारा मुंह मारा जाता है और वे भूखे होने के कारण खाद्य वस्तुओं के साथ प्लास्टिक की थैलियों आदि को यूं ही निगल जाते हैं और उनकी असमय मौत हो जाती है। जानकारी देना चाहूंगा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 चीजों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। यह सामान यानी वह प्लास्टिक का सामान जो फेंकने से पहले या रिसाइकल करने से पहले सिर्फ एक बार ही

अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल, सरकार चाहती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे-धीरे करके कई चरणों में लोगों की जिंदगी से हटाया जाए। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। सरकार का यह कदम वास्तव में अत्यंत काबिले तारीफ कहा जा सकता है, क्यों कि प्लास्टिक हजारों सालों तक भी गलता सड़ता नहीं है और मानव समेत धरती के प्राणियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स या प्लास्टिक (पॉलिथीन) की थैलियों को इन 19 चीजों में शामिल नहीं किया गया है लेकिन पिछले साल ही यानी कि वर्ष 2022 में ही इनकी मोटाई को बढ़ाकर 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन कर दिया गया था। सरकार के अनुसार प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक लगाई गई है। वास्तव में आज प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे हमारी धरती पर उपलब्ध पहाड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, क्यों कि पहाड़ हमारी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को, हमारे पर्यावरण को, हमारी धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को सुंदर व अच्छा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन

हिमालय के 80 प्रतिशत ग्लेशियर को भारी खतरा

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने यह चेतावनी दी है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह बढ़ता रहा तो हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र के अस्सी फीसदी ग्लेशियर वर्ष 2100 तक नष्ट हो जाएंगे। यह संकेत इस संस्था की ताजा रिपोर्ट से मिला है।

यह रिपोर्ट भावी पीढ़ियों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जगाती है कि यदि बढ़ते पर्यावरणीय तापमान को कम करने के गंभीर प्रयास न हुए तो आने वाले आठ दशकों के बाद हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र के अस्सी फीसदी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की यह चेतावनी खतरे की घंटी है कि सुधर जाइए अन्यथा कुदरत के रौद्र का सामना करने के लिये तैयार रहें।

संस्था को अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आशंका है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह बढ़ता रहा तो हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र के अस्सी फीसदी ग्लेशियर वर्ष 2100 तक नष्ट हो जाएंगे। दुनिया में ध्रुवीय इलाकों के अलावा सबसे ज्यादा बर्फ इन्हीं इलाकों में जमा है। जिसे एकत्र होने में हजारों साल लगे हैं। अध्ययन के निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं कि इस सदी के पहले दशक के मुकाबले दूसरे दशक में ग्लेशियर 65 फीसदी तीव्र गति से पिघले हैं, जो स्थिति की भयावहता को ही दर्शाते हैं।

ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान के स्तर का पता इस बात से चलता है कि वर्ष 2100 तक यदि इसी गति से ग्लेशियर पिघलते रहे तो इस क्षेत्र के दो अरब लोगों के रोजगार व जीवन पर भयावह असर पड़ेगा। इससे न केवल हमारी सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी , बल्कि पशुधन की भी भारी क्षति होगी। हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर और बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से जो जीवनदायी पानी क्षेत्र की बारह नदियों के लिये निकलता है, वो करीब चौबीस करोड़ लोगों के पेयजल का मुख्य स्रोत भी है। इतना ही नहीं, यदि तेजी से ग्लेशियर पिघलते हैं तो भीषण बाढ़-हिमस्खलन से भारी पैमाने पर मानवीय क्षति भी होगी। दो साल पहले उत्तराखंड के चमोली जनपद में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही को दुनिया ने देखा था। हमें भविष्य में ऐसे संकटों के लिये तैयार रहना होगा।

हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला में पिघलते ग्लेशियरों पर अध्ययन करने वाले इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट नामक अंतर-सरकारी संगठन में भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान व म्यांमार के सदस्य शामिल हैं। अध्ययन चेताता है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रहती है तो क्षेत्र के ग्लेशियर वर्ष 2100 तक तीस से पचास प्रतिशत तक पिघलेंगे। लेकिन यदि तापमान दो डिग्री से ज्यादा होता है तो इनके पिघलने की दर 55 से अस्सी प्रतिशत तक रह सकती है। आसन्न संकट के मद्देनजर दुनिया के विकसित व विकासशील देशों को इसे खतरे की घंटी मानते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। अन्यथा करोड़ों लोगों का जीवन संकट में फंस जायेगा। इससे जहां इन देशों की खाद्य सुरक्षा तहस-नहस हो जाएगी, वहीं प्राकृतिक आपदा कई रूपों में कहर बरपाएगी। सिंचाई के संसाधन नष्ट होने से खाद्यान्न संकट गहरा जायेगा।

चमोली गढ़वाल इलाके में वर्ष 2021 में आई प्रलयंकारी बाढ़ के मूल में भी ग्लेशियर टूटने से आया सैलाब ही बताया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में कई जगह ग्लेशियर पिघलने से छोटी-छोटी झीलें बन गई हैं। इनमें पानी का लेवल बढ़ जाने से ये झीलें टूट जाती हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ जाती है। वर्ष 2013 की केदारनाथ दुर्घटना के मूल में भी ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ को बताया जाता रहा है।

चमोली जनपद के इस इलाके में एक हजार के लगभग ग्लेशियर हैं। तापमान बढ़ने से जब विशाल हिमखंड टूटते हैं तो भारी मात्रा में पानी निकलता है। हिमस्खलन के साथ चट्टानें व मिट्टी टूटकर नीचे आने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कई इलाकों में ग्लेशियरों के पीछे हटने से कुछ बर्फ ग्लेशियरों से अलग हो जाती है व फिर चट्टानों व कंकड़ों के मलबे को साथ लेकर नदियों में कहर बरपाती है। निस्संदेह, हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से बढ़ते तापमान के कारण पिघल रहे ग्लेशियरों को हमें एक बड़े संकट के रूप में देखना चाहिए। अन्यथा पिघलने से आने वाली बाढ़ इसके मार्ग में आने वाली बस्तियों, पुलों, हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट जैसे आधारभूत ढांचों को भी ध्वस्त कर सकती है।

बढ़ रही है तपिश, पर्यावरण संग सामंजस्य जरूरी

धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और आज संपूर्ण विश्व के साथ ही भारत भी बढ़ती तपिश का सामना कर रहा है। धरती का तापमान बढ़ने से धरती की पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं। तपिश इतनी बढ़ चुकी है कि मैदानी भागों में तो क्या पहाड़ों में भी आदमी तपिश व बढ़ती उमस को नहीं झेल पा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पर इससे पेयजल संकट गहरा गया है तो कहीं पर सूखे का खतरा तक मंडराने लगा है। हाल ही में उत्तराखंड के टनकपुर में पारा इकतालीस डिग्री को पार कर गया, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। बढ़ती गर्मी से आदमी तो आदमी जीव जंतुओं का हाल बहुत बुरा हो गया है। हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पेयजल संकट गहरा गया है और पांच योजनाओं में 30 प्रतिशत पानी कम होने पर विभाग को रोस्टर प्रणाली शुरू करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि मुख्यालय के बड़े कैचमेंट एरिया पर लगातार सूखे का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच यदि हम यहां मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान आजकल भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हाल ही में एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि गर्मी और लू से अकेले उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अस्पताल में 10 से 17 जून के बीच 121 मौतें हुई, जिनमें से 34 मौतें तो बाद के दो दिनों में हुई। दैनिक के हवाले से यह पता चला है कि तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और तमाम अस्पताल डायरिया व लू के मरीजों से भरे हुए हैं। प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक ने अपने संपादकीय में यह भी लिखा है कि बिहार के पटना में अत्यधिक गर्मी और लू से हुई मौतों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस कारण बिहार में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में पांचवीं तक के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने तापमान घटने की संभावना तो नहीं ही जताई है, उल्टे अगले पांच दिन तक विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तापमान और बढ़ने की बात कही है। धरती पर लगातार बढ़ती तपिश के परिणामस्वरूप पृथ्वी में लगातार बदलाव आ रहा है और इसके कारण ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। पर्वतों पर ग्लेशियर लगातार घट रहे हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्री स्तर बढ़ने से जनसमूहों का लगातार पलायन हो रहा है। जानकारी देना चाहूंगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंकाएं बढ़ जाती है। एक अत्यधिक गर्म जलवायु में, वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। वास्तव में, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल का क्रमिक ताप, मानव गतिविधियों के कारण होता है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में उत्सर्जित करता है। आज विश्व के विकसित देश लगातार बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो गई है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार घटक है। विकसित देश, विकासशील देशों को अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जबकि अधिकतम कार्बन का उत्सर्जन वे स्वयं करते हैं और वे इसके लिए विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहां जानकारी देना चाहूंगा कि करीब 200 देशों ने साल 2015 के पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 C या उससे कम तक सीमित करने का संकल्प लिया था, लेकिन ये देश अपने ही संकल्प को पूरा कर पाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रहे हैं। यहां यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि आज ग्लोबल वार्मिंग से भारत समेत पूरी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने के अलावा बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और कामकाज प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक, वर्ष 2000 से 2004 तक देश में लू और बढ़े तापमान के कारण सालाना औसतन 20,000 मौतें होती थी, पर वर्ष 2017 से 2021 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर सालाना 31,000 मौतों का हो गया। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस परिवर्तन(ग्लोबल वार्मिंग) के पीछे ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका है, जिन्हें सीएफसी या क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी कहते हैं।

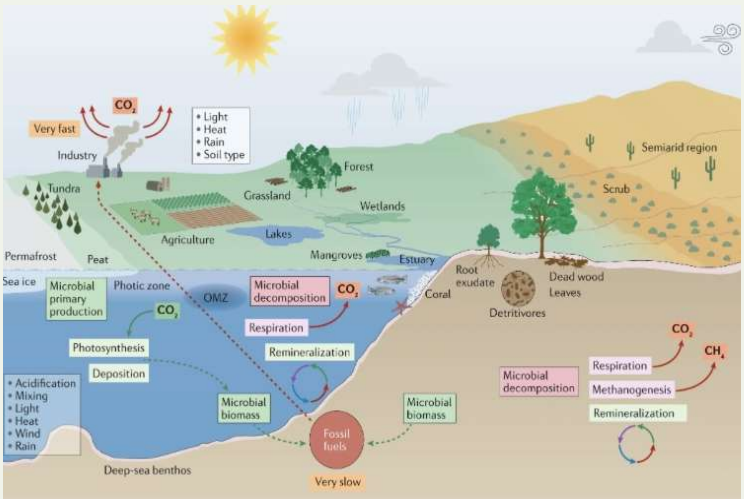

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गैसें वातावरण में बढ़ती जा रही हैं और इससे ओजोन परत की छेद का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समस्या है और इससे एकजुट होकर ही निपटा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए मुख्य रूप से सीएफसी गैसों का उत्सर्जन कम करने की जरूरत है और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे सीएफसी गैसें कम निकलती हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकले वाला धुआं हानिकारक हैं और इनसे निकलने वाला कार्बन डाई ऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। वास्तव में हमें इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुंए का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। इतना ही नहीं, हमें उद्योगों और ख़ासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश

करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। आज बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए कोयला जलाया जाता है, और कोयले से ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक होता है, इसलिए हमें अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाए तो धरती की आबोहवा को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया को आगाह किया था। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि अगले पांच सालों के भीतर ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक 1.5 C की सीमा को पार कर जाएगी। अल नीनो और मानव जनित जलवायु परिवर्तन से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा आएगी, इससे भारी मात्रा में विनाश देखने को मिल सकता है। यहां यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि अल नीनो तब होता है जब गर्म हवा आमतौर पर पानी को दक्षिण अमेरिका से एशिया तक प्रशांत महासागर के पार पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे अधिक गर्म पानी बना रहता है। यह दुनिया भर में जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र ने यहां तक कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अधिकतम तापमान में इस तरह की वृद्धि दर्ज होगी। यदि जिस तरह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसी तरह से उसका बढ़ना जारी रहता है तो इससे स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन और पर्यावरण पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। हालांकि,एक रिपोर्ट के मुताबिक अन्य देशों की तुलना में भारत में तापमान में कम इजाफा हुआ है। दुनिया में जहां 1.59 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है वहीं भारत में केवल 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके भारत को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ऊपर सुझाए गए सुझावों पर अमल करना होगा। कहना ग़लत नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य घटक मानव गतिविधियों को ही कहा जा सकता है, इसलिए हमें पर्यावरण के साथ तालमेल, सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना होगा।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार

करते हैं। आज प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि ये पदार्थ न तो गलता है और न ही नष्ट होता है। प्लास्टिक जल, भूमि,वायु सभी को किसी न किसी रूप में प्रदूषित करता है और नुकसान पहुंचता है। सच तो यह है कि प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफी कठिन होता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफी अहम योगदान है, जिससे यह भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। प्लास्टिक बैगों, बर्तनों और फर्नीचर के बढ़ते इस्तेमाल के वजह से प्लास्टिक के कचरे में काफी वृद्धि हुई है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। हमें यह चाहिए कि हम प्लास्टिक का या तो उपयोग करें ही नहीं और अन्य विकल्पों को अपनाएं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिये सबसे महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से ही बचना चाहिये। आज की भागमभाग की इस जिंदगी में हम इसके उपयोग के काफी हद तक आदि हो चुके है तथा यह काफी सस्ते भी है, इसलिये हम इनके उपयोग को पूरी तरह से बंद नही कर सकते हैं। हालांकि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को आसानी से बंद कर सकते है, जिनके इको-फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिये, बाजार से सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक बैग के जगह हम जूट, कपड़े या पेपर से बने बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पार्टियों और उत्सवों के दौरान हम प्लास्टिक के बर्तन और अन्य सामानों का उपयोग के जगह हम स्टील, कागज, थर्माकोल या अन्य उत्पादों से वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जिनका आसानी से पुनरुपयोग और निस्तारण किया जा सके। यदि हम प्लास्टिक बैगों, थैलियों और प्लास्टिक से बनी अन्य वस्तुओं का उपयोग बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हे फेंकने से पहले जितनी बार भी हो सके उनका कम से कम उनका पुनरुपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक को खुले में जलाना कभी भी नहीं चाहिए, क्यों कि इसे जलाना तो और भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। जानकारी देना चाहूंगा कि प्लास्टिक को जलाने से वातावरण तो दूषित होता ही है, इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक को न तो खुले में फेंकना चाहिए और न ही जलाना चाहिए। इसे जितना हो सके रिसाइकल किया जाना चाहिए। जानकारी देना चाहूंगा कि हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे ही बिना उपचार के वातावरण में छोड़ा जा रहा है जो हवा, पानी और फसलों के जरिए लौटकर वापस हमारे पास ही आ रहा है। हाल ही में प्रकाशित शोधों से पता चला है कि प्लास्टिक के यह कण न केवल इंसानी फेफड़ों बल्कि उसके रक्त में भी मिले हैं।

आज शहरों में नगर निगम,नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतों का कूड़ा सड़क पर या शहर के बाहर कहीं पर भी डाल दिया

जाता है। अमूमन देखा जाता है कि सफाई कर्मचारी इस कूड़े में अक्सर आग लगा देते हैं। आग लगने से कूड़े से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। कूड़े में सबसे ज्यादा पॉलिथीन ही जलती है।आज के समय में यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विज्ञान कहता है कि प्लास्टिक एक प्रकार का पॉलीमर यानी मोनोमर नाम की दोहराई जाने वाली इकाइयों से युक्त बड़ा अणु है। प्लास्टिक थैलों के मामले में दोहराई जाने वाली इकाइयां एथिलीन की होती हैं। जब एथिलीन के अणु को पॉली एथिलीन बनाने के लिए पॉलीमराइज किया जाता है तो कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला बनाती है। इसमें प्रत्येक कार्बन को हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोजित किया जाता है। बहरहाल, आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रुप में 5,000 अरब टुकड़े तैर रहे हैं। अधिक वक्त बीतने के बाद यह टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो गए हैं। जीव विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर तैरने वाला यह भाग कुल प्लास्टिक का सिर्फ एक फीसदी है, जबकि 99 फीसदी समुद्री जीवों के पेट में है या फिर समुद्र तल में छुपा है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगी।

प्लास्टिक के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि हर साल दुनियाभर में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण इसका निपटारा कर पाना गंभीर चुनौती है। प्लास्टिक 500 से 700 साल बाद नष्ट होना शुरू होता है और पूरी तरह से डिग्रेड होने में उसे 1000 साल लग जाते हैं। यहां यह भी जानकारी देता चलूं कि प्लास्टिक छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता है पर नष्ट नहीं होता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। दुनियाभर में केवल 1 से 3% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है। यहां यदि हम भारत की बात करें तो देश में हर साल तकरीबन 56 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 9205 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग में लाया जाता है। जानकारी मिलती है कि भारत में सबसे ज्यादा 24 फीसदी प्लास्टिक का उपयोग पैकिंग के लिए, कृषि कार्य के लिए 23 फीसदी, घरेलू उपयोग वाली सामग्री में 10 फीसदी उपयोग है। भारत में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार हर साल 3.4 मिलियन प्लास्टिक कचड़े का उत्पादन होता है।

डाउन टू अर्थ में छपे एक आर्टिकल के अनुसार 2019 में जहां 7.9 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा ऐसे ही वातावरण में डंप किया जा रहा था, उसका आंकड़ा 2060 में बढ़कर 15.3 करोड़ पर पहुंच जाएगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1950 के बाद से अब तक करीब 830 करोड़ टन प्लास्टिक उत्पादित किया जा चुका है जिनमें से 60 फीसदी को ऐसे ही या तो लैंडफिल में डंप कर दिया गया है, या फिर वातावरण में छोड़ दिया गया है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हर मिनट कूड़े से भरे एक ट्रक के बराबर प्लास्टिक समुद्र के पानी में मिल रहा है। पिछले कुछ दशक में दुनियाभर में प्लास्टिक का इतना उत्पादन किया गया था, जितना पिछली पूरी शताब्दी में नहीं हुआ था। यूएन एनवायरमेंट के मुताबिक हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल में लाते हैं उसका 50 फीसदी सिंगल-यूज या डिस्पोजेबल होता है। हर मिनट दुनिया में करीब 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स खरीदे जाते हैं। दुनियाभर में जो भी कूड़ा-कचरा पैदा होता है, उसका 10 से 20 फीसदी हिस्सा प्लास्टिक का ही होता है।डाउन टू अर्थ में छपे एक आर्टिकल से पता चलता है कि प्लास्टिक की खपत पिछले कुछ समय में बहुत अधिक हो गई है।प्लास्टिक की खपत कितनी विशाल है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां वर्ष 2019 में हर साल करीब 46 करोड़ टन प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा था वो वर्ष 2060 तक बढ़कर 123 करोड़ टन प्रति वर्ष से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में यह बहुत ही जरूरी है कि दुनिया के सभी देश इस समस्या की गंभीरता को समझें और इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाएं। प्लास्टिक पर नियंत्रण अकेले किसी व्यक्ति विशेष का विषय ही नहीं है, अपितु यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वास्तव में सरकार या प्रशासन या व्यक्ति विशेष अकेले अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती है। वास्तव में, हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक से निपटने के यथेष्ठ व नायाब प्रयास करने होंगे।

बढ़ते प्लास्टिक उपयोग को कम करना हमारी भी जिम्मेवारी है। इसके लिए हमें जरुरत से ज्यादा प्लास्टिक उत्पादों की खरीदारी से बचना चाहिए और उससे जुड़े कचरे को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक व पॉलीथिन को फेंकने से पहले हमें सौ बार यह सोचना चाहिए कि इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच सकता है। हमें इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि खतरा इन उत्पादों से ज्यादा हमारी जीवन शैली से है जो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की बर्बादी की राह पर जा रही है। अगले लगभग चालीस सालों में प्लास्टिक का उपयोग तीन गुना तक बढ़ने की प्रबल संभावना है इसलिए हमें धरती पर जीवन को बचाना है तो हमें प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना होगा और इसके बढ़ते उपयोग को रोकना होगा। लोगों को हमें जागरूक करना होगा। ■

कैसे रुके डॉक्टरों का ब्रेन ड्रेन ?

भारत से डॉक्टरों का ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन इस मायने में महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है कि देश को चिकित्सकों की आज भी बेहद कमी का सामना करना पड़ रहा है।भारत को ग्रेनाडा से सबक़ लेना चाहिए। सबसे अधिक डॉक्टरों के ब्रेन ड्रेन वाले देश ग्रेनाडा के दस हजार डॉक्टरों के विदेशों में पलायन और कोरोना महामारी के प्रकोप ने जब उस देश को हिला कर रख दिया तो ग्रेनाडा को अपने चिकित्सकों को विदेशों से वापस बुलाने तक का निर्णय करना पड़ा।

भारत के भी करीब 75 हजार डॉक्टर्स ओईसीडी यानी कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन से जुड़े देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े दिल्ली के एम्स है जहां पिछले दस माह में 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किसी ना किसी कारण से सेवाएं देना बंद कर दिया है। आज दस हजार से अधिक लोगों को प्रतिदिन सेवाएं देने वाले एम्स में ही 200 डॉक्टर्स की कमी चल रही है। यह तो एक मिसाल मात्र है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे चिकित्सक अपनी काबिलियत और विशेषज्ञता के कारण ही विदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और एक मोटे अनुमान के अनुसार ओईसीडी देशों में रह रहे 75 हजार डॉक्टरों में से करीब दो तिहाई डॉक्टर्स तो अमेरिका में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

दूसरी तरफ़ सरकारी व गैरसरकारी प्रयासों से अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेट आदि की जरूरत को पूरा करने के प्रयास कि हुए पर आज भी प्रशिक्षित मैनपावर की कमी के कारण इन उपकरणों का सही उपयोग नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा। यदि हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करें तो देश में शहरी क्षेत्र में तो कमी है ही पर ग्रामीण क्षेत्र के हालात अधिक चिंताजनक हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 की मानें तो देश में ग्रामीण इलाकों की डिस्पेंसरियों में 81.6 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। सामान्य फिजिशियनों की ही बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की डिस्पेंसरियों में 79 प्रतिशत फिजिशियनों की कमी है। 72 प्रतिशत से कुछ अधिक कमी प्रसूति रोग विशेषज्ञों की है। यह तो सरकारी आंकड़ों में दर्शाये गये हालात हैं। हालांकि नवीनतम रिपोर्ट में हालात में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं पर अधिक सुधार की आशा करना बेमानी होगा। दरअसल

हमारे यहां दस हजार की आबादी पर केवल 7 डॉक्टर उपलब्ध हैं जबकि क्यूबा जैसा देश दुनिया के देशों में मेडिकल चिकित्सकीय सेवा में लीड कर रहा है और वहां दस हजार की आबादी पर 84 डॉक्टर उपलब्ध हैं, अमेरिका में यह संख्या 35 तो चीन में 23 है।

ब्रेन ड्रेन शब्द सबसे पहली बार विश्वयुद्ध के समय उभर कर आया जब भारतीय इंजीनियर व अन्य विशेषज्ञ अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने विदेशों में जाने लगे और वहां अपनी पहचान बनाई। 1950 से 1960 के दशक में यूके, कनाडा और यूएसए में प्रतिभा पलायन का दौर चला और इसे ब्रिटिश रॉयल सोसायटी ने ब्रेन ड्रेन कहा तो अब विदेशों में प्रतिभा पलायन चाहे वह किसी भी देश की हो उसे ब्रेन ड्रेन के नाम से पुकारा जाने लगा है। ब्रेन ड्रेन को एक तरह से अच्छा भी माना जा सकता है क्योंकि हमारी प्रतिभा को वहां स्थान मिल रहा हैं पर जब तक घर के हालात तंदुरुस्त नहीं हों तब तक इसे ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैसे भी हमारे यहां से ही नहीं अपितु दुनिया के लगभग अधिकांश देशों से प्रतिभाएं किसी ना किसी कारण से पलायन करती हैं। विदेशों में प्रतिभा पलायन को ही ब्रेन ड्रेन कहा जाने लगा है।

अब ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कह कर भी पुकारा जाने लगा है तो दूसरी और रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होने लगा है। सवाल यह है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और डॉक्टरों की जरूरतों को देश में पूरा करना समय की मांग है। आज हम देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके बादजूद ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खासतौर से चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लाख सरकारी दावों के बावजूद अन्य देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी की तुलना में हमारे देश में 3 प्रतिशत से कुछ अधिक ही खर्च किया जा रहा है जबकि यूएसए में जीडीपी का स्वास्थ्य पर खर्च 18 प्रतिशत से भी अधिक है तो क्यूबा में 11 प्रतिशत और जापान में 10 से अधिक ही व्यय किया जा रहा है।

चिकित्सकों के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भी सरकार को ठोस प्रयास करने होंगे। डॉक्टर्स की सेवा शर्तों में सुधार के साथ ही इस क्षेत्र में निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होगा। आज भी चिकित्सा क्षेत्र में निवेश की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वह यही है कि करीब 90 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र में आ रहा है। लाख टके का सवाल है कि लाख सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद निजी चिकित्सालयों तक अधिकांश लोगों की पहुंच लगभग नहीं के बराबर ही है और आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव होगा यह लगता भी नहीं है। ■

अमृतकाल में भारतीय आर्थिक दर्शन के सहारे आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था

● **प्रहलाद सबनानी**

श्री एंगस मेडिसन दुनिया के जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री इतिहासकार रहे हैं। आपने विश्व के कई देशों के आर्थिक इतिहास पर गहरा अनुसंधान कार्य किया है। भारत के संदर्भ में आपका कहना है कि एक ईस्वी के पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत में अतुलनीय आर्थिक प्रगति, भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार चलायी जा रही आर्थिक नीतियों के चलते ही सम्भव हो सकी थी। भारत में पिछले 9 वर्षों के दौरान भारतीय आर्थिक दर्शन के सहारे किए गए कई आर्थिक निर्णयों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन पुनः अब तेज गति से पटरी पर दौड़ने लगा है। लगभग समस्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी लगातार बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भारत में आर्थिक विकास की दर पूरे विश्व में सबसे अधिक रहने वाली है एवं आर्थिक क्षेत्र में केवल वर्तमान दशक ही नहीं बल्कि वर्तमान सदी ही भारत की रहने वाली है।

भारत में 60, 70 एवं 80 के दशकों में हम लगभग समस्त नागरिक हमारे बचपन काल से ही सुनते आए हैं कि भारत एक गरीब देश है एवं भारतीय नागरिक अति गरीब हैं। हालांकि भारत का प्राचीनकाल बहुत उज्जवल रहा है, परंतु आक्रांताओं एवं ब्रिटेन ने अपने शासन काल में भारत को लूटकर एक गरीब देश बना दिया था। अब समय का चक्र पूर्णतः घूमते हुए आज के खंडकाल पर आकर खड़ा हो गया है एवं भारत पूरे विश्व को कई मामलों में अपना नेतृत्व प्रदान करता दिखाई दे रहा है। साथ ही, भारत में विशेष रूप से कोरोना महामारी के बीच एवं इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सनातन भारतीय संस्कारों का पालन करते हुए गरीब वर्ग के लाभार्थ चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज की जो सुविधा प्रदान की गई है एवं इसे कोरोना महामारी के बाद भी जारी रखा गया है, इसके परिणामस्वरूप देश में गरीब वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में गरीबी के अनुमान पर एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इस वर्किंग पेपर में अलग अलग मान्यताओं के आधार पर भारत में गरीबी को लेकर अनुमान व्यक्त किए गए हैं। इस वर्किंग पेपर के अनुसार, हाल ही के समय में भारत में 1.2 करोड़ नागरिक अतिगरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। वर्ष 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2011 में भारत में 22.5 प्रतिशत नागरिक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थे परंतु वर्ष 2019 में यह प्रतिशत घटकर 10.2 रह गया है। वर्ष 2016 में भारत में अतिगरीब वर्ग की आबादी 12.4 करोड़ थी जो वर्ष 2022 में घटकर 1.5 करोड़ रह गई है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत में 40 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। दरअसल पिछले लगभग 9 वर्षों के दौरान भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जिसके चलते भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है और भारत को गरीबी उन्मूलन के मामले में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

भारत में अतिगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों नागरिकों का इतने कम समय में गरीबी रेखा के ऊपर आना विश्व के अन्य देशों के लिए एक सबक है। इतने कम समय में किसी भी देश में इतनी तादाद में लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाए हैं ऐसा कहीं नहीं हुआ है। भारत में गरीबी का जो बदलाव आया है वह धरातल पर दिखाई देता है। इससे पूरे विश्व में भारत की छवि बदल गई है।

यह भी सनातनी संस्कार ही हैं जो भारत के नागरिकों को छोटी छोटी बचतें करना सिखाते हैं। भारतीय परम्पराओं के अनुसार हमारे बुजुर्ग हममें बचत की प्रवृत्ति बचपन में ही यह कहकर विकसित करते हैं कि भविष्य में आड़े अथवा बुरे वक्त के दौर में, पुराने समय में की गई बचत का बहुत बड़ा सहारा मिलता है। भारतीय परिवारों में तो गृहणियां घर खर्च के लिए उन्हें प्रदान की गई राशि में से भी बहुत छोटी राशि की बचतें करने का गणित जानती हैं एवं वक्त आने पर अपने परिवार के सदस्यों को उक्त बचत की राशि सौंप कर संतोष का भाव जागृत करती हैं। जबकि अन्य देशों के नागरिकों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, बचत की आदत नहीं के बराबर होती है। पश्चिमी दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हैं अतः पश्चिमी देशों के नागरिक अपने जीवन को आज ही जी लेना चाहते हैं, कल (भविष्य) पर अधिक भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए, पश्चिमी देशों के नागरिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपभोग करते हैं एवं अपनी लगभग पूरी आय ही उपभोग पर खत्म कर देते हैं, बचत करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस करते हैं। इसके विपरीत भारतीय दर्शन आध्यात्म पर आधारित है एवं जीवन में अच्छे कर्मों को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। अतः इस लोक एवं परलोक को सुधारने के लिए समाज के गरीब वर्ग की सहायता करने की प्रवृत्ति भारतीय नागरिकों में पाई जाती है। भारतीय नागरिक इसलिए छोटी से छोटी बचतों पर भी बहुत भरोसा करते हैं। इसी कड़ी में, वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने भारत में गरीब वर्ग के नागरिकों को बैंकों से जोड़ने के लिए जनधन योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 50 करोड़ बचत खाते विभिन्न बैंकों में खोले जा चुके हैं एवं छोटी छोटी बचतों को जोड़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से

रक्षा क्षेत्र में बढ़ता उत्पादन भारत को बनाएगा 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था

भारत कुछ समय पूर्व तक रक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः आयातित उत्पादों पर ही निर्भर रहता था। छोटे से छोटा उत्पाद भी विकसित देशों से आयात किया जाता रहा है। परंतु, हाल ही के समय में भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक जानकारी के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का उत्पादन 1.07 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों के उत्पादन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह राशि 1200 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का उत्पादन 95,000 करोड़ रुपये का रहा था। इस प्रकार, भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

अभी हाल ही में रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक सूची जारी की है, इस सूची में दिए गए समस्त उत्पादों का निर्माण अब पूर्णतः भारत में ही किया जाएगा एवं आगामी वर्षों में इन उत्पादों का आयात पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में इन उत्पादों पर 715 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उक्त सूची में वर्णित उत्पादों को भारत में ही निर्माण की मंजूरी भी दे दी गई है। इस प्रकार की तीन सूचियां पूर्व में भी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार के इस क्रांतिकारी निर्णय से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का निर्माण अब भारत में ही होने लगा है एवं पूर्व में इन उत्पादों के आयात पर भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च की जाती थी, अब उस विदेशी मुद्रा की भी देश को बचत हो रही है।

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों का आयात लगातार कम करते हुए अब कई रक्षा उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ कर दिया है। अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी निर्मित तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद बनाकर उभरा है। मलेशिया ने अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। जिसमें चीन के जेएफ-17, दक्षिण कोरिया के एफए-50 और रूस के मिग-35 के साथ साथ याक-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान तेजस को पसंद किया है। आकाश मिसाइल भी भारत की पहचान है एवं यह एक स्वदेशी (96 प्रतिशत) मिसाइल है। दक्षिणपूर्व एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, और फिलिपींस के अलावा बहरीन, केन्या, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने आकाश मिसाइल को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल के साथ ही कई अन्य देशों ने तटीय निगरानी प्रणाली, राडार और एयर प्लेटफार्मों को खरीदने में भी अपनी रुचि दिखाई है। भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों यथा फिलीपींस, वियतनाम एवं इंडोनेशिया आदि को ब्रह्मोस मिसाइल भी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। कुछ अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका आदि ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आज भारत से 84 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। इस सूची में कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश भी शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण, आदि निर्यात किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कुल बजट की राशि का 8 प्रतिशत है। बजट में आवंटित की गई इस राशि का उपयोग हथियारों की आत्मनिर्भर तकनीक और भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के कार्य पर किया जाएगा। इससे देश में ही रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंगे।

चूंकि भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को भारत में ही निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा रक्षा उत्पादों का भारत में ही निर्माण एवं भारत से निर्यात जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है इससे अब यह आभास होने लगा है कि वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में, आगे आने वाले समय में, देश का रक्षा क्षेत्र भी प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। वर्ष 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

- प्रह्लाद सबनानी

अधिक की राशि इन खातों में जमा की जा चुकी है। भारत ने इस संदर्भ में पूरे विश्व को ही राह दिखाई है। यह बचत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को कल का मध्यम वर्ग बनाएगी, इससे देश में विभिन्न उत्पादों का उपभोग बढ़ेगा तथा देश की आर्थिक उन्नति की गति भी तेज होगी। यह भारतीय सनातन संस्कारों के चलते ही सम्भव हो पाया है। भारत में परिवार अपने खर्चों को संतुलित करते हुए भविष्य के लिए बचत आवश्यक समझते हैं।

एक और क्षेत्र जिसमें भारतीय दर्शन ने पूरे विश्व को राह दिखाई है, वह है मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना। दरअसल, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए विकसित देशों द्वारा ब्याज दरों में लगातार वृद्धि करते जाना, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को विपरीत रूप से प्रभावित करता नजर आ रहा है, जबकि इससे मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा

भारत में किसानों की आय हो रही है दोगुनी

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है एवं इसमें से बहुत बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यदि ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिकों की आय में वृद्धि होने लगे तो भारत के आर्थिक विकास की दर को चार चांद लगाते हुए इसे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से भी अधिक किया जा सकता है। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार लगातार यह प्रयास करती रही है किसानों की आय को किस प्रकार दुगुना किया जाय। इस संदर्भ में कई नीतियों एवं सुधार कार्यक्रम लागू करते हुए किसानों की आय को दुगुना किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अप्रेल 2016 में इस सम्बंध में एक मंत्रालय समिति का गठन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया था एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सात स्त्रोतों की पहचान की गई थी, इनमे शामिल हैं, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना, संसाधन के उपयोग में दक्षता हासिल करते हुए कृषि गतिविधियों की उत्पादन लागत में कमी करना, फसल की सघनता में वृद्धि करना, किसान को उच्च मूल्य वाली खेती के लिए प्रोत्साहित करना (खेती का वीविधीकरण), किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना एवं अधिशेष श्रमबल को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाना। उक्त सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के अब सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं एवं कई प्रदेशों में किसानों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है, किसानों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है एवं कुल मिलाकर अब देश के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

प्राचीन भारत में तो सनातन संस्कृति का पालन करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में गाय पालन की गतिविधियां बहुत बड़े स्तर पर चलाई जाती थी। उस खंडकाल में गाय पालन से दरअसल बहुत अधिक आर्थिक लाभ होता था। गाय के गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता था, गाय के दूध से डेयरी उत्पादों का निर्माण कर बाजार में बेचा जाता था, गौ मूत्र का दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, आदि। ग्रामीण इलाकों में किसी भी परिवार की सम्पन्नता इस बात से आंकी जाती थी कि किस परिवार में गाय की संख्या कितनी है। कृषि कार्य के अतिरिक्त लगभग समस्त परिवार गाय पालन की गतिविधि में भी संलग्न रहते थे एवं इससे यह उनकी आय का एक अतिरिक्त साधन बन जाता था। इसी तर्ज पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए पशुपालन की गतिविधि को एक अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया है।

पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए बजट आबंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वर्ष 2015-16 में कृषि बजट के लिए 25,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 138,551 करोड़ रुपए का हो गया है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष रुपए 6000 की राशि, तीन समान किश्तों में, पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ही केंद्र सरकार द्वारा जमा कर दी जाती है। इस राशि का उपयोग पात्र किसान कृषि कार्य सम्पन्न करने के लिए खाद, बीज आदि खरीदते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अभी तक 11.3 करोड़ पात्र किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है।

देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों के बीच किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा प्रभावित किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे भारतीय किसानों का आत्म विश्वास बढ़ा है। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण के लक्ष्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पशु पालन और मत्स्य पालन के लिए प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे इन गतिविधियों में किसानों की लाभप्रदता बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से समस्त प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। विभिन्न उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के डेढ़ गुने तक तय किया जा रहा है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके कारण कीटनाशक दवाओं एवं उर्वरकों का कम इस्तेमाल होने लगा है एवं इससे किसानों के लिए कृषि पदार्थों की उत्पादन लागत कम हो रही है।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) की स्थापना भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिला है। कृषि उपज लाजिस्टिकस में सुधार करते हुए किसान रेल की शुरुआत भी की गई है। इस विशेष सुविधा से विशेष रूप से फल एवं सब्जी जैसे पदार्थों के नष्ट होने की सम्भावनाएं कम हो गई हैं। देश में कृषि और सम्बंध क्षेत्र में स्टार्ट अप ईको सिस्टम का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर अब किसान की आय बढ़ाने हेतु नीतियों का निर्माण किया जा रहा है।

किसानों को 'प्रति बूंद अधिक फसल' के सिद्धांत का पालन करते हुए, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इस सम्बंध में सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन भी किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसलों को उचित दामों पर बाजार में बेच सकें एवं इस संदर्भ में बाजार में प्रतियोगी बन सकें। कृषि क्षेत्र के यंत्रीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेत के मिट्टी की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसान इस मिट्टी में उसी फसल को उगाए जिसकी उत्पादकता अधिक आने की सम्भावना हो।

भारत में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि के चलते अब भारत के किसान विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगे हैं। भारतीय कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही मांग के चलते अब किसानों को इन उत्पादों के निर्यात से अच्छी आय होने लगी है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के देश से निर्यात सम्बंधी नियमों को आसान किया है।

केंद्र सरकार द्वारा किए गए उक्त वर्णित कई उपायों के चलते फसलों और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, संसाधनों के उपयोग में दक्षता आने से उत्पादन लागत में कमी आई है, फसल की सघनता में वृद्धि दर्ज हुई है, उच्च मूल्य वाली खेती की ओर विविधिकरण हुआ है, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है एवं अतिरिक्त श्रमबल को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाया गया है। इस सबका मिलाजुला परिणाम यह हुआ है कि किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों की आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

- प्रहलाद सबनानी

है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अब पुराने सिद्धांत बोथरे साबित हो रहे हैं। और फिर, केवल मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में लगातार वृद्धि करते जाना ताकि बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो, एक नकारात्मक निर्णय है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्पादों की मांग कम होने से, कम्पनियों का उत्पादन कम होता है, देश में मंदी फैलने की सम्भावना बढ़ने लगती है, इससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा पैदा होने लगता है, सामान्य नागरिकों की ईएमआई में वृद्धि होने लगती है, आदि। अमेरिका में कई कम्पनियों ने इस माहौल में अपनी लाभप्रदता बनाए रखने के लिए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। किसी नागरिक को बेरोजगार कर देना एक अमानवीय कृत्य ही कहा जाएगा। और फिर, अमेरिका में ही इसी माहौल के बीच तीन बड़े बैंक फैल हो गए हैं। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां अन्य देशों में भी फैलती हैं तो पूरे विश्व में ही मंदी की स्थिति छा सकती है। पश्चिम की उक्त व्यवस्था के ठीक विपरीत, भारतीय आर्थिक चिंतन में विपुलता की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा गया है, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन करो – 'शतहस्त समाहर, सहस्त्रहस्त संकिर' (सौ हाथों से संग्रह करके हजार हाथों से बांट दो) – यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। विपुलता की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक नागरिकों को उपभोग्य वस्तुएं आसानी से उचित मूल्य पर प्राप्त होती रहती हैं, इससे उत्पादों के बाजार भाव बढ़ने के स्थान पर घटते रहते हैं। भारतीय वैदिक अर्थव्यवस्था में उत्पादों के बाजार भाव लगातार कम होने की व्यवस्था है एवं मुद्रा स्फीति के बारे में तो भारतीय शास्त्रों में शायद कहीं कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है। भारतीय आर्थिक चिंतन व्यक्तिगत लाभ केंद्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर मानवमात्र के लाभ को केंद्र में रखकर चलने वाली अर्थव्यवस्था को तरजीह देता है।

आज विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों में भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या प्रभावशाली स्तर पर पहुंच गई है एवं भारतीय मूल के नागरिक इन देशों, विकसित देशों सहित, की अर्थव्यवस्थाओं में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हुए अपने लिए भी उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर रहे हैं। जब अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की उल्लेखनीय सफलता के पीछे कारण खोजने का प्रयास किया गया तो निम्नलिखित कारण ध्यान में आए हैं।

भारतीय संस्कारों के अनुसार, भारतीय माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने हितों का त्याग करते पाए जाते हैं। भारतीय माताएं अपने व्यावसायिक कार्य के प्रति जुनून को अपने बच्चों के हित में त्याग देती हैं। इसी प्रकार, भारतीय पिता अपने व्यवसाय में अपने बच्चों के हित में कई प्रकार के समझौते करते हैं। अत: भारतीय माता पिता के लिय अपने बच्चों का लालन पालन सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। भारतीय माता पिता अपने जीवन के व्यस्ततम पलों में भी सबसे उत्कृष्ट समय अपने बच्चों के विकास पर खर्च करते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों द्वारा अपने बच्चों को अमरीका में अभी भी भारतीय संस्कारों के अनुसार ही पाला पोसा जाता है।

भारतीय माता पिता अपने बच्चों में बचपन में ही विश्वास का भाव जगाते हैं। वे स्वयं भी अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं एवं उन्हें भी समाज के अन्य वर्गों के प्रति विश्वास करना सिखाते हैं। बच्चों में विकसित किए गए इस विश्वास के चलते माता पिता अपने बच्चों के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं एवं बच्चे अपने माता पिता के साथ अपने जीवन की समस्त बातों को साझा करने में डरते नहीं हैं।

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिका में भी संयुक्त परिवार के रूप में एक ही मकान में रहते हैं। इससे इनके पारिवारिक व्यवसाय को विकसित करने एवं तेजी से तरक्की करने में बहुत आसानी होती है। साथ ही, संयुक्त परिवार के रूप में रहने से तुलनात्मक रूप से पारिवारिक खर्चे भी कम होते हैं।

अमेरिका में वैवाहिक जीवन के मामले में भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बहुत संतुष्ट एवं सुखी पाए जाते है। इसे शादी के बाद दिए जाने वाले तलाक सम्बंधी आंकड़ों के माध्यम से आंका गया है। अमेरिका में सबसे अधिक तलाक की दर अमेरिकी काले नागरिकों के बीच 28.8 प्रतिशत है, अमेरिकी गोरे नागरिकों के बीच यह 15.1 प्रतिशत है, परंतु भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के बीच यह केवल 1.3 प्रतिशत है (हालांकि कुछ सूर्वे में यह 6 प्रतिशत भी आंकी गई है), जो कि समस्त अन्य देशों के नागरिकों के बीच सबसे कम दर है। यह भारतीय संस्कारों का ही परिणाम है।

भारतीय माता पिता अपने बच्चों को भारतीय सामाजिक मान्यताओं से बचपन में ही परिचित कराते है एवं वे अपने बच्चों को अपने नाते रिश्तेदारों एवं जान पहिचान के परिवारों में विभिन्न आयोजनों में भाग लेना सिखाते हैं एवं इनसे सम्बंध स्थापित करना सिखाते हैं। वे अपने बच्चों को, इनकी शादी हो जाने तक, अपने पास ही रखते हैं, बहुत से भारतीय परिवार

भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ तो हुई है परंतु अभी भी सतर्कता जरूरी

आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र की 11 बैंकों को, इन बैंकों में खराब कर्ज के खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के कारण, त्वरित सुधारात्मक ढांचे के तहत रखा था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कम पूंजी आधार, गैर-पेशेवर प्रबंधन, हताश कर्मचारियों और भारी अक्षमताओं सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। परंतु, केंद्र सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कई उपाय किये एवं केंद्र सरकार ने पांच वित्त वर्षों के दौरान (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 3,10,997 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश किया। इससे इन बैंकों को आवश्यक मदद मिली और उनकी ओर से किसी भी चूक की आशंका खत्म हो गई। अभी हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया गया है। इस प्रतिवेदन में भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बताया गया है एवं इस प्रतिवेदन के अनुसार दिसम्बर 2022 को समाप्त अवधि में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.1 प्रतिशत, सकल गैरनिष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत 4.41 प्रतिशत एवं प्रोविजन कवरेज अनुपात 73.20 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जहां 85,390 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्शाया था, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन बैंकों ने 66,539 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में सरकारी क्षेत्र की बैंकों का लाभ एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का तो एक तरह से कायाकल्प ही हो गया है।

बैंकिंग उद्योग किसी भी देश में अर्थ जगत की रीढ़ माना जाता है। बैंकिंग उद्योग में आ रही परेशानियों का निदान यदि समय पर नहीं किया जाता है तो आगे चलकर यह समस्या उस देश के अन्य उद्योगों को प्रभावित कर, उस देश के आर्थिक विकास की गति को कम कर सकती है। इसलिए पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने बैंकों की लगभग हर तरह की समस्याओं के समाधान हेतु कई ईमानदार प्रयास किए हैं। गैरनिष्पादनकारी आस्तियों से निपटने के लिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता लागू की गई है। देश में सही ब्याज दरों को लागू करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति बनायी गई है। साथ ही, दिनांक 30 अगस्त 2019 को देश की वित्त मंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाए जाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की थी। सरकारी क्षेत्र के बैकों की, समेकन के माध्यम से, क्षमता अनवरोधित (अनलाक) करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इन बैंकों के विलय में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि इनके विलय से किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये तकनीक के लिहाज से एक ही प्लेटफार्म पर हों, इन बैंकों की संस्कृति एक ही हो तथा इन बैंकों के व्यवसाय में वृद्धि दृष्टिगोचर हो। वर्ष 2017 में भारत में सरकारी क्षेत्र के 27 बैंक थे लेकिन इनके आपस में विलय के बाद अब केवल 12 सरकारी क्षेत्र के बैंक रह जाएंगे। इस प्रकार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अगली पीढ़ी के बैंकों का रूप दिया जा रहा है। उक्त विलय के बाद इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बड़े हुए आकार ने इन बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में अभितपूर्व वृद्धि की है। इन बैंकों की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति के साथ ही इनकी अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच बन गई है। विलय के बाद इन बैंकों की परिचालन लागत में कमी आई है जिससे इनके द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों की लागत में भी सुधार हुआ है। इन बैंकों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय हेतु, नई तकनीकी के अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिससे इनकी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होता दिखाई दे रहा है। इन बैंकों की बाजार से संसाधनों को जुटाने की क्षमता में भी सुधार हुआ है।

केंद्र सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त प्रयासों से भारत में समस्त वर्गीकृत वाणिज्यिक बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि में 16.7 प्रतिशत के सराहनीय स्तर पर पहुंच गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडो के अनुसार, बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम 8 प्रतिशत (एवं 2.5 प्रतिशत के पूंजी कंजर्वेटिव बफर को मिलाकर 10.5 प्रतिशत) होना बैंकों के लिए आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार, भारत में वर्गीकृत वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों पर आय एवं इक्विटी पर आय भी इस अवधि में संतोषप्रद रही है, जिसके चलते पूंजी पर्याप्तता अनुपात में भी लगातार सुधार हो रहा है, जो मार्च 2020 में 14.7 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर 2020 में 15.8 प्रतिशत हो गया एवं मार्च 2021 में 16 प्रतिशत होकर मार्च 2022 में 16.7 प्रतिशत हो गया है।

वर्गीकृत वाणिज्यिक बैंकों में सकल गैरनिष्पादनकारी आस्तियों एवं शुद्ध गैरनिष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत भी 30 सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही में कम होकर 5.0 प्रतिशत (पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर) एवं 1.3 प्रतिशत (पिछले 10 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर) क्रमशः हो गया है। सकल गैरनिष्पादनकारी आस्तियां मार्च 2020 में 8.4 प्रतिशत, मार्च 2021 में 7.3 प्रतिशत एवं मार्च 2022 में 5.9 प्रतिशत रही हैं। साथ ही, शुद्ध गैरनिष्पादनकारी आस्तियां मार्च 2020 में 3.0 प्रतिशत, मार्च 2021 में 2.4 प्रतिशत एवं मार्च 2022 में 1.7 प्रतिशत की रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रभावित हुए ऋण खातेदारों को उनके द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज एवं किश्त की अदायगी में छूट प्रदान की थी, जिसके कारण भी गैर निष्पादनकारी आस्तियों में कमी दृष्टिगोचर हुई है। परंतु उक्त बैंकों के प्रोविजन कवरेज अनुपात में सुधार हुआ है और यह मार्च 2021 के 67.6 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 70.9 प्रतिशत हो गया है। इसका आशय यह है कि इन बैंकों ने अपने खातों में गैरनिष्पादनकारी आस्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोविजन कर लिया है। यदि आगे आने वाले समय में इन गैरनिष्पादनकारी आस्तियों में समस्या होती है तो बैंकों को इस प्रकार की समस्या से निपटने में आसानी होगी।

अभी हाल ही में किए गए एक आंकलन के अनुसार अमेरिका के 160 बड़े बैंकों (जिनके पास 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि की आस्तियां हैं) को 20,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका की रेटिंग संस्थाओं स्टैंडर्ड एंड पूअर्स एवं फिच ने कुछ बैंकों की रेटिंग घटाकर जंक श्रेणी में डाल दी है क्योंकि यह बैंक अपने जमाकर्ताओं को राशि वापिस करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों को भी भारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनके अमेरिकी बांड्ज में किए गए निवेश की बाजार कीमत कम हो गई है। सिटी बैंक समूह को 4,700 करोड़ अमेरिकी

डॉलर, बैंक आफ अमेरिका को 2,120 करोड़ अमेरिकी डॉलर, जे पी मोर्गन चेज को 1,730 करोड़ अमेरिकी डॉलर, टरुइस्ट फायनैन्शल को 1,360 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वेल्ज फार्गो को 1,340 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं यूएस बैंक कॉर्प को 1,140 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है। यह सभी बड़े बैंक हैं अतः इस नुक्सान को सहन कर जाएंगे परंतु छोटे बैंक तो असफल (फैल) ही हो जाने वाले हैं। अभी तक दो बैंक (सिलिकॉन वैली बैंक एवं सिग्नेचर बैंक) बंद हो चुके हैं और 6 अन्य छोटे आकार के बैंकों (फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वेस्टर्न अलाइन्स बैंक, पैकवेस्ट, यूएमबी फायनैन्शल सहित) पर गम्भीर संकट आ गया था। इन बैंकों में रोकड़ एवं तरलता की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं इनके पास अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। इन बैंकों के शेयरों की कीमत पूंजी बाजार में 14 से 30 प्रतिशत के बीच गिर चुकी है।

परंतु भारत में चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार भारतीय बैंकों को 4.5 प्रतिशत रोकड़ रिजर्व अनुपात एवं 18 प्रतिशत संवैधानिक रिजर्व अनुपात बनाए रखना होता है। जिसके अंतर्गत बैंकों को रोकड़ एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उक्त राशि जमा रखना होती है, ताकि बैंकों को तरलता सम्बंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, भारतीय बैंकों में प्रति जमाकर्ता के खाते में रुपए 5 लाख तक की जमाराशि का बीमा भी रहता है। अतः अमेरिकी बैंकों पर आए संकट का प्रभाव भारतीय बैंकों पर पड़ता हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि भारतीय बैंकों की उक्त वर्णित मजबूत स्थिति के चलते भारतीय रिजर्व बैंक की आज पूरी दुनिया में बहुत प्रशंसा हो रही है कि क्योंकि उसने भारतीय बैंकों को आज इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास को 'गवर्नर आफ द ईयर' अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 के लिए सेंट्रल बैंकिंग, एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान जर्नल की ओर से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

फिर भी कुल मिलाकर भारतीय बैकों की आर्थिक स्थिति को लेकर अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैकों के किए जा रहे अपने निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर कुछ बैंकों में स्थिति ठीक नहीं है। अतः कॉरपोरेट गवर्नेस के मुद्दे पर इन बैकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। बैकों को अपने जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि उनकी जमाराशियां बैकों में सुरक्षित रहे। अतिमहत्वाकांक्षी तरीके से ऋण वितरण करने के तरीकों से बचना भी जरूरी है। इससे बैकों के व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि तो जाती है परंतु इस प्रकार प्रदान किए गए ऋणों की वसूली में कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी देश के बैकिंग क्षेत्र में संकट आने पर प्रायः यह पाया गया है कि यह संकट पूरे देश में ही आर्थिक संकट के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

कुछ बैंक स्मार्ट लेखा पद्धति अपनाकर अपने वित्तीय निष्पादन को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं एवं कुछ अन्य बैकों द्वारा गैरनिष्पादनकारी आस्तियों को भी छुपाया जाता है, इस तरह के प्रयास कुछ समय तक तो बैकों की वित्तीय स्थिति को छुपा सकते हैं परंतु लम्बे समय में इन बैकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस प्रकार के प्रयास नहीं किया जाने चाहिए। बैंक व्यवसाय में अति महत्वाकांक्षी वृद्धि दर हासिल करने के उद्देश्य से भी कुछ बैंक भारी जोखिम लेते पाए जाते हैं। जैसे, बाजार दर से कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना एवं जमाराशि पर तुलनात्मक रूप से अधिक ब्याज प्रदान करना आदि, इस तरह के प्रयासों से बैंक की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। कुछ बैकों को आस्ति देयता प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा बैंक में आस्ति देयता में असंतुलन एवं तरलता की समस्या खड़ी हो सकती है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कई बैकों ने निष्पादन सम्बंधी नतीजे घोषित किए हैं, इन नतीजों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैकों सहित कई बैकों ने अपने व्यवसाय एवं लाभप्रदता में अतुलनीय वृद्धि दर्ज की है। इस वित्तीय निष्पादन को जारी रखने के लिए बैकों को उक्त वर्णित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- प्रहलाद सबनानी

तो अपने बच्चों की शादी हो जाने के बाद भी इनके परिवार को संयुक्त परिवार के रूप में अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं। इससे बच्चों को मानसिक सहयोग प्राप्त होता है एवं वे भारतीय संस्कारों एवं सामाजिक संस्कारों को सीखते हैं। बचपन में ही, बच्चों को संयुक्त परिवार में रहने की शिक्षा दी जाती है। बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार देखकर ही भारतीय संस्कार भी सीखते हैं। इसके ठीक विपरीत अमेरिकी मूल के नागरिक अपने बच्चों को उनकी 18 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही अपने से अलग कर देते हैं एवं उन्हें अपना अलग घर बसाना होता है। बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पश्चिम के संस्कार ही कुछ इस तरह के हैं।

भारतीय मूल के अमेरिकी माता पिता अपने बच्चों में बचपन में ही, बच्चों के रुझान को पहचान कर उसी क्षेत्र में उनका कौशल विकसित करते हैं ताकि बच्चे भविष्य में उसी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकें। साथ ही, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं एवं बच्चों की गतिविधियों पर भी पूरी नजर रखते हैं ताकि उनके बच्चे किसी गलत राह पर न चल पड़ें। वे अपने बच्चों में बचपन में ही महान सनातन हिंदू संस्कृति, संस्कारों, परम्पराओं एवं विरासत का संवर्धन करते हैं। भारत में समस्त धर्मों को मानने वाले नागरिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अतः अमेरिका में भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बहुत संतोषी, शांतिप्रिय, मेहनती, अपने इरादों में पक्के एवं अपनो से बड़ों का आदर करने वाले पाए जाते हैं, वे किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर ही रखना पसंद करते हैं।

अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में भारतीय मूल के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य क्षेत्रों में अपार सफलता देखकर अब तो पूरा विश्व ही भारतीय संस्कारों को अपनाने के लिए लालायित होता दिखाई देने लगा है। ■

उच्च शिक्षा : न्यू नार्मल में एब्नार्मल

● **अनुज अग्रवाल, संपादक**

अभी हाल ही में मैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बारे में अपने परिचित से जानकारी ले रहा था जो वहां पढ़ रहा है।अमेरिका की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में शामिल लगभग छः हजार एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में तीन सौ से अधिक रिसर्च सेंटर व संस्थान हैं जिनमे 67 हजार से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। फीस के अतिरिक्त यूनिवर्सिटी के पास इतने प्रोजेक्ट कारपोरेट सेक्टर व सरकारों से आ जाते हैं कि वह पूर्णत: आत्मनिर्भर है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र के अनुसार "Great school with good professors, world class infrastructure, library & labs, fun social life, and lots of school spirit, e&cellent achievements of our people and for their contributions to society in the pursuit of education, research, and health care. Admission strictly on merit basis. Placement is good and The average base salary after PG is .106,372."

भारत में निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।किंतु विश्व स्तरीय संस्थानों से हम कितना पीछे हैं यह ऊपर के कथन से स्पष्ट हो गया है। इतने पर भी हमारे सैकड़ों केंद्रीय विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों ने सीमित संसाधनों व चुनौतियों के बीच विश्व में झंडे गाड़े हैं। केंद्रीय व राज्यों के सरकारी व सरकारी और निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी लगातार अपनी साख और सेवाओं का विस्तार कर रहीं हैं तो पिछले दो दशकों में निजी विश्वविद्यालयों की एक बड़ी श्रृंखला खड़ी हो गई है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी , पेरामेडिकल, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, डिजाइन, फाइन आर्ट्स, ला, स्पोर्ट्स, बीएड, पॉलीटेक्निक आदि के हजारो संस्थान खड़े हो चुके हैं। जो भी अच्छा कर रहा है वह तीव्र विस्तार कर रहा है और बड़े शिक्षा समूह व विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों के समूह में बदलता जा रहा है। कई ने देश के बाहर भी शाखाएं खोल ली हैं।

इतना सब के बाद
भ ी

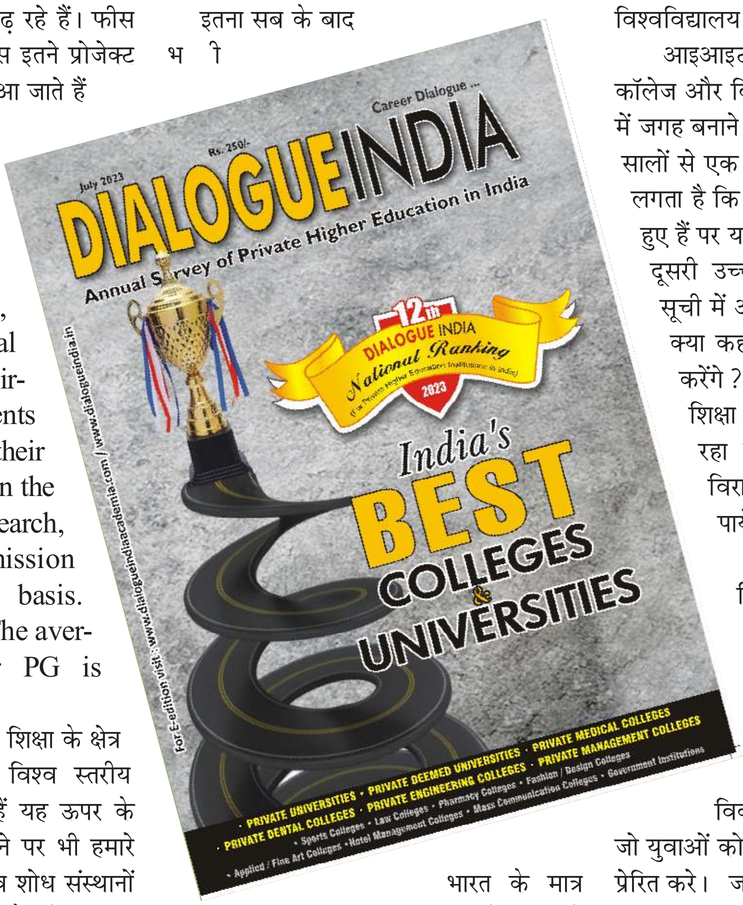

भारत के मात्र दस प्रतिशत सरकारी व निजी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थान ही ऐसे हैं जो परिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर, योग्य शिक्षक, लाइब्रेरी, शोध संस्थान, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व योग्य विद्यार्थियों से भरे हों। अच्छे प्रोजेक्ट, टाइ-अप्स, अच्छे प्लेसमेंट व स्टार्टअप भी इन्ही के हिस्से में आते हैं। इनको भारी मात्रा में सरकारी व अन्य सहायता व अनुदान भी मिल जाता है। इतना सबके बाद भी विश्व रैंकिंग में ये बहुत पीछे हैं।विडम्बना यह है कि भारत का कोई भी संस्थान वैश्विक शीर्ष सौ संस्थानों में अपनी जगह नहीं बना पाया। वैश्विक टॉप 200 में केवल तीन भारतीय संस्थान ही जगह बना पाए हैं। कुल मिलाकर 41 भारतीय संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने इस वर्ष क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग सूची में जगह बनाई है।

आइआइटी हो या आईआईएम या फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय, रैंकिंग के टॉप टेन में जगह बनाने वाली शिक्षण संस्थाओं में पिछले सालों से एक से नाम ही नजर आते हैं। यह तो लगता है कि ये संस्थाएं अपनी गुणवत्ता बनाए हुए हैं पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरी उच्च शिक्षण संस्थाएं आखिर टॉप सूची में आने से क्यों वंचित रहती हैं? हम क्या कहकर विदेशी छात्रों को आकर्षित करेंगे? भारत प्राचीन समय में उच्च शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र रहा है, फिर आजादी के बाद इस विरासत को क्यों नहीं कायम रख पाये?

इन त्रासद उच्च स्तरीय शिक्षा के परिदृश्यों में बदलाव लाने लाते हुए यह देखना है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में हम कैसे सम्मानजनक स्थान बनाये। भारत में समुचित सुविधाएं और अनुसंधान एवं विकास के लिए वह माहौल नहीं है जो युवाओं को नया सोचने और खोज करने को प्रेरित करे। जहां तकनीक चालित जगत में नित उन्नत अनुसंधान हो रहा है वहीं हमारी पुराने ढर्रे की शिक्षा प्रणाली आज भी रट्टा मारकर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केंद्रित है। यह कृत्य गहन प्रतिस्पर्धा वाली मौजूदा दुनिया में हमें पछाड़कर रख देगा, न ही इससे हमारे विश्वविद्यालयों और लैब्स में क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल

रिजेक्शन को सिलेक्शन में कैसे बदलें ?

जिस तरह से हमारे कदम आधुनिकता की तरफ तकनीकी के साथ जुड़ कर तेजी से आगे बढ़ रहे है उसी अनुपात में नई घटना और आश्चर्यचकित करने वाली बातें निकल कर सामने आ रही है। जिन पर आज बहस करना और समाधान खोजना बेहद जरुरी हो गया है। यदि आप नियमित समाचार पत्र पढ़तें हो तो आपकी जानकारी में यह होगा की नव-युवक और युवतियां रिजेक्शन को बर्दास्त नहीं कर पा रहें है और अनुचित कदम उठाने से गुरेज नहीं कर रहें। जब भी किसी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आता है तो ऐसी घटनाएं देखने को अक्सर मिल जाती है। आज अधिकांशतः ऐसा प्रचलित हो गया है की सफल लोगों की ही धाक और इज्जत है असफल लोगों की नहीं । जबकि सच्चाई यह है की प्रारंभ में असफल लोगों ने देश समाज को कुछ बड़ा दिया है । बचपन से यह सिखाया जाने लगा है की डॉक्टर, इंजिनियर, और सरकारी नौकरी के अतिरिक्त जीवन कही नहीं है । आधुनिकता की पहुंच मोबाइल के रूप में सभी के हाथों में है । सामाजिक नियंत्रण अब टूट चूका है । जिस उम्र में पढ़ाई करनी है उस उम्र में लोग अपराध कर रहें है । बाजारवाद का दबाव न केवल वयस्क लोगों पर है बल्कि नन्हे-मुन्नों को भी अपने नियंत्रण में तेजी से लेता चला जा रहा है । पाश्चात्य संस्कृति हम पर अब भारी होने लगी है । पारिवारिक सम्बन्धो और संस्कार को बिना नियंत्रण के वेब-सीरीज हर उम्र हर तबके को प्रसारित कर कुछ ऐसा सीखा रहें है जिसका परिणाम भयावह होने से शायद ही कोई रोक सकें । इन तमाम कारणों की वजह से रिजेक्शन को बर्दास्त नहीं किया जा रहा है जबकि सामान्य रूप से उसे स्वीकार्य कैसे किया जाए ? इस पर कदम उठाने की जरूरत है ।

रिजेक्शन को फेस करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है पर महत्वपूर्ण यह है कि सभी को इसका अनुभव होता है आप एकलौते इस संसार में नहीं है जिसने इसका बुरा अनुभव किया है, आपसे पहले भी और बाद भी लोग इसका अनुभव करेंगे । जब किसी को रिजेक्ट किया जाता है तो वह न केवल भारी दर्द को महसूस करता है बल्कि निराशा अपने चरम पर आ जाती है परिणाम स्वरुप व्यक्ति बेहद दुखी और क्रोध में हो जाता है और क्षण भर में गलत निर्णय की तरफ न केवल आकर्षित हो जाता है बल्कि सब कायदे कानून भूल कर अपराध कर बैठता है। ऐसी स्थिति जब भी उत्पन्न हो दिमाग को ठंडा रखकर रिजेक्शन को स्वीकार करना चाहिए । क्योंकि एक सफल इन्सान के जीवन की पहली सीढ़ी रिजेक्शन ही है जिससे आप न केवल मजबूत बनते है बल्कि अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करतें है।

कभी भी रिजेक्शन को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता । एक व्यक्ति के अंतर्गत अनेकों ऐसी खूबियां है जिसके माध्यम से वह अनेकों लोगों को प्रभावित कर सकता है साथ ही ऐसे कई बड़े काम कर सकता है जिससे इतिहास में उसका नाम दर्ज हो सकें । बड़े कलाकार, सेलेब्रिटी, बड़े अधिकारी, बिजनस मैन एक दो नहीं अनेकों बार प्रारम्भ में रिजेक्ट हुए है। पर जीवन में इसे स्वीकारना और आगे बढ़ना जरुरी होता है। आपकी इच्छा शक्ति रिजेक्शन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से न केवल आपको लड़ना सिखा देगा बल्कि जीवन को सामान्य रूप में लाने में मदद करेगी।

रिजेक्शन एक ऐसा अनूठा अनुभव है जिसे आप गहराई से समझ कर स्वयं की न केवल पहचान कर सकतें है बल्कि स्वयं के लिए लाभप्रद गत-विधियों में तेजी से आगे बढ़ सकतें है। मुशीबतें ही अवसर प्रदान करती है, न की सामान्य परिस्थितियां। इस बात को जितने जल्दी हम स्वीकार कर ले की रिजेक्शन जीवन का एक अहम् हिस्सा है जिससे सभी को दो चार होना ही पढ़ता है फिर चाहे निजी जीवन में हो, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में हो या शैक्षिक जीवन में हो, स्वीकार कर लेने से हम विजेता बन जातें है। सबसे अहम् पहलू यह है की किसी भी विषय/क्षेत्र में आप को रिजेक्ट होने के पश्चात् लगातार पुनः कोशिश करना ही आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकता है।

हम सभी को अपने आप को यह अनुमति देनी चाहिए की हम अपनी भावनाओं को महसूस कर सकें पर हम पर रिजेक्शन भारी न हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए । ऐसी परिस्थितियों में अपनी ताकत और उपलब्धियों को जरुर याद करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए की यही एक अंतिम विकल्प जीवन के लिए नहीं है । अपने आस-पास पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना चाहिए और उनकी बातों और आत्मविश्वास से स्वयं परिस्थिति से बाहर आने की भरपूर कार्य करनी चाहिए ।

मां-बाप की अपेक्षा अपने बच्चों से अत्यधिक होती है इन अपेक्षाओं के लिए उन-पर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए तथा हमेशा प्रेरित करना चाहिए की एक बेहतर जीवन कैसे व्यतीत किया जाए । रिजेक्शन के समय परिवार का साथ होना अपने आप में स्वतः पुनः लड़ने की नई शक्ति प्रदान करता है जबकि इसके विपरीत संवाद न होने और डर की स्थिति में कुछ ऐसा नुकशान कर देता है जिसकी भरपाई संभव नहीं हो सकती है । जीवन चलतें का नाम है आदरणीय मैथलीशरण गुप्त जी की एक रचना जिसमे उन्होंने लिखा है 'नर हो न निराश करों मन को, कुछ काम करों कुछ काम करों' एक ऐसी सुन्दर रचना है जिससे हम कई बातों को सीख सकतें है और रिजेक्शन से बाहर आने में मदद मिल सकती है । जब हम इस धरती पर आते है तो मौत धीरें से कानों में यह कह कर चली जाती है की जब तक मै वापस तुम्हे लेने नहीं आ रही हु तब तक जी ले अपनी जिंदगी, यानि की इस संसार में जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो एक असफलता और रिजेक्शन स्थायी कैसे हो सकता है । समय और सोच जीवन को बेहतर बनाने और लक्ष्य को भेदने की हर पल एक नई प्रेरणा देता है ऐसे में आत्मा की आवाज सुनियें और सोचिएं सिर्फ एक रिजेक्शन यह कैसे निर्धारित कर सकता है की अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं ? आपके पास अनेकों ऐसी उपलब्धियां है जिसके आधार पर आप नए सिरें से प्रयास कर रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदल सकते है ।

- डॉ. अजय कुमार मिश्रा

असली हथियार निजी स्कूलें है जो जड़े काटते हैं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने एवं तरह-तरह के कानूनों के प्रावधानों के बावजूद आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र के शिक्षा-मन्दिर बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की बजाय उन्हें कमाऊ-धन कमाने की मशीन बना रहे हैं। स्कूलें बच्चों को संस्कारी बनाने की बजाय उन पर हिंसा करने, पिटने, सजा देने के अखाड़े बने हुए है, जहां शिक्षक अपनी मानसिक दुर्बलता एवं कुंठा की वजह से बच्चों के प्रति बर्बरता की हदें लांघ रहे हैं, वहीं निजी शिक्षण संस्थाएं इन शिक्षकों का तरह-तरह से शोषण करके उन्हें कुंठित बना रहे हैं। सरकारें शिक्षा में अभिनव क्रांति करने का ढ़िढोरा पीट रही है, लेकिन अपने शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं पर सवार हिंसा की मानसिकता एवं उनके शोषण को दूर करने का कोई सार्थक उपक्रम नहीं कर पायी है। यही कारण है कि दिल्ली में एक प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका ने पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को न केवल बुरी तरह पीटा, बल्कि कैंची से वार करते हुए उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। यह कैसी शिक्षा है एवं कैसे शिक्षक है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होने के बावजूद शिक्षा की विसंगतियां एवं विडम्बनाएं दूर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज के निजी विद्यालय अपने शिक्षकों को उचित वेतन एवं प्रोत्साहन नहीं देते। अपने आर्थिक लाभ के लिये निजी स्कूलें शिक्षकों को वास्तविक वेतन कुछ और देते है और पूरे वेतन के वाउचर पर हस्ताक्षर लेते हैं, यह शिक्षा के मन्दिरों से जुड़ी अनैतिकता का बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं ये निजी स्कूलें परीक्षा परिणाम को अव्वल लाने के लिये छात्रों पर तरह-तरह के गैरकानूनी प्रयोग करने की छूट शिक्षकों को दे देते हैं। दूसरी ओर अपने निजी लाभ के लिये शिक्षक छात्रों के परीक्षा परिणामों से छेड़छाड़ करने, कक्षाओं में छात्रों के साथ भेदभाव करने, उनको बेवजह सजा देने का दुस्साहस भी करते हैं ताकि छात्र उन शिक्षकों से ट्यूशन लेने को विवश हो सके। शिक्षक का पेशा पवित्रतम एवं आदर्श माना जाता है। यह इसलिए भी कि शिक्षक के माध्यम से ही बच्चों के भविष्य की नींव तैयार होती है।

देश भर में निजी स्कूलों के शिक्षकों का काफी शोषण किया जाता है। शोचनीय यह है कि जिन अध्यापकों की वजह से ये स्कूल चलते हैं, उन्हें वेतन काफी कम मिलता है, जबकि वे अपनी पूरी जिंदगी उस स्कूल को संवारने में लगा देते हैं। खासतौर से शिक्षिकाओं की मजबूरी का खूब फायदा उठाया जाता है। शहर में संचालित छोटे-बड़े निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी उन्नति व सुख सुविधा के लिए शिक्षा को व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है। जिस कारण निजी विद्यालय दिन प्रतिदिन शिक्षक व अभिभावकों के आर्थिक शोषण का केंद्र बन गया है। सरकारी विद्यालयों की चरमराती शैक्षणिक व्यवस्था से आहत अभिभावकों के सामने अपने बच्चों को बेहतर तालिम देने की समस्या खड़ी होती जा रही है। वहीं निजी स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था की चमक दमक से

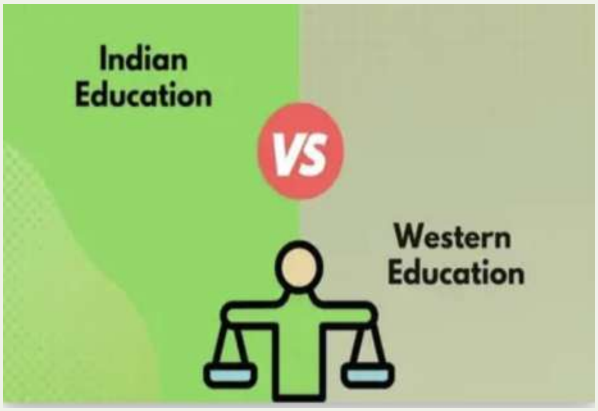

अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। ऐसे स्कूलों में बच्चों के नामांकन के बाद अभिभावक परेशान है। कई पीड़ित अभिभावकों ने कहा कि नामांकन के समय जो स्कूल प्रबंधन द्वारा सब्जबाग दिया जाता है, उस हिसाब से न तो शैक्षणिक व्यवस्था है और सुविधा। प्रतिवर्ष मनमाने ढंग से विविध शुल्कों में वृद्धि कर दी जाती है। अभिभावकों की शिकायत को प्रबंधन द्वारा नहीं सुनी जाती है उल्टे बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिए जाने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। ऐसे छोटे बड़े निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक व अन्य कर्मियों ने दबी जुवान में कहा कि बच्चों का शुल्क तो प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाता है पर हमलोगों के पगार में मामूली वृद्धि भी नहीं की जाती है। समाज के संवेदनशील लोगों की माने तो निजी शिक्षण संस्था धीरे-धीरे अपने मकसद से भटकता जा रह है। वहां कमजोर बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके विकास को लेकर प्रबंधन को कोई चिंता नहीं है।

मनुष्य को मनुष्यता का भान कराने में शिक्षा ही सशक्त माध्यम है तथा सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराने का दर्पण है। आज की शिक्षा अधूरी है एवं इसमें आधारभूत सुधारों की आवश्यकता है। इस पर वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं, सम्मेलन होते रहते हैं तथा अनेक शिक्षा-शास्त्रियों के आयोग भी बनाए गए। उनके सुझावों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी घोषित की गयी है, पर हमारी शिक्षा प्रणाली अभी तक उपयुक्त दिशा की ओर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भारतीयता के मूल्यों की पटरी से उतरी हुई है। खुले आकाश के नीचे चल रही पाठशालाओं से लेकर पहाड़ों पर उच्च स्तरीय विद्यालय चल रहे हैं। समानता की दृष्टि से यह स्थिति जमीन और पहाड़ जितनी दूरी लिए हुए है। यह फर्क कब मिटेगा, यह कोई नहीं जानता। विदेशी शासन से मुक्ति का अमृत महोत्सव के बाद भी शिक्षा अभी तक विदेशी भाषा और विदेशी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकी है। हजारों की तादाद में देश में अंग्रेजी और मिशनरी (कोन्वेंट) स्कूल चल रहे हैं जहां शिक्षा में भाषा के माध्यम से लेकर प्रार्थनाएं तक अंग्रेजी में होती हैं। हम हैं कि एक दीवानगी पाले हुए हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में धड़ल्ले से बोले। हमारी संस्कृति पर केवल विदेशी टी.वी. के चैनल ही हमला नहीं कर रहे बल्कि असली धारदार हथियार तो ये स्कूल हैं, जो जड़ें ही काट देते हैं।

विदेशी भाषा का हम भाषा और साहित्य की दृष्टि से आदर कर सकते हैं, कुछ अंशों में विदेशी संस्कृति के अच्छे पक्षों को भी स्वीकार सकते हैं पर भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति की कीमत पर कत्तई नहीं। ऐसे स्कूल में एक बार एक लड़के को इसलिए अपमानित होना पड़ा कि रक्षा बन्धन के पवित्र त्यौहार पर राखियां बांधे स्कूल चला गया। एक दूसरे कान्वेंट स्कूल में एक लड़की को इसलिए कक्षा में नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी रची हुई थी। यह जानकर मेरा ही नहीं, मेरे भारत के हर नागरिक को भी धक्का

लगेगा। लेकिन यह सच्चाई है। इस प्रवाह में केवल मिशनरी ही नहीं अनेक भारतीय संचालक भी बह रहे हैं। स्कूलों के नाम भी अंग्रेजी, ड्रेसें भी अंग्रेजी। उद्देश्य केवल अर्थलाभ। संस्कृति को मिटाकर, सबकुछ भुलाकर। एक बात सौ वर्ष पुरानी है। राजस्थान की एक रियासत के राजा की लड़की बचपन में ही विधवा हो गई। अपना पूरा समय ध्यान, पूजा और भजन में व्यतीत करने लगी। एक दिन राजघराने में एक अंग्रेज मेहमान आया। राजा ने सबसे परिचय कराते वक्त अपनी विधवा लड़की से भी मिलाया। सारी बात सुनकर अंग्रेज मेहमान ने लड़की से कहा, 'तुमने दुबारा शादी क्यों नहीं की?' लड़की की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने सिर पर हाथ फेरकर पूछा, 'क्या हुआ बेटी?' लड़की ने कहा, 'मुझे दुःख इस बात का है कि इसने यह तो पूछा कि तुमने दुबारा शादी क्यों नहीं की, यह नहीं पूछा कि तू मीरां क्यों नहीं बनी।' लेकिन ऐसी सोच वाली बालिकाएं आज की शिक्षा से तो तैयार नहीं हो सकती। यह गौरवशाली भारतीय संस्कृति की उज्ज्वलता थी। ऐसा उत्तर जिस दिन देश की बालिकाएं देंगी, तभी सबकुछ बदलेगा, शिक्षा वास्तविक भारतीय मूल्यों एवं सिद्धान्तों से परिपूर्ण होगी।

ऐसा लगता है कि न नये इंसानों को गढ़ने की सही प्रक्रिया है और न इंसान गढ़ने के प्रति शिक्षक एवं शिक्षण-संस्थानों के भीतर सच्ची निष्ठा। ऐसी स्थिति में शिक्षा का दायित्व कैसे अपने मुकाम पर पहुंचे? इसी कारण शिक्षा की सीख एवं साख नहीं बन पा रही है। शिक्षण संस्थानों पर उन्नत नागरिक बनाने दायित्व है, लेकिन लगता है इस दायित्व को निभाने वालों की सोच एवं समझ के दायरे बदल गये हैं। शिक्षा के आदर्श, सिद्धान्त एवं शैली के प्रति बनी नई मान्यताओं ने नये मानक बना लिये हैं।

यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि स्कूलों में पढ़ाई पूरी व गुणवत्तापूर्ण हो, प्रभावी एवं सहज हो ताकि लोभ, ट्यूशन, शोषण, बर्बरता एवं हिंसक व्यवहार की जरूरत न हो। सरकारी व निजी स्कूलों के आर्थिक प्रलोभनों, शिक्षकों में ट्यूशन की दुष्प्रवृत्ति एवं सजा देने पर अंकुश भी रखना होगा। छात्रों से ज्यादा जरूरी है शिक्षकों का चरित्र विकास और शिक्षण-संस्थानों को भारतीयाता के सांचे में ढालने की। तभी नये भारत एवं सशक्त भारत की ओर बढ़ते देश की शिक्षा अधिक कारगर एवं प्रभावी होगी। उसके लिये शिक्षा-क्रांति से ज्यादा शिक्षक-क्रांति एवं व्यावसायिक होती शिक्षा को नियंत्रित करने की जरूरत है।

– ललित गर्ग

इंटेलिजेंस, नैनो-टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इत्यादि नवीनतम तकनीकों का वैसा प्रसार हो पाएगा, जो भविष्य को आकार दे रहा है। आज भारत तमाम क्षेत्रों और विधाओं में पश्चिमी जगत और चीन का मुकाबला करना चाहते है, परंतु तरक्की के लिए जो दो अवयव - शिक्षा और स्वास्थ्य - एक पूर्व-शर्त हैं। भारत में रक्षा सामग्री, मेडिकल उपकरण, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, वाहन, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों के आयात पर अरबों-खरबों रुपये खर्च रहे हैं। यह इसलिए कि स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं नगण्य हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी हैं, अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण युद्धस्तर पर करना जरूरी है और इसकी राह शिक्षा एवं स्वास्थ्य से होकर है। जिस रूस और अन्य पश्चिमी मुल्कों से हम खरबों डॉलर का आयात कर रहे हैं उन्हीं से तकनीक देने को कह रहे हैं ताकि वे वस्तुएं भारत में बन सकें, पर इसमें सफलता न्यून रही है। कंप्यूटिंग क्षमता की बात करें तो आज भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तो हमारी स्थिति उस बच्चे की मानिंद है जो अभी चलना सीख रहा है। दवा क्षेत्र में, मुख्य घटक सामग्री और नवीनतम खोज के लिए हम अभी भी चीन और पश्चिमी मुल्कों पर निर्भर हैं। हमारे पास आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे विश्वस्तरीय संस्थान हैं, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत कम हैं और बड़ी बात यह कि यहां से प्रशिक्षित होकर निकली प्रतिभाओं को हम उचित माहौल देकर देश में नहीं रोक पा रहे। इन संस्थानों से पढ़कर निकले अधिकांश स्नातक उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए पश्चिमी देशों का रुख करते हैं। भारत में वैसा माहौल और अवसर नहीं हैं कि देश की प्रतिभा स्वदेश में रहना चुनें। यह ब्रेन-ड्रेन देश का बड़ा घाटा है। ध्यान का केंद्र उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी बनाने और अनुसंधान के लिए सरकारी धन मुहैया करवाने पर हो। विकसित देशों में यही युक्ति कारगर रही है, जहां पर वे आपसी तालमेल से चलते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा की इस दयनीय स्थिति के कारण ही वर्ष 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। अकेले वर्ष 2022 में ही 7.5 लाख भारतीयों ने विदेश जाने का अपना उद्देश्य अध्ययन करना बताया था। एक बात साफ है कि विश्व स्तरीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं का काफी नीचे के पायदान पर होना भी इसकी एक महत्त्वपूर्ण वजह है। भारत की रैंकिंग में टॉप टेन पर रहने वाली उच्च शिक्षण संस्थाएं जब वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष सौ की सूची में भी नहीं आए तो चिंता होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना ही नहीं है बल्कि चिंतन, मनन और शोध की नई धारा को प्रवाहित करना एवं गुणवान नागरिकों का निर्माण करना भी इस उद्देश्य में शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2035 तक स्कूल में दाखिला लेने वाले पचास फीसदी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा का मार्ग भी चुनेंगे। ऐसे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षण संस्थाओं को वैश्विक मुकाबले में आने योग्य बनाना होगा। यह चुनौती इसलिये भी बड़ी है कि हमने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिये भी भारत के दरवाजे खोल दिये हैं। इसलिये भारत के उच्च-शिक्षण संस्थानों के लिये यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे संख्यात्मक नहीं, बल्कि गुणात्मक दृष्टिकोण लिए हों। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हुए अगस्त तक

काश भक्ति की जगह 'शिक्षा' पर ध्यान होता

जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको राजनेता भक्ति भाव में मतदान तक डुबोए रखना चाहते है। सारे राजनेता इसी में जुट गए है। आप चाहे शोर कितना ही मचाएं लेकिन किसी राजनेता या राजनीतिक दल के पास इतनी दूरदर्शिता नहीं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य पर बजट तो शिक्षा से भी कम है, जोकि जीडीपी के 1.5 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत के बीच झूलता रहता है।

संसद में सरकार द्वारा रखे आंकड़े देश की दशा बताते हैं , भारत से विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में एक वर्ष में 68 प्रतिशत इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में यह गिनती 7,50,365 रही, जबकि 2021 में 4,44,553 थी। न्यूनतम अनुमान के मुताबिक, इस पर आया खर्च काफी विशाल होगा। लेकिन हम सुधार की अपेक्षा रखें भी कैसे, जब पिछले दो दशक से भी ज्यादा अवधि में, सालाना बजट में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का महज 3 प्रतिशत खर्च रखा गया हो। इकॉनोमिक सर्वे के अनुसार यह मद केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों की मिलाकर है।

राज्य और केंद्र सरकारें हमें अज्ञानी और अधकचरे,और धार्मिक रूप से बंटे हुए ऐसे नागरिक बनाए रखना चाहती हैं, जो समय-समय पर बंटने वाली सरकारी खैरातों में मुफ्त की वस्तुएं पाने के लिए पंक्तियों में लगे रहें। सर्वमान्य तथ्य है कि कमजोर इंसान को जाति-पाति, धर्म, पंथ इत्यादि के नाम पर बरगलाकर वोट प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होता है। अपने देश में सुविधाओं की कमी के कारण युवाओं के पास उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने के सिवा विकल्प नहीं बचता। जो मौके उपलब्ध हैं भी, वे राजनीतिक लाभ के लिए बनाए विभिन्न किस्मों के आरक्षण कोटों की वजह से बहुत कम रह जाते हैं।

सवाल यह है उच्च शिक्षा और अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की ओर हमारे बच्चों का यह पलायन क्या यूं ही जारी रहेगा ? भारत में समुचित सुविधाएं और अनुसंधान एवं विकास के लिए वह माहौल नहीं है जो युवाओं को नया सोचने और खोज करने को प्रेरित करे, सरकारें धर्म विभाजन और अन्य नामों पर बंटवारे करने वाले आयोजन करती है । जहां तकनीक चालित जगत में नित उन्नत अनुसंधान हो रहा है वहीं हमारी पुराने ढर्रे की शिक्षा प्रणाली आज भी रट्टा मारकर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केंद्रित है। लगता है हम अपने इतिहास का पुनर्निमाण करने और उसे अपने भविष्य के तौर पर पेश करने पर तुले हुए हैं। यह कृत्य गहन प्रतिस्पर्धा वाली मौजूदा दुनिया

में हमें पछाड़कर रख देगा, न ही इससे हमारे विश्वविद्यालयों और लैब्स में क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो-टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इत्यादि नवीनतम तकनीकों का वैसा प्रसार हो पाएगा, जो भविष्य को आकार दे रहा है।

आज भारत तमाम क्षेत्रों और विधाओं में पश्चिमी जगत और चीन का मुकाबला करना चाहते है, परंतु तरक्की के लिए जो दो अवयव - शिक्षा और स्वास्थ्य - एक पूर्व-शर्त हैं, वह देश की राजनीतिक सोच में नदारद है। भारत में रक्षा सामग्री, मेडिकल उपकरण, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, वाहन, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों के आयात पर खरबों-खरबों रुपये खर्च रहे हैं। यह इसलिए कि स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं नगण्य हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी हैं, अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण युद्धस्तर पर करना जरूरी है और इसकी राह शिक्षा एवं स्वास्थ्य से होकर है। भारत सरकार उद्योगों के आधुनिकीकरण में निवेश करने को निजी क्षेत्र की मुख्य भूमिका बनवाने में सफल नहीं हो पाई।

कैसी विडंबना है कि जिस रूस और अन्य पश्चिमी मुल्कों से हम खरबों डॉलर का आयात कर रहे हैं उन्हीं से तकनीक देने को कह रहे हैं ताकि वे वस्तुएं भारत में बन सकें, पर इसमें सफलता न्यून रही। कंप्यूटिंग क्षमता की बात करें तो आज भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तो हमारी स्थिति उस बच्चे की मानिंद है जो अभी चलना सीख रहा है। दवा क्षेत्र में, मुख्य घटक सामग्री और नवीनतम खोज के लिए हम अभी भी चीन और पश्चिमी मुल्कों पर निर्भर हैं।

कहने को हमारे पास आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे विश्वस्तरीय संस्थान हैं, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत कम हैं और बड़ी बात यह कि यहां से प्रशिक्षित होकर निकली प्रतिभाओं को हम उचित माहौल देकर देश में नहीं रोक पा रहे। इन संस्थानों से पढ़कर निकले अधिकांश स्नातक उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए पश्चिमी देशों का रुख करते हैं। भारत में वैसा माहौल और अवसर नहीं हैं कि देश की प्रतिभा स्वदेश में रहना चुनें। । यह ब्रेन-ड्रेन देश का बड़ा घाटा है। ध्यान का केंद्र उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी बनाने और अनुसंधान के लिए सरकारी धन मुहैया करवाने पर हो। विकसित देशों में यही युक्ति कारगर रही है, जहां पर वे आपसी तालमेल से चलते हैंहमारे यहां राजनीति गडे मुर्दे उखाड़ने और आलोचना में व्यस्त है।

डिजिटल यूनिवर्सिटी के शुरू होने और विदेशों के ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज और येल जैसे उच्च स्तरीय लगभग पांच सौ श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों के भारत में कैंपस खुलने शुरु हो जायेंगे। अब भारत के छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा स्वदेश में ही मिलेगी और यह कम खर्चीली एवं सुविधाजनक होगी। इसका एक लाभ होगा कि कुछ सालों में भारतीय शिक्षा एवं उसके उच्च मूल्य मानक विश्वव्यापी होंगे।

डायलॉग इंडिया का वर्ष 2023 का सर्वे बता रहा है कि शीर्ष दस प्रतिशत संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो भारत में शेष 90% उच्च शिक्षा संस्थान एक जैसी समस्याओं व चुनौतियों से घिरे हैं। लगभग सभी संस्थान एडमिशन के लिए कंसल्टेंट, एजुकेशन फेयर व एक्सीबिशन, आक्रामक व अक्सर झूठा प्रचार, अतिरंजित इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, टाई-अप्स, सुविधाओं, प्लेसमेंट के दावे करने वाले विज्ञापन, एचआर मैनेजर की मदद से फर्जी नियुक्ति पत्र, डिग्री बेचने, बेमतलब के शोध, झूठे पेटेंट, सरकारों व रेग्युलेटरी संस्थाओं को भारी रिश्वत, सरकारी अनुदान में गड़बड़ी आदि का शिकार हैं। बेसिक स्किल की कक्षाएं देना उनकी मजबूरी है क्योंकि स्कूली शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है।

भारत में स्कूली शिक्षा में छात्र-छात्रों के ड्रॉपआउट्स की संख्या बढ़ना न केवल शिक्षा-व्यवस्था पर बल्कि स्कूल-प्रबंधकों पर एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आठ करोड़ से भी ज्यादा है, जो यह बताने के पर्याप्त है कि स्थिति काफी गंभीर है। पिछले साल पैंतीस लाख विद्यार्थी दसवीं के बाद ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए। इनमें से साढ़े सत्ताइस लाख सफल नहीं हुए और साढ़े सात लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इसी तरह, पिछले साल बारहवीं के बाद 2.34 लाख विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी।

डायलॉग इंडिया का सर्वे कहता है कि अगर उच्च शिक्षा व उनसे जुड़े संस्थानो के स्तर को सुधारना है तो बेसिक व माध्यमिक शिक्षा को पेचिदा बनाने की बजाय सहज एवं रोचक बनाना होगा। ताकि कुछ बच्चों को स्कूल बोरिंग न लगे है, 9वीं और 10वीं कक्षा तक आते-आते कई बच्चों को स्कूल बोरिंग लगने लगता है। इस कारण वे स्कूल देरी से जाना चाहते हैं, क्लास बंक कर देते हैं और लंच ब्रेक में बैठे रहते हैं। पढ़ाई और स्कूल से लगाव ना होने की वजह से अक्सर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। किसी भी वजह से बच्चे का स्कूल या पढ़ाई छोड़ने का मन करना, पैरेंट्स के लिए एक बड़ी परेशानी है, लेकिन यह शिक्षा की एक बड़ी कमी की ओर भी इशारा भी करता है।

लगातार शिक्षा मन्दिरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी बच्चों को स्कूलें छोड़ने पर विवश करते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद भी भारत में सिंगल टीचर स्कूलों की मौजूदगी बनी हुई है। स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापक नहीं है, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वे आठवीं के बाद आगे पढ़ने लायक क्षमता का विकास नहीं कर पाते। स्कूल आने वाले लाखों बच्चों में गणित और भाषा के बुनियादी कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस कारण से स्कूल छोड़ने वाली स्थितियां निर्मित होती हैं।

भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि करोड़ों बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। बहुत से सरकारी स्कूलों में शौचालय की स्थिति दयनीय है, विशेषत: बालिकाओं एवं बच्चे सम्मान के साथ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गांवों एवं पिछड़े इलाकों की स्कूलों की बात छोड़िये, राजधानी दिल्ली में स्कूलों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बैठने के लिये पर्याप्त साधन नहीं है, इस स्थिति में भी बदलाव की जरूरत है। बहुत से स्कूलों में शिक्षक शराब पीकर आते हैं। या फिर स्कूल में हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाते हैं। ऐसी स्थिति का असर भी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। शिक्षकों को बच्चों की प्रगति और पीछे रहने के लिए जिम्मेदार बनाने वाला सिस्टम नहीं बन पाया है, इस दिशा में भी गंभीर पहल की जरूरत है।

ऐसे में अधिकांश बारहवीं पास बच्चे जैसे तैसे रट्टा मारकर या नकल कर पास होते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मुसीबत व बोझ बन जाते हैं। बड़े जतन व बहला फुसला कर लिए गए इन विद्यार्थियों को न तो लैब समझ आती है न लाइब्रेरी और न ही अंग्रेजी में पढ़ाते अध्यापक की बाते और यह सब दिखाबटी और सजावटी अधिक हो जाता है। दस बीस प्रतिशत औसत या बेहतर विद्यार्थियों को अलग कक्षायें देकर शेष के लिए मजबूरी में संस्थान बेसिक स्किल पढ़ाते रह जाते हैं और मूल कोर्स कवर ही नहीं हो पाता। फिर इज्जत बचाने के लिए अतिरिक्त अंक दिलवाने के जुगाड़ किए जाते हैं और जैसे तैसे विद्यार्थी को डिग्री थमा दी जाती है। इसीलिए भारत में डिग्री का रोजगार से कोई ख़ास नाता नहीं है। यहां तक कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट और शिक्षा भी बस कागज़ी ज़्यादा हैं।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति और चौथी औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक है कि

- शिक्षा का भारतीयकरण हो, भारत की भाषाओं में हो व यह भारत की आवश्यकताओं पर केंद्रित हो ।
- बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पर अधिक फोकस किया जाए।अगर उच्च शिक्षा संस्थानो को प्रतिभाशाली व योग्य विद्यार्थी मिलेंगे तो उनकी गुणवत्ता में निखार आता जाएगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध, अनुसंधान, इनोवेशन, स्किल व एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना होगा।
- कंप्यूटर व आईटी के साथ अन्य ब्रांचों में भी समान रूप से अवसरों की उपलब्धता व वेतन उपलब्ध होने चाहिए।
- आरक्षण व्यवस्था समाप्त करनी होगी व निर्धन को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा देनी होगी। साथ ही एजुकेशन लोन के लिए धन की उपलब्धता को भी कई गुना बढ़ाना होगा
- छात्र व अध्यापकों के संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण व पारदर्शी बनानी होगी ।
- वह सभी वस्तुएं जो हम आयात करते हैं उनको देश में ही बनाने का तंत्र विकसित करना होगा।
- विश्व को जलवायु परिवर्तन के कारण मिल रही चुनौतियों का समाधान भारतीय दृष्टिकोण से खोजना होगा।
- डिजिटलीकरण व एआई की चुनौती का सामना करने में हमारा शिक्षा तंत्र सक्षम हो व रोजगार परक हो।

यह सब यूही नहीं होगा, इसके लिए शिक्षा के बजट व सरकार और समाज के संकल्प दोनों को दोगुना करना होगा ताकि सभी जरूरी संसाधन जुटाए जा सके और उनके माध्यम से ईमानदारी से लक्ष्यों की पूर्ति का मनोबल विकसित किया जा सके। ■

तीन मोर्चे तीन गठजोड़
नये मुद्दे, नये साथियों पर जोर

लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे पास आता जा रहा है वैसे वैसे भाजपा, कांग्रेस और तीसरे मोर्चे का नया स्वरूप आकार लेता जा रहा है। भाजपा के विरोध में बार बार ऐसी कवायद का प्रयास किया जा रहा है जिसमे कांग्रेस और तीसरे मोर्चे को मिलाकर एक संयुक्त विपक्ष बनाया जाये किन्तु इसमे सफलता नहीं मिल रही है। पटना में सभी विपक्षी दल एक साथ मिले तो वहां भी सबके अपने अपने हित एक दूसरे से टकराते रहे। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी बौखलाए हुये हैं। वह किसी भी तरफ के भाजपा विरोधी खेमे में शामिल होने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर कांग्रेस ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया तो वह उसके साथ नहीं आयेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह उस गठबंधन में नहीं रहेगी जिसमे कांग्रेस शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा 2017 का चुनाव एक साथ गठबंधन करके लड़ चुके हैं और इस बार इन दोनों का भी एक साथ आना संदिग्ध है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ संयुक्त गठबंधन तो चाहते हैं किन्तु यह भी चाहते हैं कि कांग्रेस कई राज्यों के चुनाव से दूर रहे। कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं होगा ? ऐसे में संयुक्त विपक्ष के गठबंधन की कल्पना भी साकार होती नहीं दिख रही है। तीसरे मोर्चे के लिए की जा रही गोलबंदी की जिम्मेदारी अब शरद पवार को सौंपी गयी है। शरद पवार ने दो महत्वपूर्ण बाते कहीं हैं। एक, भाजपा के विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, विपक्षी मोर्चे के पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होना आवश्यक नहीं है। यह दोनों बातें हालांकि नयी नही हैं किन्तु विपक्षी एकता के सूत्रधार किसी नेता द्वारा यह दोनो बातें पहली बार कही गयी हैं। इस घटनाक्रम के एक अन्य मुख्य किरदार नितीश कुमार ने जबसे भाजपा से अपना नाता तोड़ा है तबसे वह भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने को लेकर मुखर रहे हैं। पटना रैली के बाद उनकी मुखरता स्पष्ट रूप से दिख रही है। वह लगातार भाजपा के विरुद्ध एक संयुक्त उम्मीदवार की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा पहले हिमाचल प्रदेश और बाद में कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति सुधरी है। संयुक्त विपक्ष की काल्पनिक अवधारणा में कांग्रेस की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ न आना इस बात का संकेत है कि आप कुछ राज्यों में स्वयं को कांग्रेस का विकल्प मान रही है। दिल्ली और पंजाब में आप ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर ही सत्ता हासिल की है। विपक्षी दलों की अगली बैठक अब शिमला में होगी जहां यह तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ? विपक्षी एकता की इस कोशिश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि क्षेत्रीय दल अपने से काफी बड़े एक राष्ट्रिय दल कांग्रेस को सुझाव दे रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। कांग्रेस के लिए यह अपनी कुर्बानी देने वाली स्थिति है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अपना वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि भाजपा और संघ भारत की नींव पर आक्रमण कर रहे हैं। नितीश कुमार भाजपा पर भारत का इतिहास बदलने का आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब सेकुलर बन रहे हैं। मोदी के सहयोगी रहे यह सभी दल मोदी हटाओं का अभियान तो चला रहे हैं किन्तु बदलाव की इस बयार में न ही कोई वैकल्पिक अजेंडा दे पा रहे हैं और न ही कोई राष्ट्रिय विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं। भाजपा और मोदी को सिर्फ अल्पसंख्यक विरोधी होने का मुद्दा दिखाकर यह दल चीन और पाकिस्तान को रास आने वाले बयान देते जा रहे हैं। नए संसद भवन का बहिष्कार करके और सेंगोल के विषय में भारतीयता न देखकर विपक्षी दलों ने मोदी खेमे के वोटरों में अपनी पैठ बनाने का एक मौका गंवा दिया। ऐसा लगता है कि इन सभी दलों में सत्ता में आने से ज्यादा मोदी विरोध के जरिये मोदी विरोधी खेमे के वोटर को अपने खेमे में लाने की कवायद ज्यादा चल रही है।

● **अमित त्यागी**

इस शताब्दी के प्रारम्भ में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय एनडीए की सरकार थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठन को अब 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। किसी समय एनडीए का गठन कांग्रेस के विरुद्ध एक मोर्चे के रूप में किया गया था। बहुत से क्षेत्रीय दल कांग्रेस के विरोध के फलस्वरूप इसमे जुड़े। 1989 के बाद से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस तरह का हो गया कि इसमे बिना गठबंधन के बहुमत प्राप्त नहीं होता है। हालांकि, 2014 और 2019 में भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को प्राप्त किया किन्तु इस दौरान भाजपा के साथ एनडीए में उसके घटक दल जुड़े रहे। अपने शुरुआती दौर के एनडीए और वर्तमान एनडीए में बहुत से घटक दल भाजपा को छोड़ चुके हैं। एक समय भाजपा के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे शिवसेना और जेडीयू वर्तमान में भाजपा विरोधी खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार का विरोध करके कांग्रेस छोडकर नया दल बनाने वाले शरद पवार और ममता बनर्जी इस समय कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त विपक्ष बनाने की कवायद कर रहे हैं। 370 हटने के बाद से भाजपा द्वारा एक झटके में कश्मीरी राजनीति में दरकिनार कर दिये गए पीडीपी और नेशनल कान्फ्रेंस 370 के विषय पर विपक्षी एकता के राग गा रहे हैं। एक समय कांग्रेस के घोटाले का विरोध करके एवं

सब मिले हुये हैं जैसे जुमले देने वाले केजरीवाल राजनीतिक व्यवस्था में पूरी तरह व्यवस्थित हो चुके हैं। अब वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं भाजपा के विरोध के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इनमे से ज़्यादातर दल एनडीए के विरोध में तो हैं किन्तु कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में जाने के लिए यह क्षेत्रीय दल तैयार नहीं हैं। वह चाहते हैं कि वह एक तीसरा गठजोड़ बनाएं जिसमे कांग्रेस उनकी शर्तों पर शामिल हो। अब यह एक अजीब विडम्बना है जिसमे क्षेत्रीय दल किसी राष्ट्रिय दल को यह सुझाव दे रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं। मोदी विरोध का सबका अजेंडा तो स्पष्ट है किन्तु ये लोग न कोई वैकल्पिक एवं रचनात्मक खाका देश के सामने रख पा रहे हैं और न ही मोदी को हटाने की कोई ठोस वजह जनता के समक्ष रख पा रहे हैं। यही वजह है कि संयुक्त विपक्ष की आड़ में चलने वाली कवायद तीन या चार मोर्चे तक पहुचती दिख रही है।

सबसे पहले यदि एनडीए की संरचना पर बात करें तो 2014 के बाद से एनडीए को लेकर भाजपा की रणनीति यही रही है कि वह बड़े सहयोगी के स्थान पर छोटे सहयोगी पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसकी वजह स्पष्ट है कि छोटे दलों से राजनीतिक सौदेबाजी आसान होती है। 2014 के बाद से ही स्वयं की सफलता से उत्साहित भाजपा सहयोगी दलों पर निर्भरता कम

पीओके और कॉमन सिविल कोड

2024 का अजेंडा सेट करते मोदी-राजनाथ

2024 के लिए एक तरफ सभी विपक्षी दल एकजुट होने का अजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं भाजपा 2024 के लिए चुनावी अजेंडा भी सेट कर चुकी है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का विषय जोर शोर से उठाया। उन्होने स्पष्ट कहा कि हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। हम तुष्टीकरण के रास्ते पर वोट बैंक के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा रास्ता तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। आज कॉमन सिविल कोड का विरोध हो रहा है जबकि संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। एक परिवार में रहने वाले दो लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। ऐसा होने पर परिवार कैसे चलेगा। तुष्टीकरण की गंदी सोच ने देश में खाई पैदा की। सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांगने वालों ने गरीब के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय किया है। मुस्लिम को वोट बैंक समझने वालों ने पस्मांदा मुस्लिमों की दुर्दशा पर ध्यान क्यों नहीं दिया है। उन्हे आज भी नीच और अछूत माना जाता है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि तीन तलाक ने सिर्फ मुस्लिम बेटियों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान किया है। यदि इस्लाम में इसकी स्वीकृति होती तो यह इस्लामिक देशों में भी लागू होता। भारत के मुसलमानों को अब समझना होगा कि कौन दल उन्हे भड़काकर उनका शोषण कर रहे हैं। 2024 में भाजपा की प्रचंड जीत से बौखलाकर विपक्षी लोग सिर्फ अपने परिवार का भला करने की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का विषय उठाकर 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाक अधिक्रांत कश्मीर का विषय उठा चुके हैं। रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत की संसद ने संकल्प लिया है कि पाक अधिक्रांत भूभाग भारत का अभिन्न अंग है।

यदि देखा जाये तो भारत की जम्मू, कश्मीर और लद्दाख नीति के संदर्भ में भारतीय संसद द्वारा 22 फरवरी 1994 को पारित प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेज है। उस समय की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में भारतीय संसद ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जताते हुए कहा था कि यह भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना होगा, जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है। भारतीय संसद द्वारा पारित इस प्रस्ताव का मूल था कि यह सदन पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकियों के शिविरों पर गंभीर चिंता जताता है। सदन का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को हथियारों और धन की आपूर्ति के साथ-साथ आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद दी जा रही है। सदन भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत अपने इस भाग के विलय का हर संभव प्रयास करेगा। भारत में इस बात की पर्याप्त क्षमता और संकल्प है कि वह उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे, जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हो और मांग करता है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे, जिसे उसने कब्जाया हुआ है। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर जवाब दिया जाएगा।

जब तक 370, 35ए नहीं हटी थी तब तक 22 फरवरी को पारित प्रस्ताव भी सिर्फ एक प्रस्ताव दिखाई देता था। इस पर अमल होना एक दुस्वप्न नजर आता था। किन्तु जब से 370 का खात्मा हुआ है तब से नरसिंह राव द्वारा पारित यह प्रस्ताव भी अपनी पूर्णता की आस दिखाने लगा है। अब जिस तरह से रक्षा मंत्री द्वारा इस विषय को उठाया गया है उसके बाद लग रहा है कि भारत अति शीघ्र इस पर कोई प्रभावी कार्य करने की योजना बना रहा है।

-अमित त्यागी

महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलट फेर के बाद अजित पवार बने डिप्टी सीएम

महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर अजित पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की और इसके बाद 17 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए राजभवन रवाना हो हुए.

राजभवन में अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें शपथ दिलाई. इस दौरान अजित पवार समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. उनके अलावा नौ एनसीपी विधायक भी शपथ ले रहे हैं जिनमें धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाडे, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धन्नी मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी राजभवन मौजूद हैं. इसके अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद हैं जिन्हें शरद पवार का करीबी कहा जाता है।

बताया जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर नहीं दिए जाने के बाद अजित असंतुष्ट थे. बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी शामिल हुईं. हालांकि, सुले बैठक छोड़कर चली गईं. रविवार सुबह एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पुणे में मौजूद शरद पवार से फोन पर बातचीत की. राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखते हुए, शरद पवार ने पुणे में रहने का फैसला किया है और कथित तौर पर अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।

कैसे महाराष्ट्र में हुई इतनी बड़ी उलटफेर?

1. एकनाथ शिंदे, बीजेपी के समर्थन वाले बयान दे रहे थे. बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी नजदीकियां जगजाहिर हैं. पटना में हुई विपक्षी एकता की महाबैठक से वह नाराज थे. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह शरद पवार और सुप्रिया सुले बैठक में शामिल होने से नाराज थे.
2. अजित पवार, चाहते थे कि एनसीपी की कमान उन्हें ही मिले. शरद पवार के होते यह मुमकिन नहीं था कि पार्टी की बागडोर उन्हें मिले. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, राजनीति में हैं. वह बेटी के रहते भतीजे को पार्टी की कमान सौंपते नजर आ नहीं आ रहे थे. अजित पवार की बगावत की एक वजह यह भी है.
3. अजित पवार, अध्यक्ष का खुद को प्रबल दावेदार मानते हैं. अलग बात है उनके पास समर्थन नहीं था. उनके समर्थक विधायकों ने भी कहा कि वह अलग पार्टी बनाएं और सत्ता में वापसी करें.
4. अजित पवार का दावा है कि उनके पास कम से कम 40 विधायकों का समर्थन मिला है. ऐसे में उनके पास मजबूत समर्थन है. वह सत्ता में आने का खोखला दावा नहीं कर रहे हैं. उनके समर्थक विधायकों ने जो उनके आवास पर हुए बैठक में यह फैसला लिया है.
5. बैठक के तुरंत बाद, पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को समर्थन पत्र सौंपने के लिए राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे और कुछ ही देर बाद उन्होंहोंने मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में तीसरी बार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ एनसीपी विधायक छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, हसन मुश्रिफ और बाबूराव अत ने भी मंत्रिपद की शपथ ली है.

नीतीश कुमार को भी बिहार में विद्रोह का डर, महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद बोले सुशील मोदी

बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की आज की हालत को लेकर विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। जदयू को भी अपनी पार्टी में विद्रोह की आशंका जता रही है।

नीतीश को पार्टी में भगदड़ की आशंका

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी है लेकिन जदयू के विधायक-सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे और न ही तेजस्वी यादव को स्वीकार करेंगे। अगर ऐसा होगा तो पार्टी में भगदड़ मचने की आशंका है।

10 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी

बीजेपी नेता ने कहा कि इस समय जदयू पर अपना वजूद बचाने का संकट मंडरा रहा है, जोकि पहले कभी नहीं था। इसलिए नीतीश कुमार ने 13 साल में कभी विधायकों का हाल तक नहीं पूछा लेकिन अब वे सभी विधायकों से अलग-अलग मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू अगर महागठबंधन में शामिल हुआ तो टिकट बंटवारे में उसके हिस्से में लोकसभा की 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी और कई सांसदों पर बेटिकट होने की तलवार लटकती रहेगी। जिससे पार्टी में विद्रोह मच सकता है।

विधायकों से बिना पूछे गए लालू के साथ

सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार ने विधायकों से बिना पूछे भाजपा से गठबंधन तोड़ा और फिर लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया। नतीजन बिहार में विकास की रफ्तार टूट गई। इससे दल के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। अब अगर वन-टू-वन भी बातचीत करें तो ये आग बुझने वाली नहीं है।

ललित गर्ग

चुनावी रथ में सवार दलों की सत्ताकांक्षा

आजादी के अमृतकाल के पहले लोकसभा चुनाव की आहट अब साफ-साफ सुनाई दे रही है। भारत के सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह चुनावी मुद्रा में आ गये हैं और प्रत्येक प्रमुख राजनैतिक दल इसी के अनुरूप बिछ रही चुनावी बिसात में अपनी गोटियां सजाने में लगे दिखाई पड़ने लगे हैं। 2024 लोकसभा एवं इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, वह पहली बार देखने को मिल रहा है की चुनाव के इतने लम्बे समय पूर्व ही चुनाव जैसी तैयारियां होती हुई दिख रही है। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक हो रहे हैं। विरोधी विचारधारा के दलों के साथ ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बता रहे हैं। कुछ प्रमुख दलों के नेता स्वयं को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देख रहे हैं। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक हुआ है, वहां राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चालाक हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें बिछाने शुरु कर दिये हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ प्रतीत करेगा। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा देश की डेढ़ अरब जनता को आजादी के अमृतकाल में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। सभी इस एक दिन के राजा को लुभाने में जुटे हैं। कोई मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश करने में जुटा है तो कोई गठबंधन को आधार बनाकर चुनाव जीतने के सपने देख रहा है।

विपक्षी दल येन-केन-प्रकारेण भाजपा को सत्ता से बाहर करने में जुटे हैं, इसके लिये विपक्षी दलों में एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं। भाजपा एवं उसके सहयोगी दल भी अपनी स्थिति को मजबूती देते हुए पुन: सत्ता में आने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये एनडीए ने भी नए साथियों की तलाश तेज कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हाल में हुई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की यात्रा से इसके पक्के संकेत मिले। भाजपा लंबे समय से दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी उसने इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर भारत में वह पिछले लोकसभा चुनाव में जितना चमत्कारी प्रदर्शन किया गया कि इस बार उसे दोहराना उसके लिये जटिल प्रतीत हो रहा है। इसलिए अगर उसे फिर से बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आना है तो दक्षिण में सीटें बढ़ानी होंगी। इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या में संभावित कमी की भरपाई हो जाएगी। भाजपा इस योजना पर पूर्ण आत्मविश्वास एवं प्रखरता के साथ बढ़ भी रही थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों से उसे झटका लगा। इसके बाद से कहा जा रहा है कि भाजपा पहले जितनी ताकतवर नहीं रही। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपनी हार के कारणों को बड़ी गहराई से लेते हुए उन कारणों को समझने एवं हार को जीत में बदलने के गणित को बिठाने में माहिर है।

आम चुनाव की सरगर्मियां उग्रता पर है, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प एवं चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत को आम चुनाव की जीत से जोड़ने की जल्दबाजी दिखाना शुरु कर दिया है। जिस तरह हिमाचल एवं कर्नाटक में उसने मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लिया, उसे वह इसी वर्ष होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा एवं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराने को तत्पर है। इसका ताजा प्रमाण है जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यह घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो सौ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, रसोई गैस सिलेंडर पांच सौ रुपये में दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। उन्होंने इसे पांच गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की गारंटियां कर्नाटक एवं हिमाचल में दी गयी थी, उन्हें पूरा करने के लिए दोनों ही प्रांतों की चुनी सरकारों को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। जैसी गारंटियां, लोकलुभावन वादे एवं मुक्त की रेवड़ियां कांग्रेस देने की बात कर रही है, वैसी ही अन्य दल भी कर रहे हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी का सर्वे-सर्वा है। क्योंकि अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में उसने

दस गारंटियां दी थीं। ये गारंटियां और कुछ नहीं लोकलुभावन वादे ही होते हैं, जिन्हें जनकल्याण का नाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चुनाव से छह महीने पहले ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा रखी है जिससे राज्य का चुनावी माहौल और गर्मा रहा है।

किसी भी राष्ट्र के जीवन में चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है। यह एक यज्ञ होता है। लोकतंत्र प्रणाली का सबसे मजबूत पैर होता है। राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क के संविधान प्रदत्त पवित्र मताधिकार प्रयोग का एक दिन। सत्ता के सिंहासन पर अब कोई राजपुरोहित या राजगुरु नहीं बैठता अपितु जनता अपने हाथों से तिलक लगाकर नायक चुनती है। लेकिन जनता तिलक किसको लगाये, इसके लिये सब तरह के साम-दाम-दंड अपनाये जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने लोकलुभावन वायदों एवं घोषणाओं को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बता रहे हैं, जो सब समस्याएं मिटा देगी तथा सब रोगों की दवा है। लेकिन ऐसा होता तो आजादी के अमृतकाल तक पहुंच जाने के बाद भी देश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं से नहीं जुझता दिखाई देता। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि 'अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।'

लोकसभा चुनाव केवल दलों के भाग्य का ही निर्णय नहीं करेगा, बल्कि उद्योग, व्यापार, रक्षा आदि राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय एकता, स्व-संस्कृति, स्व-पहचान तथा राष्ट्र की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग जाति का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। और दलों के आधार पर गठबंधन भी एक प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में बदले हुए हैं। एक प्रांत में सहयोगी वही दूसरे प्रांत में विरोधी है। कुर्सी ने सिद्धांत और स्वार्थ के बीच की भेद-रेखा को मिटा दिया गया है। चुनावों का नतीजा अभी लोगों के दिमागों में है। मतपेटियां क्या राज खोलेंगी, यह समय के गर्भ में है। पर एक संदेश इस चुनाव से मिलेगा कि अधिकार प्राप्त एक ही व्यक्ति अगर ठान ले तो अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी आदि समस्याओं पर नकेल डाली जा सकती है। लेकिन देश बनाने एवं विकास की ओर अग्रसर करने की बजाय सभी दल मुक्त रेवडियां बांट कर एक अकर्मण्य पीढ़ी को गढ़ने की कुचेष्टा कर रहे हैं, कई बार तो ऐसी घोषणाएं भी कर दी जाती हैं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे-अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या देर से अथवा उनके लिए धन का प्रबंध जनता के पैसों से ही किया जाता है। उदाहरणस्वरूप कर्नाटक सरकार ने दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोकलुभावन वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। जो चुनाव सशक्त एवं आदर्श शासक नायक के चयन का माध्यम होता है, उससे अगर नकारा, ठग एवं अलोकतांत्रिक नेताओं का चयन होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं देश की विडम्बना है।

- ललित गर्ग

करके स्वयं के विस्तार पर जुट गयी है। इसी क्रम में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों पर उसने अपना वर्चस्व बनाया। जैसे महाराष्ट्र में देखें तो वहां भाजपा और शिवसेना एक समय एक दूसरे के पूरक कहे जाते थे। विधानसभा में शिवसेना और लोकसभा में भाजपा को ज़्यादा सीटें देने की एक अघोषित सहमति दोनों दलों में रहती थे। जब भाजपा का प्रभाव बढ़ा तो भाजपा राज्य पर भी अपना वर्चस्व चाहने लगी। इसी क्रम में शिवसेना और भाजपा के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गयी और शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में शिवसेना के उद्धव ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया। बाल ठाकरे की कट्टर शिवसेना अब उद्धव के नेतृत्व में सेकुलर है। उसमे भी अब दो फाड़ हो चुके हैं। एक धड़ा उद्धव के साथ है तो दूसरा धड़ा शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है।

बिहार में भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन में एक प्रमुख दल नितीश कुमार का जेडीयू भी रहा था। लालू यादव के विरोध और कांग्रेस से दूरी के बाद भाजपा और जेडीयू दशकों तक साथ रहे। महाराष्ट्र की तरह ही वर्चस्व की लड़ाई बिहार में हुयी और भाजपा की ताकत बढ़ने लगी। अपनी राजनीतिक असुरक्षा को महसूस करके नितीश कुमार ने निर्णय लिया और उन्होने भाजपा का साथ छोड़ दिया। इसके बाद सबसे खास बात यह रही कि उन्होने उस दल आरजेडी के साथ हाथ मिलाया जिसके विरोध में चुनाव लड़के वह सत्ता में आए थे। अलग अलग राज्यों में दल मोदी को हटाकर लोकतन्त्र बचाना चाहते हैं। भाजपा के बढ़ते वर्चस्व के बीच स्वयं के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करने वाले यह राजनीतिक दल मोदी को हटाकर कौन सा लोकतन्त्र बचाना चाहते है, यह आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा भी नए सहयोगियों की आवश्यकता महसूस कर रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा कुछ राज्यों में अपना सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर चुकी है। उस स्तर पर टिके रहना भाजपा के लिए आसान नहीं है। इसके साथ ही दस साल सरकार रहने के बाद सत्ता विरोधी रुझान भी

क्यों आवश्यक है समान नागरिक संहिता?

आजादी के अमृतकाल में समानता की स्थापना के लिये अपूर्व वातावरण बन रहा है, इसके लिये वर्तमान में समान नागरिक कानून की चर्चा बहुत ज्यादा है। यह भारत की बड़ी जरूरत है। समानता एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक लोकतांत्रिक मूल्य है। इस मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये समान कानून की अपेक्षा है। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब-तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को झेलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने 14 जून 2023 को राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव 30 दिनों के अंदर आमंत्रित किए हैं। विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव आमंत्रित किए जाने के बाद इस पर बहस एक बार फिर से उग्र रूप से शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है।

समान नागरिक संहिता को लेकर भी एक ऐसा फोबिया बन गया है जिससे देश की सियासत को धर्मों में बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। सियासत में ध्रुवीकरण की राजनीति जमकर हो रही है। बेहतर यही होगा कि मुस्लिम समाज अपनी गलतफहमियों को दूर करे। यद्यपि भारतीय संविधान में सभी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आजादी दी गई है। मजहब भले ही अलग-अलग हों लेकिन देश एक है। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि एक देश में अलग-अलग धर्मों के हिसाब से अलग-अलग कानून कैसे औचित्यपूर्ण हो सकते हैं, फिर बवाल क्यों? देश का मुस्लिम भी समाज का एक हिस्सा है, जिसे इसी रूप में प्रस्तुत करने की परिपाटी चलन में आ जाए तो भेद करने वाले विचारों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को ऐसे भ्रम में रखने के लिए प्रेरित किया कि वह भी ऐसा ही चिंतन करने लगा, जबकि सच्चाई यह है कि आज के मुसलमान बाहर से नहीं आए, वे भारत के ही हैं। परिस्थितियों के चलते उनके पूर्वज मुसलमान बन गए। वे सभी स्वभाव से आज भी भारतीय हैं और विचार से सनातनी हैं, लेकिन देश के राजनैतिक दल अपने राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक के चलते मुसलमानों के इस सनातनी भाव को प्रकट करने का अवसर नहीं दे रहे।

भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां विभिन्न पंथों व पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इन सबके शादी करने, बच्चा गोद लेने, जायदाद का बंटवारा करने, तलाक देने व तलाक उपरांत तलाकशुदा महिला के जीवनयापन हेतु गुजारा भत्ता देने आदि के लिए अपने-अपने धर्मानुसार नियम, कायदे व कानून हैं। इन्हीं नियमों, कायदे व कानूनों को पर्सनल लॉ कहते हैं। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने यह विविधता देखी, तो उस समय उन्हें लगा पूरे देश को सुचारूरूप से चलाने के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता बनानी आवश्यक है। जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो हर धर्मों के लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसे में उन्होंने लम्बे समय तक यहां अपने पांव जमाये रखने के लिए किसी से उलझना ठीक नहीं समझा। इन परिस्थितियों में 1860 में उन्होंने इंडियन पैनल कोड तो लागू किया पर इंडियन सिविल कोड नहीं। यानि एक देश-एक दंड संहिता तो लागू की, लेकिन एक देश-एक नागरिक संहिता लागू करने का जिम्मेदारी एवं साहसपूर्ण काम नहीं किया। उसके बाद बनी सरकारों ने तो अंग्रेजों की सोच एवं नीतियों का ही अनुसरण किया, इसलिये वे भी अपने राजनीतिक हितों के लिये इसे लागू नहीं किया। जबसे नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए ऐसे राष्ट्रहित के निर्णय लेकर राष्ट्र को नया उजाला एवं सांसें दी है।

आज जबकि भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जी-20 देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, भारत की अहिंसा एवं योग को दुनिया ने स्वीकारा है, विश्व योग दिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस जैसे आयोजनों की संरचना हुई है। इन सब सकारात्मक स्थितियों को देखते हुए भारत की कानून विषयक विसंगतियों को दूर करना अपेक्षित है। क्योंकि विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता का पालन में होता है। लेकिन भारत में राजनीतिक फायदे के लिए तुष्टिकरण का ऐसा खेल खेला गया, जो विविधता में एकता एवं वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन को तार-तार कर रहा है। निजी कानूनों के कारण कहीं-कहीं विसंगति के हालात भी पैदा हो रहे हैं। सामुदायिक घटनाओं को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, घटना को देखने का यह नजरिया वास्तव में वर्ग भेद को बढ़ावा देने वाला है।

वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग समान नागरिक कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज की महिलाएं इस कानून के समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सुर्खियों में आया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में बिल पास कराया था। इस कानून के समर्थकों का मानना है कि अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।

संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि अलग-अलग धर्म के लिए अलग-अलग कानूनों के बजाय सभी नागरिकों के लिए धर्म जाति भाषा क्षेत्र और लिंग निरपेक्ष एक 'भारतीय नागरिक संहिता' लागू होना चाहिए। लेकिन भारत में जब भी समान नागरिक संहिता की बात उठती है तो उसका इस आधार पर विरोध किया जाता है इसके आधार पर वर्ग विशेष को निशाना बनाने की कोशिश है। इसके विरोध में तरह-तरह के कुतर्क दिए जाने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की मानें तो समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की पहल मोदी सरकार के ध्रुवीकरण का एजेंडा है। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने ध्रुवीकरण के किसी एजेंडे के तहत ही अनुच्छेद 44 में यह लिखवा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है? कांग्रेस को इस प्रश्न पर विचार करने के साथ ही इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने के बाद भी वह समान नागरिक संहिता के मामले में संविधान निर्माताओं की इच्छा का पालन नहीं कर सकी।

अगर हम यह चिंतन भारतीय भाव से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देगा कि समान नागरिक कानून देश और समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। अगर इसे हिन्दू मुस्लिम के संकुचित भाव से देखेंगे तो खामी न होने के बाद भी खामियां दिखाई देंगी। मौजूदा सरकार पूरे देश में हर नागरिक को समान अधिकार देने के पक्ष में है। वह पुरुष हो या महिला। हिंदू हो या मुसलमान या किसी दूसरे मजहब को मानने वाले नागरिक। ऐसा होगा तभी देश में सामाजिक समरसता की स्थापना संभव हो सकेगी। लोक राज्य, स्वराज्य, सुराज्य, रामराज्य का सुनहरा स्वप्न भेदपूर्ण कानून व्यवस्था की नींव पर कैसे साकार होगा? यहां तो सब अपना-अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं।

- ललित गर्ग

एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। हालांकि, मोदी के चेहरे के सामने सत्ता विरोधी रुझान का प्रभाव बहुत कम दिखता है किन्तु फिर भी उस तत्व को नकारा नहीं जा सकता है। सत्ता विरोधी रुझान का फर्क फ्लोटिंग वोटर पर पड़ता है और फ्लोटिंग वोटर ही सबसे महत्वपूर्ण मतदाता होता है। वह जिस खेमे के साथ चला जाता है, उसकी सरकार बनवा देता है। जनादेश निर्धारण में यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है।

विपक्षी एकता बनाम एनडीए का नया स्वरूप

उत्तर भारत में फ्लोटिंग वोटर निर्णायक रहता है। ऐसे ही एक वर्ग पर उत्तर प्रदेश में पकड़ रखने वाले ओमप्रकाश राजभर भाजपा के साथ जाते दिख रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में वह अखिलेश यादव के साथ थे। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद वहां जेडीएस हाशिये पर चला गया है। बहुमत न होने की स्थिति में कर्नाटक में जेडीएस सौदेबाजी की भूमिका में आ जाता है। अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जेडीएस का भाजपा के साथ जाना राजनीतिक मजबूरी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भाजपा से करीबी दिखा रहे हैं। टीडीपी फिर से एनडीए के खेमे में आना चाह रही है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने नितीश कुमार से अलग होकर नया दल बनाया है। वह भी एनडीए की तरफ आते दिख रहे हैं। बिहार के नए समीकरणों में जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी के धडे भी एनडीए के साथ आएंगे। पंजाब में जबसे प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है तबसे अकाली दल के लिए राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने अकाली दल कभी भी प्रभावी विपक्ष नहीं दिखता है। ऐसे में अकाली दल यदि फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाये तो कोई हैरानी की बात नहीं मानी जाएगी। पर भाजपा के लिए इन नए दलों के साथ सामंजस्य आसान नहीं है।

आंध्र प्रदेश में अगर भाजपा फिर से चंद्रबाबू नायडू को जोडती है तो जगनमोहन रेड्डी से उसके रिश्ते खराब होंगे। भाजपा एक तरफ टीडीपी से नजदीकियां बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ जगनमोहन को पोलावरम परियोजना के माध्यम से लाभ दे रही है। भाजपा इन दोनों ही दलों के साथ संतुलन साधने का प्रयास कर रही है। अब यदि दक्षिण के अन्य राज्यों की ओर देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडू और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा के स्थानीय संगठन और इकाइयां चिंता का विषय हैं। तमिलनाडू के अध्यक्ष अन्नामलाई नहीं चाहते हैं कि भाजपा नेतृत्व एआईएडीएमके के किसी भी धड़े के साथ कोई समझौता करे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता के बाद भाजपा का एक धड़ा असंतुष्ट दिख रहा है। इन सबके बावजूद भाजपा के साथ एक सकारात्मक पक्ष यह है कि केन्द्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद सभी असंतुष्ट धड़े तुरंत एक हो जाते हैं। मोदी के चेहरे के बाद कोई भी असंतोष बाकी नहीं रहता है।

कांग्रेस के साथ जाने से बचते क्षेत्रीय दल

अब अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की बात करें तो वह लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस की जिस तरह लगातार किरकिरी हुयी उसके बाद उसके अनेक सहयोगी उससे बचने लगे। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ। इस चुनाव में दोनों दलों की जबरदस्त हार हुयी। इसके बाद सपा और बसपा ने 2019 में गठबंधन किया। इसमे भी यह गठबंधन हार गया। अब उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन तो चाहती है किन्तु यह भी चाहती है कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर चुनाव

समान नागरिक संहिता का विरोध अनुचित

विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड पर फिर से आम लोगों और धार्मिक संस्थाओं आदि का सुझाव मांगना स्पष्ट करता है कि अब इसके साकार होने का समय आ गया है। पिछले वर्ष ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। उसी समय लग गया था कि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने भी समान नागरिक संहिता की बात की।फिर असम सरकार ने भी इसकी घोषणा की। कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की ओर से धीरे-धीरे यह संदेश दिया जाता रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए जिस समान नागरिक कानून का सपना देखा और संविधान में उसे शामिल किया उसको साकार करने का कार्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भीऔर प्रदेश की भाजपा सरकार है करने जा रही है। मोदी सरकार ने इस दिशा में काफी पहले ही पहल कर दी थी। विधि आयोग ने 7 अक्टूबर, 2016 को समान नागरिक संहिता पर राय मांगी थी। इसके बाद 19 मार्च, 2018 और फिर 27 मार्च, 2018 को भी सलाह मांगी गई थी। ध्यान रखिए 31 अगस्त, 2018 को विधि आयोग ने फैमिली लौ यानी परिवार कानून के सुधार की अनुशंसा भी की थी प्रमिला।

जो सूचना है विधि आयोग के पास करीब 70 हजार सुझाव आए थे। ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक लाने के पहले एक बार फिर जनता और धार्मिक संगठनों के साथ जाने का मन बनाया है। चूंकि पिछले कुछ समय में इस पर काफी बहस हुई एवं न्यायालयों की भी टिप्पणियां आई है, इस कारण विधि आयोग ने फिर से कंसल्टेशन पेपर यानी सलाह प्रपत्र जारी किया है। उसने कहा है कि उस कंसल्टेशन पेपर को जारी हुए काफी समय बीत चुका है इसलिए हम नया जारी कर रहे हैं। निस्संदेह , इसके समर्थकों एवं विरोधियों दोनों का दायित्व बनता है कि अपना मत विधि आयोग के समक्ष रख हैं। लेकिन समान नागरिक कानून को लेकर जिस तरह का माहौल देश में बनाया जाता रहा है उसमें यह उम्मीद करना व्यर्थ होगा एक बड़ा समूह सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करेगा। इन्हें यह समझना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार का रिकार्ड अपनी विचारधारा पर की गई घोषणा से पीछे हटने का नहीं रहा है। इसलिए आपका रवैया चाहे जो हो यह मान लीजिए कि अब देश में सभी के लिए एक समान नागरिक कानून बनेगा और व्यवहार में आएगा।

विश्व में एकमात्र भारत देश है जहां समान नागरिक कानून को भी सांप्रदायिक, फासीवाद, किसी एक समुदाय के विरुद्ध, हिंदू राष्ट्र का प्रतीक और न जाने क्या-क्या कहा जाता है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां समान नागरिक कानून नहीं हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने यूं ही भारत में समान नागरिक संहिता की वकालत नहीं की। संविधान सभा में स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी जबरदस्त पैरवी की तथा उनके साथ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ए कृष्णस्वामी अय्यर जैसे नेताओं ने भी इसकी वकालत की। इसी कारण संविधान के चौथे भाग में लिखित नीति निर्देशक तत्व में इसे स्थान मिला। इसे एक त्रासदी कहा जाएगा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी संविधान निर्माताओं का यह महान सपना साकार नहीं हो सका। क्यों? इसका उत्तर देने के पहले यह समझें कि आखिर समान नागरिक कानून से होगा क्या? इसके माध्यम से विवाह, तलाक, भरण-पोषण भत्ता, विरासत और गोद लेने जैसे नियम कानून एक समान होंगे। इसके बाद यह मायने नहीं रखेगा कि आप किस मजहब या किस पंथ से हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समान नागरिक संहिता न होने के कारण न केवल सामाजिक असमानता की स्थिति है बल्कि यह सेकुलरिज्म यानी पंथनिरपेक्षता के मूल आधार के लिए भी चुनौतियां खड़ी करती हैं। कहा जाए तो समतामूलक समाज के निर्माण के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय एकता में भी बाधक बना हुआ है। तर्क यह दिया जाता है कि समान नागरिक संहिता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। ये भूल जाते हैं कि इससे कानूनी विसंगतियां पैदा होती है और फिर धार्मिक सौहार्द पर ही आघात पहुंचता है। अगर आप अलग-अलग समुदायों मुसलमानों ,ईसाइयों आदि के पर्सनल कानूनों को देखें तो इसमें लैंगिक आसमानता साफ दिखता है। यानी धार्मिक समुदायों के पर्सनल कानून व्यवहार में महिला विरोधी हैं। इसलिए कोई यह न माने कि किसी राजनीतिक विचारधारा का थोथा आदर्श है। वास्तव में यह सभी समुदायों के बीच व्याप्त विषमता को दूर कर सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का आधार बनेगा । इसी से राष्ट्रीय एकता सशक्त होगी। कानून के समक्ष समानता के साथ निष्पक्षता और स्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए भी समान नागरिक संहिता आवश्यक है।

यहीं पर क्यों प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। आखिर आज तक यह लागू क्यों नहीं हुआ? हमारे देश में सेक्यूलरवाद की गलत अवधारणा यह बनी कि यहां मुसलमानों, ईसाइयों या ऐसे दूसरे समुदायों के सामाजिक -सांस्कृतिक - मजहबी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। धर्म और संस्कृति तो समझ में आती है पर उसके नाम पर सामाजिक व्यवस्था और कानूनी ढांचा अलग किया जाना सेक्यूलरवाद का पर्याय नहीं हो सकता। 1985 में शाहबानो मामले ने इस दिशा में सबसे बड़ा आघात पहुंचाया। जबलपुर के न्यायालय ने एक बूढ़ी महिला शाहबानो को उसके तलाक देने वाले पति से गुजारे भत्ते का आदेश दिया। उसका वकील पति उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक आया और उसे पराजय मिली। मात्र 179 रुपया 20 पैसा मासिक गुजारा भत्ता का आदेश मुसलमानों के सड़क पर उतरने का कारण बन गया। इसका इतना विरोध हुआ कि अंततः तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला कानून पारित कर न्यायालय के निर्णय को पलट

दिया। तब से सत्ता के अंदर यह धारणा बनी कि मुस्लिम मामलों में हस्तक्षेप करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। इस तरह कहा जा सकता है कि समान नागरिक कानून बनाने से बनाने से बचने या विरोध करने का मूल कारण राजनीति है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां अपने एजेंडे में समान नागरिक संहिता को शामिल करती रही हैं पर वह इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं क्योंकि इसे भाजपा की सरकार लागू करने की बात करती है। समाजवादियों में डॉ राम मनोहर लोहिया से लेकर अन्य कई नेताओं ने इसके मांग की थी। आज समाजवाद के नाम पर चलने वाली पार्टियां ही इसके विरोध में खड़ी है। साफ है कि इसके पीछे केवल मुस्लिम और जहां ईसाई हैं वहां उनके वोट बैंक की राजनीति है।

भारत में गोवा ऐसा राज्य है जिसने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। गोवा उत्तराधिकार, स्पेशल नोटरीज एंड इन्वेंट्री प्रोसीडिंग्स कानून, 2012 बनाने और लागू करने में अलग-अलग समुदायों की सांस्कृतिक विशेषता को विशेषाधिकार के रूप में सुरक्षित रखते हुए सफलता प्राप्त किया गया है। यह हिंदू संहिता में सहभागिता की अवधारणा को विस्तारित करते हुए दूसरे समुदायों के विवाह पूर्व समझौतों के साथ संपत्तियों के मिल्कियत में साझापन को मान्यता देता है। गोवा का अनुभव अभी तक अच्छा है तो यह देश के लिए भी समस्यामूलक नहीं होगा।

अगर यह भारत के संविधान का लक्ष्य नहीं होता और आवश्यकता महसूस नहीं होती तो उच्चतम न्यायालय बार-बार इस दिशा में आगे बढ़ने की बात नहीं की होती। अनेक फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश को समान संहिता की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें सन 2020 का जोस पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजो वेलेंटिना परेरा और अन्य मामले में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की टिप्पणियों का बार-बार उल्लेख किया जाता है। उन्होंने कहा था कि 1956 में हिंदू कानूनों के संहिताबद्ध होने के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए, जैसा पूर्व में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो और सरला मुद्गल और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में सुझाया भी गया था। यह किसी के गले उतर सकता है की आखिर जब देश की 80 प्रतिशत आबादी संहिताबद्ध निजी कानूनों के दायरे में आ गई है तो अन्य समुदायों को ऐसे कानूनों की परिधि से परे रखने का क्या औचित्य है? इसे धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक -विविधता का अपमान बताने वाले न केवल उच्चतम न्यायालय बल्कि हमारे महान नेताओं के सपने पर प्रश्न खड़ा करते हैं। यह सामाजिक समानता एवं सबको समान न्याय सुनिश्चित करने का वाहक होगा। इस तरह नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। संसद में पारित कर सरकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्ष्य और महान नेताओं के सपने को साकार करे।

- अवधेश कुमार

लड़े। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि मुस्लिम मतदाता अब सपा से निराश हो चुका है इसलिए अब वह अपने परंपरागत दल कांग्रेस की तरफ वापस आयेगा। ऐसे में सपा का यूपीए के साथ आना संभव नहीं है। वह तीसरे मोर्चे के साथ ही रहेगा। बंगाल में वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस में से कोई एक कांग्रेस के साथ रहेगा। तृणमूल ने स्पष्ट कर दिया है कि वाम दलों के साथ रहने की स्थिति में वह गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। आप ने भी कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया है। यह सब समीकरण संयुक्त विपक्ष के स्थान पर तीसरे धड़े की अवधारणा ज़्यादा पुष्ट कर रहे हैं।

नए संसद भवन के उदघाटन के अवसर पर 20 दलों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, पर उससे ज़्यादा दल उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहिष्कार करने वाले यह सभी दल आपस में भी एकजुट नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान विपक्षी एकता की वैचारिक असमानता दिख गयी थी। उस दौरान यह सभी दल अपने अंतर्विरोधों के कारण एकजुटता दिखाने का मौका चूक गए थे। इन सभी दलों में अंतर्विरोध से ज़्यादा वैचारिक दुराग्रह दिखता है। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और बीआरएस के मुखिया चन्द्रशेखर राव को निमंत्रित नही किया गया तो ममता बनर्जी निमंत्रण के बाद भी कार्यक्रम में नही पहुंचीं। यह दल भाजपा से निपटने से पहले एक दूसरे को निपटाने की रणनीति पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे जब सोनिया और राहुल से केन्द्रीय जांच अजेंसियों की पूछताछ हुयी तो उस समय आप के नेताओं के बोल जग जाहिर हैं, किन्तु अब जब शराब घोटाले और दिल्ली सरकार के अधिकारों के विषय पर आप संकट में है तब वह कांग्रेस से समर्थन चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और राहुल गांधी से समय मांगा। समय देने की बात तो दूर, कांग्रेस इस विषय पर किसी भी प्रकार की जल्दी में नही दिखती है।

चंद्रबाबू और जगनमोहन में से किसे चुनेगी भाजपा

यदि भाजपा विरोधी अन्य दलों की बात करें तो संसद भवन के कार्यक्रम में बसपा, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस ने सहभागिता की। अब यह दल भाजपा के विरोध में नहीं हैं, ऐसा नहीं है। इस बात से इतना तो स्पष्ट है कि वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए या तीसरे मोर्चे के गठजोड़ के साथ तो नही हैं। ऐसे में इस तरह के दल एक चौथे मोर्चे की रूपरेखा तैयार कर देते हैं। शिरोमणि अकाली दल से भाजपा का रिश्ता कृषि कानूनों पर टूटा था। यह कानून अंततः वापस हो गए तो अब भाजपा और अकाली दल में वैचारिक दुराग्रह तो नही है। अलग अलग चुनाव लड़कर दोनों दल अपनी अपनी सीमाओं का एहसास भी कर चुके हैं। जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है उसके बाद वह अब एनडीए के साथ जाएंगे। चन्द्रबाबू नायडू ने राष्ट्रिय महत्वकांक्षा दिखाते हुये पूर्व में एनडीए को छोड़ दिया था। इसका खामियाजा उन्होने उठाया था और वह जगनमोहन के हाथों आंध्र प्रदेश की सत्ता भी गंवा बैठे। अब वह फिर से एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। उनकी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाक़ात हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन और मोदी सरकार एक दूसरे की मदद तो करते हैं किन्तु सार्वजनिक रूप से साथ नही आते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू का भाजपा के साथ जाना संभव विकल्प है। एक महत्वपूर्ण नाम उड़ीसा के नवीन पटनायक का है। पांच बार मुख्यमंत्री बन चुके नवीन पटनायक को राष्ट्रिय राजनीति में कांग्रेस और भाजपा दोनों की आवश्यकता नही है किन्तु दोनों ही दलों को उनकी आवश्यकता रहती है। उत्तर प्रदेश में बसपा की स्थिति असपष्ट रहती है। पिछली बार 2019 में वह अपनी धुर विरोधी सपा के साथ चुनाव लड़ी थी।

संयुक्त विपक्ष की कोशिश में कुछ

मोदी विरोधी विपक्षी मोर्चा की कवायद

आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा विरोधी मोर्चाबंदी की जारी कवायद ओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर संतुलित होकर विचार करना आवश्यक है। कुछ महीने पूर्व तक इन गतिविधियों में संपूर्ण सक्रियता से बचने की कोशिश करने वाले राकांपा प्रमुख शरद पवार अब इसका एक महत्वपूर्ण चेहरा बन रहे हैं। शरद पवार ने भाजपा विरोधी संयुक्त विपक्षी मोर्चा की तैयारी पर तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। एक, विपक्षी मोर्चा का कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना आवश्यक नहीं है। दूसरे, हम भाजपा के विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे, 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में रणनीति बनेगी जिसमें संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार होगा। ये तीनों बातें ऐसी नहीं है जिन पर पहले भाजपा विरोधी किसी नेता ने बयान न दिया हो। हां, एक साथ तीनों बातें पहली बार किसी बड़े नेता की ओर से कही गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ने के बाद लगातार भाजपा के विरुद्ध विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा करने पर जोर दिया है। पटना बैठक उन्हीं की पहल पर आयोजित हो रही है। जब से विपक्षी एकता की बात हुई है आम लोग भी यह प्रश्न उठाने लगे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर विपक्ष का चेहरा कौन होगा? विपक्ष के किसी नेता के पास इसका सहमतिकारक उत्तर नहीं होता। शरद पवार ने 1977 की चर्चा करते हुए कहा है कि उस समय भी विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था लेकिन जनता पार्टी चुनाव जीती और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नेतृत्व विहीन भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के मायने क्या हैं?

हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय से उसके राजनीतिक और गैर राजनीतिक विरोधियों के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उत्साह और उम्मीद पैदा हुई है। भाजपा विरोधी पार्टियों और नेताओं को लगने लगा है कि अगर वे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में पराजित किया जा सकता है। नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं कि अगर मिलकर लड़े और भाजपा के विरुद्ध विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हो तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। पर राजनीति और चुनाव कल्पना का नहीं यथार्थ का विषय है। कोई नेता या नेताओं का समूह किसी समीकरण या राजनीतिक तस्वीर की कल्पना कर ले उससे वह यथार्थ में बदल जाए आवश्यक नहीं। वर्तमान भारतीय राजनीति का सच यही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के समानांतर विपक्ष के पास कोई एक नेता नहीं। आप उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम पूरे देश में चले जाइए, आम जनता के अंदर उनकी विश्वसनीयता का अनुभव आपको हो जाएगा। यहां तक कि जिन राज्यों में भाजपा का जनाधार मजबूत नहीं है और उसे वोट नहीं मिलता वहां भी लोगों का बड़ा समूह आपको प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही अपनी पसंद बता देता है। दूसरे, संगठन और जनाधार के स्तर पर भी भाजपा देश की इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति है जिसके समानांतर राष्ट्रीय स्तर पर कोई या दो-चार दलों का समूह नहीं टिक सकता। भाजपा विरोधी दलों और नेताओं को इस जमीनी यथार्थ का आभास है तभी वे अपने कटु मतभेदों को परे रखकर एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। 1977 की तरह पार्टियों का विलय कर एक पार्टी बनाने की बात तो दूर अभी तक इन कवायदों के ऐसे ठोस परिणाम नहीं आए हैं जिनसे वाकई यह लगे कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को भारत को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त विपक्ष की कड़ी चुनौती मिलने वाली है। क्यों?

1977 का उदाहरण देने वाले भूल रहे हैं कि आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में साथ आने, जेल में बंद रहने और यातनाएं भुगतने के कारण विपक्षी नेताओं का आपस में संवाद और संबंध तब काफी गहरा हो चुका था। दूसरे, आंदोलन में जयप्रकाश नारायण सदृश दलीय स्वार्थों से परे एक ऐसा विराट व्यक्तित्व था जिसके प्रति सबके मन में सम्मान का भाव था। यानी जयप्रकाश नारायण विपक्षी एकता और जनता पार्टी के गठन के मुख्य कारक थे। दक्षिण भारत के परे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध कई कारणों से व्यापक आक्रोश था। 2023 - 2024 की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल अलग है। कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में पराजय के आधार पर अगर विरोधी दल और नेता यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरुद्ध जनता में गुस्सा है तो कहना पड़ेगा कि विरोध की मानसिकता में वे जमीनी यथार्थ नहीं देख पा रहे। किसी भी विश्वसनीय सर्वेक्षण में जनता के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध ऐसे किसी आक्रोश का प्रकटीकरण नहीं हुआ है। हां,

भाजपा और संगठन परिवार के अंदर असंतोष अवश्य दिखा है जो स्थानीय नेताओं मंत्रियों और पार्टी को लेकर है। दोनों राज्यों में भाजपा अपने आंतरिक कलह के कारण ही पराजित हुई। जब पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक समूह जगह-जगह उदासीन हो जाए या पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध काम करें तो चुनाव जीतना मुश्किल होता है। भाजपा के लिए यह चिंता का विषय है और इसे संभालने के लिए उसे काम करना होगा। किंतु विधानसभा चुनाव में प्रकट असंतोष इसी रूप में लोकसभा चुनाव में दिखेगा इसकी संभावना नहीं है। कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध पार्टी और संगठन परिवार में असंतोष और आक्रोश कहीं नहीं दिखा है। सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म इतिहास, राष्ट्र आदि को लेकर जिस तरह का जागरण हुआ है विपक्ष की कोई पार्टी भाजपा की तुलना में उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है । देश के बड़े समूह की मानसिकता यही है कि व्यक्तिगत जीवन में थोड़े कष्ट भी उठाने पड़ें तो हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, धर्म-संस्कृति आदि के मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते। ऐसी घनीभूत मानसिकता वालों के सामने वर्तमान राजनीति में एकमात्र विकल्प इस समय भाजपा ही है। इसी कारण कर्नाटक में इतना असंतोष होने के बावजूद भाजपा के मतों में कमी नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर काम करने के साथ सामाजिक न्याय पर ऐसे ठोस काम किए हैं जिनसे बड़ा समर्थक वर्ग कायम हुआ है। आप आदिवासियों और दलितों के बीच जाकर पूछिए कि किसे वोट देंगे तो अधिकतर बिना सोचे मोदी का नाम लेंगे। चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी एक दिन भी बैठी नहीं है। आप देख लीजिए जनता तक पहुंचने के देशव्यापी कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें शीर्ष से लेकर नीचे स्तर के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं।

इसकी तुलना में विपक्ष कहां खड़ा है? राज्यों के स्तर पर कई पार्टियां, नेता और गठबंधन मजबूत हैं और वे कुछ अभियान भी चला रहे हैं, किंतु एक राज्य में किसी पार्टी, गठबंधन या सरकार के अभियान से दूसरे राज्य में भाजपा विरोधी पार्टियों को लाभ मिल जाए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को या फिर तेलंगना में के चंद्रशेखर राव को या ये नेता बिहार में इन्हें सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। पटना की बैठक से भाजपा के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा हो भी जाए तो कई राज्यों में इसको जमीन पर उतारना संभव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ सकती। ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस अगर वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, उनका समर्थन करती है तो वह उनका समर्थन भूल जाए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली तथा पंजाब में कांग्रेस के साथ सीटों पर समझौता कैसे करेगी? महाराष्ट्र में राकांपा, कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के संयुक्त उम्मीदवार के विरुद्ध विपक्ष का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो यह संभव है। इसी तरह की स्थिति बिहार में होगी। किंतु तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का भारत राष्ट्र समिति से या उत्तर प्रदेश में सपा का बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन होना कठिन है। कांग्रेस मध्यप्रदेश, राजस्थान छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसी विपक्षी दल के साथ सीटों पर समझौता करेगी इसकी भी कल्पना कठिन है। तो निष्कर्ष यह कि शरद पवार , नीतीश कुमार या ऐसे कुछ नेताओं के बयान वर्तमान राजनीति की जमीनी वास्तविकता नहीं हैं। आम मतदाताओं को इसका आभास है कि विपक्षी नेताओं के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का अभाव है तभी वह किसी को प्रधानमंत्री पद के रूप में अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव परिणाम से केवल इतना बदला है कि कई विपक्षी दलों और नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के विरुद्ध तत्काल तल्ख बयान बंद कर दिया है। कांग्रेस ने जैसे ही गठबंधन न होने पर विपक्ष की मजबूती वाले राज्यों में उम्मीदवार उतारे उसके विरुद्ध वैसे ही बयान आएंगे जैसे पहले आ रहे थे। इससे आम मतदाताओं के बीच क्या संदेश जाएगा बताने की आवश्यकता नहीं। बार-बार 1977 की याद दिलाने वाले न भूलें कि जयप्रकाश नारायण जैसे विराट व्यक्तित्व के रहते हुए भी जनता पार्टी की अंदरूनी कलह में ढाई साल में ही सरकार की जीवन लीला समाप्त हो गई। आम मतदाताओं के अंदर यही धारणा बनी कि न विपक्षी पार्टियों एकजुट रह सकती है न सरकार चला सकती हैं। गैर कांग्रेस में केवल भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाई है। देश के लोगों ने विपक्षी गठबंधन वाली अस्थिर सरकारों का दौर देखा और परिणाम भुगता है। किसी दल से न जुड़े लोगों को जब तक यह विश्वास न हो जाए कि जिन्हें वे मत दे रहे हैं वो पूरे कार्यकाल तक सरकार चला पाएंगे तब तक राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से गैर भाजपा दलों के उम्मीदवारों को मत भी नहीं देंगे। क्या नीतीश कुमार, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव, एम के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी आदि जनता को यह विश्वास दिलाने में सक्षम हैं? इसका उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं।

- अवधेश कुमार

गांठे भी हैं। नितीश, ममता और शरद पवार जैसे क्षत्रप चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी भूमिका सीमित करे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली को छोड़कर कांग्रेस अन्य राज्यों में दूसरे स्थान पर रहे दल के लिए छोड़ दे। इस रणनीति के अंतर्गत 543 में से 474 सीटों पर भाजपा के विरुद्ध एक ही साझा उम्मीदवार उतारने की योजना है। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 244 सीट ही आएंगी। अब एक राष्ट्रिय दल इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कैसे तैयार होगा, यह बड़ा प्रश्न है। शेष सीटों पर कांग्रेस का संगठन कैसे अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेगा ? हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस इस फार्मूले पर शायद ही तैयार हो। पर इस फार्मूले से एक बात तो स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के प्रति क्या सोच रखते हैं। क्षेत्रीय दल भाजपा से लड़ना चाहते हैं और इस लड़ाई में कांग्रेस का सहयोग भी चाहते हैं किन्तु कांग्रेस का खोया जनाधार उसके पास वापस जाते देखना नही चाहते हैं। क्षेत्रीय दल जानते हैं कि भाजपा को हराने के साथ साथ उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस की कमजोरी पर ही टिका है। भाजपा विरोध के बाद अगर कांग्रेस मजबूत हो गयी तो क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। फिर कांग्रेस और भाजपा ही आमने सामने होंगे।

विपक्षी एकता का उम्मीदवार कौन

विपक्षी एकता की पूरी कवायद के बाद एक बड़ा प्रश्न यह है कि संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। विपक्ष जानता है कि यदि उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया तो वह मोदी के सामने नहीं टिकेगा। मोदी के क़द के समकक्ष कोई नेता वर्तमान में नहीं है। इसलिए विपक्षी दल नेता के नाम से बच रहे हैं। यह सभी क्षेत्रीय

दलों के लिए भी मुफीद स्थिति है। इसके द्वारा सभी दलों के लिए विकल्प खुले रहते हैं। विपक्षी एकता के सूत्रधारों में एक शरद पवार का कहना है कि आपातकाल के बाद हुये चुनावों में भी विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं था किन्तु उन्होने सत्ताधारी दल को हरा दिया था। जबकि उस समय की परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति की तुलना ही अभी बेमानी है। 1977 में आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने और जेल में रहने के कारण विपक्ष के नेताओं के बीच संवाद गहरा गया था। जनता में आक्रोश था। सिर्फ इन्दिरा के विरोध के कारण नहीं बल्कि जय काश नारायण जैसे बड़े नाम के कारण दलों में समन्वय था। जयप्रकाश नारायण पूरे उत्तर भारत में व्यापक जनप्रभाव रखते थे। वहीं दक्षिण भारत के परे इन्दिरा गांधी के प्रति जबरदस्त आक्रोश था। वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी न तो आपातकाल के कारण जनता में आक्रोश है और नही विपक्षी दल जेलों में बंद हैं। जिस ईडी और सीबीआई की बात कहकर वह मोदी को घेरते हैं वह विषय जनता में र्प्भावी नहीं हैं। जनता इन दलों और इनके नेताओं को भ्रष्टाचारी मानती है। मोदी के विरुद्ध उसके वोटर में कोई दुराग्रह नहीं है। इसलिए बिना किसी नेता और राष्ट्रिय विमर्श के सिर्फ 1977 वाली परिस्थिति से तुलना निष्प्रभावी हो जाती है।

आज का राजनीतिक सच यह है कि मोदी के समकक्ष कोई चेहरा विपक्ष के पास है ही नहीं। जिन राज्यों में भाजपा कमजोर है और कांग्रेस मजबूत है, उन राज्यों की जनता भी मोदी से जुड़ी दिखती है। जिन राज्यों में भाजपा को वोट नहीं मिलता है वहां की जनता भी मोदी को अपनी पसंद बता देती है। इसके साथ ही अगर देखें तो 2014 के बाद से भाजपा ने स्वयं का संगठन बहुत मजबूत कर लिया है। उसके स्तर का संगठन और बूथ स्तर तक भाजपा की पहुंच उसके विपक्षी दलों के पास नहीं है। भाजपा का संगठन अब इस तरह व्यापक स्वरूप ले चुका है जैसे कभी बंगाल में वामपंथियों का संगठन होता था। 1977 की तर्ज पर सब दलों के विलय करके एक दल बनाने की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुयी है। अभी तो विपक्षी एकता की बात करने वाले सभी दल सिर्फ स्वयं के अस्तित्व के लिए जमीन तलाश रहे हैं। उसके दूसरी तरफ अगर देखें तो भाजपा ने भारतीयता के आधार पर राजनीति करके जनता की नब्ज पकड़ ली है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संस्कृति और धर्म इतिहास राजनीति की जो इमारत भाजपा ने खड़ी कर दी है उसे न राहुल गांधी समझ पा रहे हैं और न ही कांग्रेस। कुछ क्षेत्रीय दल इस बात को समझ रहे हैं किन्तु बिना कांग्रेस के इस बात को समझें विपक्षी एकता का भला नहीं होने वाला है। भारत में पिछले एक दशक की राजनीति का जनता पर प्रभाव यह है कि अब जनता थोड़ा कष्ट उठाने को तो तैयार है किन्तु वह भारतीयता और भारत से जुड़े विषयों पर समझौते को तैयार नहीं है। इसलिए जब क्षेत्रीय दल जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जनता के बीच वह विमर्श का विषय नहीं बन पाता है।

कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का परंपरागत वोट दलित अब किधर है ?

संयुक्त विपक्ष सिर्फ सभी दलों के इकट्ठा होने से नहीं बनेगा बल्कि उसके लिए वोट बैंक के आंकड़े को भी समझना होगा। आजादी के बाद से दलित वोटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। किसी अन्य दल की तरफ जाने के बारे में दलित सोंच भी नहीं सकता था। इसके बाद इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो सहानुभूति लहर में सब वोट बैंक सिर्फ राजीव के पक्ष में नजर आया। राजीव गांधी के प्रमुख सिपहसालार वी पी सिंह ने बोफोर्स दलाली के मुद्दे पर बगावत कर दी। अपना नया दल जनता दल नाम से बना लिया। अपने लिए वोट बैंक की तलाश कर रहे वी पी सिंह ने सबसे पहले मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करके आरक्षण की शुरुआत की। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुये एवं हिंसा के साथ कई लोगों की जाने चली गईं। इसके बाद वीपी सिंह ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में 1990 में संशोधन किया। इस संसोधन के बाद यह व्यवस्था आरंभ हो गयी कि आरक्षित जातियों द्वारा शिकायत करने मात्र से ही गिरफ्तारी हो जाएगी। कोई भी जांच एवं अन्य प्रक्रियाएं गिरफ्तारी के बाद शुरू होंगी। यह भारत में सवर्ण और दलित के बीच तलवारें खिंचने की शुरुआत थी। मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करने एवं अधिनियम में संसोधन के जरिये वीपी सिंह दलित वोटों को जनता दल का वोट बैंक बनाना चाह रहे थे।

चूंकि उस दौरान राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के द्वारा हथियाए जाने के कारण हिन्दू भाजपा की तरफ खिंच रहा था और शाहबानों प्रकरण के बाद मुस्लिम कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक था इसलिए वीपी सिंह के द्वारा राजनीति कठिन थी। दलित कार्ड के द्वारा उन्होने भाजपा और कांग्रेस दोनों के हिस्से से कुछ वोट बैंक चुराने का कयास लगाया था। अपने लिए नए सामाजिक समीकरण बनाने के क्रम में उन्होने पहले संसद के केन्द्रीय कक्ष में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई और बाद में उन्हे मरणोंपरांत भारत रत्न दिया। यह सब इतनी तेजी के साथ घटित हुआ कि कांग्रेस को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसका दलित जनाधार एक झटके में उसके हाथ से फिसल गया। वह न तो वीपी सिंह का समर्थन कर पा रही थी और न ही उसका विरोध। समर्थन और विरोध दोनों से राजनैतिक नुकसान तय था। वीपी सिंह ने पहले बोफोर्स और बाद में दलित वोट बैंक के जरिये कांग्रेस को इतने बड़े झटके दिये कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तिलमिला कर रह गयी। बाद में कांग्रेस द्वारा वीपी सिंह सरकार के एक मंत्री चन्द्रशेखर को तोड़ लिया गया और उनको समर्थन देकर भारत का प्रधानमंत्री बनवाया गया। इसके बाद धीरे धीरे वी पी सिंह का राजनैतिक पतन हो गया। संयुक्त विपक्ष की कवायद के बीच भाजपा ने दलित और पिछड़े वोटों पर अच्छी पकड़ बना ली है। भाजपा ने गैर यादव और गैर जाटव के फोर्मूले के द्वारा क्षेत्रीय दल सपा और बसपा के एक बड़े वोट बैंक को तोड़ लिया है।

मायावती ने 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निकाला था। ब्राह्मण वोटों के सहारे सत्ता प्राप्त करने के कारण उनके तेवर तब नर्म थे। सत्ता संभालते ही उन्होने कहा कि एससीएसटी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए उन्होने इसमे संशोधन करते हुये कहा कि हत्या और दुष्कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य अन्य मामले में दलित उत्पीड़न पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। वर्तमान में भारत की राजनीति और खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में दलित एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। देश की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं। देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दलित एवं आदिवासियों का निवास है। भारत की लोकसभा में अनुसूचित

जातियों एवं जनजातियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मायावती का रुझान किसकी तरफ है यह समझना मुश्किल होता है। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों में जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ तब मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और उसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती का गठबंधन सपा के साथ हुआ तो सपा को बड़ा नुकसान हुआ और मायावती फिर से पुनर्जीवित हो गईं। इस बीच भाजपा ने भी बड़ा फायदा उठाया।

विपक्षी खेमा एक बात को बार बार कहता जा रहा है कि देश का मोदी से मोहभंग हो चुका है। अपनी बात को मनवाने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष ईवीएम को मोदी की जीत का आधार बताता है। पर जब किसी उपचुनाव या किसी राज्य में भाजपा की हार होती है तो उसे मोदी से मोहभंग के रूप में प्रचारित-प्रसारित किया जाता है। विपक्ष की इन्ही हरकतों की वजह से ब्रांड मोदी धीरे धीरे मजबूत हो गया। धीरे धीरे दलित वोट क्षेत्रीय दलों से छिटक कर भाजपा में समाहित हो गया। दलित, पिछड़े और मुस्लिम की राजनीति करने वाले दल नेपथ्य में चले गए। कभी कांग्रेस को कमजोर समझने वाले दल अब कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद से उसको अलग रखने की स्थिति में नहीं बचे हैं। यह क्षेत्रीय दल स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई को कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई दिखाकर मोदी विरोध को भुनाना चाहते हैं।

मोदी बनाम संयुक्त विपक्ष

मोदी के विरोध में बनने वाले संयुक्त विपक्ष की स्थिति में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा घाटा उठाना पड़ेगा। 16 राज्यों में कांग्रेस पर इसका प्रभाव होगा। सात राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के लिए स्थान छोडना होगा तो नौ राज्यों में अपने दम पर सीधे भाजपा से जूझना होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें छोडनी होंगी। इन राज्यों से 269 सीटों का कांग्रेस को नुकसान होगा। यदि इन राज्यों से कुछ सीटें कांग्रेस को मिल भी गईं तो इनकी संख्या डेढ़ दर्जन से ज़्यादा नहीं होगी। इसके साथ ही कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर भाजपा के सामने होगी। इन नौ राज्यों से 214 सीटें आती हैं। इस फार्मूले में देखें तो कांग्रेस जैसा बड़ा राष्ट्रिय दल बहुमत के आंकड़े के बराबर सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस के साथ एक समस्या यह भी है कि विपक्षी एकता में ज़्यादातर ऐसे दल शामिल हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। यदि राज्य में कांग्रेस उनके लिए सीट छोडती है तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विपक्षी एकता की बात करने वाले एक बात को और नहीं समझ पा रहे हैं कि अधिकांश सीटों पर त्रिकोणिय मुकाबला होने से वह भाजपा को हरा सकते हैं। एक के सामने एक प्रत्याशी होने का नुकसान 2017 और 2019 में क्षेत्रीय दल उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा ने गठबंधन करके भाजपा को ही मजबूत किया। भाजपा के सामने सिर्फ एक दल होने की स्थिति में चुनाव सीधे सीधे हिन्दू मुस्लिम वोटों पर केन्द्रित हो जाता है।

अब यदि कर्नाटक में देखें तो हालांकि वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की किन्तु सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद भाजपा के मत प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। भाजपा का मतदाता उसके साथ ही जुड़ा है। मुस्लिम वोट बैंक ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया। जेडीएस ज़्यादा मुस्लिम वोटों में सेंध नहीं लगा सका। जिस कर्नाटक में अभी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लोकसभा चुनाव में वही कर्नाटक भाजपा के खाते में जाता दिख रहा है। मोदी का प्रभाव लोकसभा चुनावों में ज़्यादा जोरदार तरीके से काम करता है। मोदी सरकार ने हिन्दुत्व के साथ साथ सामाजिक न्याय के विषयों पर ऐसा काम किया हुआ है कि एक बड़ा समर्थक वर्ग पैदा हो गया है। जैसा कि मेरा हमेशा से यह कहना रहा है कि भारत में 10-15 करोड़ का एक वोटर मोदी के नाम पर लोकसभा में वोट देता है। आदिवासियों और दलितों में भाजपा ने अब गहरी पैठ बना ली है। पहले एक दलित रामनाथ कोविन्द और फिर एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने कई राज्यों में अपनी जड़ें गहरी की हैं। इसकी तुलना में देखें तो विपक्ष अभी कहां है ? कहीं कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का रास्ता रोके खड़ी है तो कहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस का रास्ता रोक रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि कांग्रेस बंगाल में वामपंथियों के साथ जाये। आप नहीं चाहती कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। यह सब बात इस बात का संकेत देती हैं कि विपक्षी नेताओं में एक दूसरे के प्रति सिर्फ समन्वय का अभाव नहीं है बल्कि सम्मान का भी अभाव है। यही कारण ही किसी एक दल के नेता को अन्य दल के लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं हैं। चूंकि जनता ने गठबंधन के दौर वाली सरकारें भी देखी हैं और उनका कार्यकाल के दौरान उनके क्रियाकलाप भी, इसलिए जनता राजनीतिक अस्थिरता वाले विपक्ष की तरफ नहीं जाती दिखती है। संयुक्त विपक्ष तभी जनता के मापदण्डों पर खरा उतरेगा जब वह इस बात को स्थापित कर देगा कि वह स्थिर सरकार देने में सक्षम है। अन्यथा की स्थिति में 2024 में संयुक्त विपक्ष कुछ खास करने नहीं जा रहा है। ■

ऑनलाइन गेमिंग एप पर धर्मांतरण का खतरनाक खेल

आरोपी गिरफ्तार, लेकिन खतरा बरकरार

● मृत्युंजय दीक्षित

आनलाइन गेमिंग एप वैसे तो कई प्रकार से समाज के लिए नुकसानदेह हैं किन्तु कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों के द्वारा इनका प्रयोग धर्मांतरण के लिए किया जाना एक बड़े दुश्चक्र के रूप में सामने आया है । विगत दिनों हुए एक बड़े खुलासे में आनलाइन गेमिंग एप पर धर्मांतरण कराने वाले एक गैंग का मुख्य आरोपी शहनवाज खान उर्फ बद्दो महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया गया जो अब 15 जून तक पुलिस रिमांड पर है। यही नहीं पुलिस ने मोबाइल सिम उपलब्ध करवाने वाले दोस्त तौफीक और आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धर्मांतरण का आरोपी बद्दो जिस प्रकार के रहस्य उजागर कर रहा है वो चकित करने वाले हैं । अब पुलिस यह पता कर रही हे कि यह गिरोह कितना बड़ा है तथा उसके तार कहां- कहां तक फैले हैं।

ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से धर्मांतरण करने का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद जिले में एक युवक घर वालों से चोरी छिपे मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लग गया। परिवार को जब पता चला तो उन्होंने मुंबई के एक व्यक्ति समेत एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि आरोपित पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग एप के सहारे धर्मांतरण की मुहिम चला रहा है।

राजनगर निवासी एक व्यक्ति का कहना है कि उनका नाबालिग बेटा पिछले काफी समय से पूरे परिवार के साथ अजीब तरह का व्यवहार कर रहा था। वह प्रतिदिन पांच बजे जिम जाने के लिए निकल जाता था और कई- कई घंटे बाद वापस आता था।संदेह होने पर उन लोगों ने बेटे का पीछा किया तो पता चला कि वह मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। उन्होंने बेटे से बात की तो उसने इस्लाम धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर बताया। उसने कहा कि वह मन से इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका है। इस पर उन्होंने बेटे के मोबाइल फोन व लैपटाप की जांच की तो उसमें इस्लाम धर्म की सामग्री मिली। जांच में पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से उसकी पहचान मुंबई के रहने वाले बद्दो नाम के व्यक्ति से हुई थी। दो साल पहले युवक ने बद्दो से कंप्यूटर के कुछ पार्ट खरीदे थे जिसके बदले में युवक ने बद्दो को 20 हजार का भुगतान किया था। वह युवक तभी से बद्दो के प्रभाव में आ गया था। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा बद्दो से कई-कई घंटों तक बात करता है और उसकी बात कुछ अन्य नंबरों पर भी होती है। परिजन काफी डरे हुए हैं तथा उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है।

एक आरोपी गिरफ्तार

इंटर पास छात्र के आनलाइन गेमिंग एप से धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र के अलावा दो किशोर व एक युवक का मतांतरण कराने के साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस ने अब्दुल रहमान को मतांतरण कराने का आरोपी बनाया है क्योंकि चारों मतांतरित नियमित रूप से वहां ही नमाज पढ़ने जाते थे। इमाम का कहना है कि उसे दो माह पूर्व ही मस्जिद कमेटी से निकाला जा चुका है जबकि पुलिस जांच में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं।

डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल ने बताया कि छात्र के मोबाइल से मिले सात नंबरों में से एक नंबर अब्दुल का था। छात्र अब्दुल से करीब सात-आठ माह पूर्व वह जामा मस्जिद में ही मिला था। अब्दुल ने व्हाटसएप पर उसको इस्लामिक सामग्री भेजनी शुरू कर दी थी। वह छात्र पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाता था।

पुलिस का शुरुआती जांच में ही कहना था कि यह बहुत ही शातिर गिरोह है जिसके सदस्य इन किशोरों से कहते थे कि आयत पढ़ोगे तो आनलाइन गेम में लगातार जीत मिलेगी । यही बात बद्दो और इसके गिरोह के साथी एप पर गेम खेलने के दौरान हारने वाले किशोरों को बोलते हैं। उनकी बातों में आकर जो किशोर ऐसा करने

पर राजी हो जाता है उसको गिरोह के सदस्य आयत पढ़ने के तरीके बताते हैं। बाद में उनका विश्वास जीतकर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिये प्रेरित करते हैं। ऐसा करके बद्दो कई लोगों को फंसा चुका है। गिरोह के सदस्यों ने गेमिंग व चैटिंग एप पर हिंदुओं के नाम से आईडी बना रखी है जिससे कोई उन पर संदेह न करे। गिरोह के तार विदेशों से भी जुड़े हैं।

प्रयागराज से भी गेमिंग एप के माध्यम से एक 17 वर्षीय नाबालिग का धर्मांतरण करवाने का समाचार सामने आया है। ब्राहमण परिवार के 17 वर्षीय बेटे ने अचानक पूजा पाठ करना बंद कर दिया था जो कभी मंदिर जाता था अब मजार पर जाकर वहां पर उर्दू में लिखी इबारत को पढ़कर चूमने लगा। मुस्लिम दोस्तों के कहने पर उसने अपना जनेऊ भी तोड़कर फेंक दिया। उस बालक की हालत यह हो गयी थी कि वह जालीदार टोपी पहनने लगा और मुस्लिम कव्वाली सुनने जाने लगा।

काल्विन अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉ. ईशान्या राजा ने बताया कि मां-बेटे से बात करने में यह बात स्पष्ट हो गयी है कि किशोर का धर्मांतरण मोबाइल गेम की आड़ में कराया जा रहा है।

धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का व्यापक दायरा पाक तक फैला है जाल

आनलाइन गेमिंग एप के सहारे नाबालिग युवकों का धर्मांतरण कराने के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे -वैसे नये खुलासे हो रहे हैं। अब तक पांच राज्यों के युवकों का धर्मांतरण कराये जाने की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना

यह तो बिलकुल स्वीकार्य नहीं!

बड़ी अजीब बात है, सरकार न जाने क्यों चुप है, यह विडंबना ही है कि स्वतंत्र और संप्रभु भारत में भी औरंगजेब के 'फैन क्लब' हैं! सोशल मीडिया पर इस नाम के समूह सक्रिय हैं और जो लगातार ऐसी-वैसी पोस्ट लिख रहे हैं, यह पराकाष्ठा तो है ही और अस्वीकार्य भी है।

'औरंगजेब आप सबका बाप' जुमले के बैनर और पोस्टर लिखे और लहराए जा रहे हैं। देश क़ा दुर्भाग्य है कि इस आजाद देश में एक तबका आज भी औरंगजेब को अपना 'नायक' मानता है। अदालतों के भीतर की बहस के दौरान ऐसी दलीलें दी जा रही हैं- औरंगजेब क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह आक्रांता भी नहीं था। उसके कालखंड के दौरान मंदिरों और अन्य हिंदू धर्मस्थलों को ध्वस्त नहीं किया गया।

ऐसी दलीलों पर हैरानी तो होती है साथ ही हंसी भी आती है कि भारत के कुछ हिस्से आज भी मजहबी, मानसिक तौर पर गुलाम है। यूं तो हम सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर हैं और हमारा संविधान भी यही सिखाता है, लिहाजा संप्रदाय के नाम पर भड़काए गए दंगों और हिंसक उपद्रवों पर टिप्पणी करने से परहेज करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर, अहिल्या नगर आदि इलाकों में, औरंगजेब के महिमा-मंडन और आपत्तिजनक हिंदू-विरोधी जुमलों के मद्देनजर, जो सांप्रदायिक तनाव भड़का, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

आज का सवाल यह है कि यह सांप्रदायिक विभाजन का सिलसिला कब थमेगा? औरंगजेब का कालखंड बीते 300 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन औरंगजेब को आज भी उसे जिंदा रखने की कोशिशें जारी हैं। जब विवादास्पद दुष्प्रचार किया गया, तो कुछ हिंदू संगठनों ने 'बंद' का आह्वान किया। नतीजतन सांप्रदायिकता भिड़ पड़ी और पुलिस को लाठीचार्ज कर माहौल को सामान्य करना पड़ा। सवाल यह है कि 21वीं सदी के भारत में औरंगजेब क्यों और किस तरह प्रासंगिक है? मुगल बादशाहत को खत्म हुए सदियां बीत चुकी हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें भी भारतीयों ने हिला दी और आज हमारा भारत एक आजाद मुल्क हैं।

मुर्दों को इतिहास में जिंदा रहने दें और अतीत को दर्ज करते रहें, लेकिन औरंगजेब को 'देश का बाप' मानने और प्रचारित करने का औचित्य क्या है? मौजूं सवाल यह है क्या मुगल भारतीय मुसलमानों के वंशज थे? मुगल बादशाहों ने अपनी ही जमात पर भी खूब जुल्म ढाए थे, क्या मुसलमानों को ये तथ्य ज्ञात नहीं हैं? वाराणसी की कथित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद विवाद अदालतों के विचाराधीन हैं। दोनों ही ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों का विध्वंस किया और मस्जिदें बनवाई थीं। बदकिस्मती है कि भारतवंशियों को आज भी अपने आस्था-स्थलों के संरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लडऩी पड़ रही है।

इतिहास में ब्यौरे दर्ज हैं कि औरंगजेब ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ही 63 हिंदू मंदिरों को तुड़वा कर 'मलबा' बनवा दिया था। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर ही काशी का मंदिर तोड़ा गया और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। मालवा की तत्कालीन महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जिसे आज हम 'काशी विश्वनाथ मंदिर' के तौर पर जानते हैं। औरंगजेब कितना अमानवीय अथवा क्रूर था, उसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। उसने सिखों के नवें गुरु तेगबहादुर जी का सिर धड़ से अलग करवा दिया था। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा उसी स्थान पर बना है, लेकिन गुलाम मानसिकता देखिए कि पास में ही 'औरंगजेब रोड' भी बनी है। औरंगजेब ने हमारे प्राचीन देश पर करीब 50 साल हुकूमत की। उस दौरान कितने मंदिर तोड़े होंगे, कितनी हत्याएं की होंगी, इसका ठोस, प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन औरंगजेब का बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां सरीखे बादशाहों की फेहरिस्त में आज स्मरण करने का औचित्य क्या है? क्या उसका हिंदुस्तान के गौरव और गर्व के लिए कोई योगदान है।

आर.के. सिन्हा

नेताजी सुभाष जीवित होते तो देश का बंटवारा न होने देते

क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो पाकिस्तान कभी बन पाता? यह बहस लंबे समय से चल रही है। इस विषय पर इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद भी रहे हैं। अब इस बहस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि 'अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता।' क्या वे मोहम्मद अली जिन्ना को समझा पाते कि भारत के बंटवारे से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा? यह सवाल अपने आप में काल्पनिक होते हुए भी महत्वपूर्ण हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल में ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। जिन्ना ने 23 मार्च, 1940 को लाहौर के बादशाही मस्जिद के ठीक आगे बने मिन्टो पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी घनघोर सांप्रदायिक सोच को प्रकट कर दिया था। जिन्ना ने सम्मेलन में अपने दो घंटे लंबे बेहद आक्रामक भाषण में हिन्दुओं को पानी पी पीकर कोसा था। कहा था– 'हिन्दू – मुसलमान दो अलग धर्म हैं। दो अलग विचार हैं। दोनों की परम्पराएं और इतिहास अलग हैं। दोनों के नायक अलग हैं। इसलिए दोनों कतई साथ नहीं रह सकते।' जिन्ना ने अपनी तकरीर के दौरान लाला लाजपत राय से लेकर दीनबंधु चितरंजन दास तक को अपशब्द कहे। बेशक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना के भाषण के अंश पढ़े होंगे।

डोभाल यह भी कहते हैं, 'नेताजी ने अपने जीवन में कई बार साहस दिखाया। उनके अंदर महात्मा गांधी को चुनौती देने का साहस भी था। वह भी तब जबकि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। फिर बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को भरी बहुमत से हरा कर कांग्रेस छोड़ दी थी। डोभाल ने आगे कहा, 'मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के ऐसे लोगों में बहुत कम समानताएं हैं, जिनमें धारा के खिलाफ बहने का साहस था और आसान नहीं था।'

सुभाष चंद्र बोस के रहते भारत का विभाजन नहीं होता। इस मसले पर बहस होती रहेगी। जिन्ना ने कहा था कि मैं केवल एक नेता को स्वीकार कर सकता हूं और वह सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी के महान प्रयासों पर कोई संदेह नहीं कर सकता, महात्मा गांधी भी उनेक प्रशंसक थे, लेकिन लोग तो अक्सर आपके परिणामों के माध्यम से आपको आंकते हैं। तो क्या सुभाष चंद्र बोस का पूरा प्रयास व्यर्थ गया। इतिहासकार तो नेताजी के प्रति घोर निर्दयी रहें हैं।

पाकिस्तानी लेखक फारूक अहमद दार ने अपनी किताब 'जिन्नाज पाकिस्तान:फोरमेशन एंड चैलेंजेंस' में लिखा है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के हक में प्रस्ताव पारित करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से जिन्ना से आग्रह किया था कि वे अलग देश की मांग को छोड़ दें। उन्होंने जिन्ना को भारत के आजाद होने के बाद पहला प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दिया था। कुछ इस तरह का प्रस्ताव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी. राजागोपालचारी ने भी जिन्ना को दिया था। जाहिर है कि जिद्दी जिन्ना ने नेताजी की पेशकश पर सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। जिन्ना तो भारत को तोड़ने पर आमादा था। इसके बाद का इतिहास सबको मालमू है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पेशावर के रास्ते देश से अफगानिस्तान के रास्ते बाहर चले गए, भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति दिलवाने के लिए। वे दुनिया के अनेक देशों में रहे। उन्होंने वीर सावरकर और रस बिहारी बोस की प्रेरणा से आजाद हिन्द फौज का गठन किया। जाहिर है कि देश से बाहर जाने के बाद वे जिन्ना या मुस्लिम लीग की गतिविधिवियों से लगभग दूर हो गए। अफसोस कि उनकी एक विमान हादसे में 1945 में मृत्यु हो जाती है।

यहां पर कुछ सवाल मन में तो आते हैं। जैसे कि अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो जिन्ना के 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया होती। जिन्ना ने 16 अगस्त,1946 के लिए डायरेक्ट एक्शन का आहवान किया था। एक तरह से वह हिन्दुओं के खिलाफ दंगों की शुरूआत थी। तब बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। लीग दंगाइयों का खुलकर साथ दिया था। उन दंगों में कोलकाता में पांच हजार मासूम मारे गए थे। मरने वालों में उड़िया मजदूर सर्वाधिक थे। फिर तो दंगों की आग चौतरफा फैल गई थी। बेशक, नेताजी

सुभाषचंद्र बोस जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ जनशक्ति के साथ सड़कों पर उतर जाते। वे कोलकाता के 1930 में मेयर थे। उन्हें कोलकाता के चप्पे- चप्पे की जानकारी थी। वे जिन्ना और मुस्लिम लीग के गुंडों का सड़कों पर मुकाबला करते। वे जुझारू नेता थे। नेताजी घर में बैठकर हालातों को देखने वालों में से नहीं थे। पर वे पहले ही संसार से विदा हो चुके थे।

जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आहवान के बाद मई, 1947 में रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के गुंडों ने जमकर हिन्दुओं और सिखों को मारा, उनकी संपति और औरतों की इज्जत लूटी। रावलपिंडी में सिख और हिन्दू खासे धनी थे। इनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। पर जिन्ना ने कभी उन दंगों को रूकवाने की अपील नहीं की। वे एक बार भी किसी दंगा ग्रस्त क्षेत्र में नहीं गए। डायरेक्ट एक्शन की आग पूर्वी बंगाल तक पहुंच गई थी। नोआखाली में हजारों हिन्दुओं का कत्लेआम हुआ था। उस कत्लेआम को रूकवाने के लिए महात्मा गांधी भी गए थे। वे दंगों को रूकवाने में मात्र कुछ हद तक ही हिन्दू बहुल इलाकों में ही सफल रहे थे। एक तरह से मुसलमानों की क्रूरता और नरसंहार का जवाब हिन्दू न दे पाये थे।

दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुसलमानों के बीच में जबरदस्त असर था। आजाद हिन्द सेना में उनके एक अहम साथी शाहनवाज खान थे। उनके अलावा भी आजाद हिन्द सेना में मुसलमानों की तादाद बहुत अधिक थी। नेताजी सुभाष की शख्सियत बेहद चमत्कारी और सेक्युलर थी। देश के बंटवारे का असर बंगाल और पंजाब पर ही हुआ। ये ही बंटे। बंगाल तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गृह प्रदेश था। इन दोनों राज्यों में मुसलमान और सिख उन्हें अपना नायक मानते थे। तो कह सकते हैं कि वे मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ी चुनौती तो अवश्य बनते।

बहरहाल, अजीत डोभाल ने एक महत्वपूर्ण बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तभकार और पूर्व सांसद हैं)

शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की काल डिटेल रिकार्ड से पता चला है कि पिछले एक साल में उसके संपर्क में 100 से ज्यादा युवक आये। बैंक से जानकारी मिली है कि उसके खाते में हर महीने लाखों रूपये जमा कराये जा रहे थे।

यह रकम गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में जमा कराई गयी । पुलिस अब रकम जमा कराने वाले लोगों के नाम पते मालूम कर उनकी कुंडली पता कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां और यूपी पुलिस आरोपी बद्दो का पाकिस्तान कनेक्शन तलाश रहे हैं। यूपी पुलिस के पास महाराष्ट्र के ठाणे जिले से भी फोन आया है जिसमें फोन करने वाले युवक ने दावा किया है कि बद्दो का गिरोह महाराष्ट्र के ठाणे में 400 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से भी काल आ चुकी है। गुजरात से आयी एक काल में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी लगभग 400 लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है।

अभी मामले की जांच चूंकि प्रथम चरण में ही और इस मामले में बहुत ही खतरनाक खुलासे हो रहे है इसलिए यह बात तो तय लग रही है कि आनलाइन गेमिंग एप के सहारे धर्मांतरण कराने का यह खेल व इसके तार बहुत दूर तक फैले हैं जो पाकिस्तान से लेकर जाकिर नाईक तक पहुंच रहे हैं ।

यह संतोष की बात है कि उप्र में धर्मांतरण विरोधी एक कड़ा कानून लागू है। थी योगी सरकार 2020 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून लेकर आयी जिसमें लोगों को बहला फुसलाकर, जबरन झूठ बोलकर या डरा धमकाकर धर्मांतरण करवाने का दोषी पाये जाने पर एक से पांच साल तक की कैद और 15 हजार रूपये तक का जुर्माना व एससी एसटी के मामले में दो साल से लेकर दस साल तक की जेल और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यही नहीं उप्र में धर्मांतरण के आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व गैंगस्टर लगाने जैसे कदम उठाने का भी प्रावधान रखा गया है तथा आरोपी पर सभी आरोप साबित होते ही उसकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान है।

अब बच्चों पर नजर रखने की जरूरत

आनलाइन गेमिंग एप से धर्मान्तरण से हुए खुलासे को देखते हुए आवश्यक है कि सभी माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य अपने बच्चों पर दृष्टि रखें ।अगर कोई भी बालक फोन या लैपटॉप पर लगातार गेम खेल रहा है, अनजान लोगों से लंबी बातें कर रहा है, बिना बताए घर से बाहर चला जाता है, उसकी आदतों में कुछ बदलाव दिखाई देरहा है तो उस पर नजर रखना और उससे पूछताछ करना जरूरी है कि कहीं वह किसी गिरोह के मकड़जाल मे तो नहीं फंस रहा है।

● ● ● ●

कट्टर एवं मतांध शासकों में नायकत्व देखने व ढूंढ़ने की प्रवृत्ति अनुचित

● प्रणय कुमार

महाराष्ट्र के अहमदनगर एवं कोल्हापुर में हुई हिंसक झड़पों के बाद एक बार फिर से औरंगजेब व टीपू सुल्तान चर्चा के केंद्र में हैं। ग़ौरतलब है कि बीते 6 जून को कोल्हापुर के कुछ युवाओं द्वारा औरंगजेब व टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक ऑडियो संदेश स्टेटस में लगाए गए थे, जिसके विरोध में 7 जून को कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित के अनुसार प्रदर्शन समाप्त होने के पश्चात जब भीड़ वापस जा रही थी, तब कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरु कर दिए, जिससे मजबूर होकर पुलिस को भी बल-प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। इससे पूर्व अहमदनगर के फाकिरवाड़ा में 4 जून को सुबह नौ बजे एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में गाने बज रहे थे, जिस पर लोग डांस कर रहे थे। इसी जुलूस में चार लोग औरंगजेब के पोस्टर लेकर चल रहे थे। 6 जून को इसके विरोध में अहमदनगर में हिंदू संगठनों द्वारा एक विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिस पर कुछ कट्टरपंथी एवं असामाजिक तत्त्वों ने

गीता प्रेस रूपी उजालों पर राजनीति क्यों?

आजादी के अमृतकाल में स्व-संस्कृति, स्व-पहचान एवं स्व-धरातल को सुदृढ़ता देने के अनेक अनूठे उपक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार में हो रहे हैं, उन्हीं में एक है भारत सरकार द्वारा एक करोड़ का गांधी शांति पुरस्कार सौ साल से सनातन संस्कृति की संवाहक रही गीता प्रेस, गोरखपुर देने की घोषणा। 1800 पुस्तकों की अब तक 92 करोड़ से अधिक प्रतियां प्रकाशित करने वाले गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लिये चुना जाना एक सराहनीय एवं सूझबूझ भरा उपक्रम है। यह सम्मान मानवता के सामूहिक उत्थान, धर्म-संस्कृति के प्रचार-प्रसार, अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। लेकिन विडम्बना है कि ऐसे मानवतावादी उपक्रमों को भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से राजनीतिक दलों और नेताओं को कितना फायदा या नुकसान होता है यह अलग बात है लेकिन सही बात तो यह है कि ऐसे विवादों का खमियाजा देश को जरूर उठाना पड़ता है।

ऐसा ही ताजा विवादित बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पुरस्कार को लेकर दिया है। रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा है। निश्चित ही यह तो उजालों पर कालिख पोतने के प्रयास है। ऐसे प्रयास अंधेरे सायों से प्यार करने वाले लोग ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों की आंखों में किरणें आंज दी जाये तो भी वे यथार्थ को नहीं दे सकते। ऐसे राजनीतिक लोग आकाश में पैबंद लगाना चाहते हैं और सछिद्र नाव पर सवार होकर राजनीति सागर की यात्रा करना चाहते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि गीता प्रेस प्रतिदिन सत्तर हजार प्रतियां प्रकाशित कर घर-घर में धर्म-संस्कृति-राष्ट्रीयता का दीप जला रहा है। अपनी किताबों के माध्यम से समाज में संस्कार परोसने व चरित्र निर्माण का काम भी यह संस्था कर रही है। गीता प्रेस के कामकाज को लेकर आज तक कोई विवाद भी पैदा नहीं हुआ। ऐसी संस्था को लेकर जब यह बयान आता है तो यह भी सवाल उठता है कि क्या जयराम रमेश के इस बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि जयराम रमेश कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं और केन्द्र में मंत्री भी रह चुके हैं।

इस तरह के उद्देश्यहीन, उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक बयान सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को कमजोर तो करते ही हैं, धर्म, आस्था और संस्कारों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को हतोत्साहित भी करते हैं। वैसे भी हर धर्म व उससे जुड़ी संस्थाओं को अपने कामकाज के प्रचार-प्रसार का पूरा हक है। गीता प्रेस के बारे में देश के तमाम बड़े नेताओं और धर्मगुरुओं की राय सकारात्मक ही रही है। संस्था ने सकारात्मकता की एक ओर मिसाल पेश करते हुए किसी प्रकार का दान स्वीकार न करने के अपने सिद्धांत के तहत एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस राशि को कहीं और खर्च करे।

गांव जलाने वाला और जलती आग से बचाने वाला- दोनों एक कैसे हो सकते हैं? गीता प्रेस पर दोषारोपण करने वाले एवं उसकी जिस तरह से अतिश्योक्तिपूर्ण तुलना की गयी है, वह आलोचक ही उच्छृंखलता एवं बुद्धिहीनता को दर्शाता है। गांव जलाने वाले और जलती आग से बचाने वाले को कोई मन्दबुद्धि व्यक्ति भी एक नहीं मान सकता। फिर गीता प्रेस जैसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक अभियान के साथ इस विसंगतिपूर्ण आलोचना की सोचना ही विध्वंसात्मक सोच है। इस तरह की आलोचना राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह के साथ बुद्धि का दिवालियापन है। हर मामले को राजनीतिक रंग में डुबोने की ताक में रहना राजनेताओं की फितरत-सी बनती जा रही है। लोकतंत्रीय पद्धति में किसी भी विचार, कार्य, निर्णय और जीवनशैली की आलोचना पर प्रतिबंध नहीं है। किन्तु आलोचक का यह कर्तव्य है कि वह पूर्व पक्ष को सही रूप में समझकर ही उसे अपनी आलोचना की छेनी से तराशे। किसी भी तथ्य को गलत रूप में प्रस्तुत कर उसकी आक्षेपात्मक आलोचना करना उचित नहीं है। जिन दलों, लोगों एवं विचारधाराओं का उद्देश्य ही निन्दा करने का हो, उनकी समझ सही कैसे हो? जिसका काम ही किसी अच्छे काम या मन्तव्य को जलील करने का हो, वह सत्य का आईना लेकर क्यों चलेगा?

गीता प्रेस के सौ वर्षों का स्वर्णिम दौर एवं संस्कृति-निर्माण के कार्य कोई कांच का नाजुक घर नहीं है कि आलोचना की बौछार से किरचें-किरचें होकर बिखर जाये। उसने जो संस्कार निर्माण एवं संस्कृति जागरण के सत्य को उजागर किया, वह शताब्दी पहले जितना सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है। बल्कि नई परिस्थितियों के साथ उसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गयी है। उसकी दूरगामी निगाहों ने अपने युग के पार देखकर जिस सत्य को पकड़ा था, दुस्साहसी कालचक्र उसे किसी भी कोने से खण्डित नहीं कर पाया। उसने तो देश के घर-घर में धर्म की पताका लहराई है, सतातन सत्यों की एक ठोस जमीन दी है, काश! समग्र दृष्टि से विचार करते हुए तथाकथित राजनीतिक लोग इस सिलसिले का सम्मान कर पाते। राजनेताओं को राजनीतिक दलों की कार्यशैली या उनके कार्यक्रमों को लेकर आपत्ति हो सकती है, पर किसी भी निर्विवाद संस्था को बेवजह विवादों में घसीटना अशोभनीय ही कहा जाएगा। यह सही है कि

आज के दौर में राजनीतिक दलों व नेताओं की रणनीति वोट बैंक की चिंता और सुर्खियां बटोरने की आतुरता के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन राजनेताओं से यह तो अपेक्षा की जाती है कि वे बयान सोच-समझकर दें। बयान देकर फिर वापस ले लेने से भी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आसान नहीं होती। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने नेताओं के लिये बयानों में संयम बरतने की आचार-संहिता लागू करें।

गीता प्रेस की पत्रिका है कल्याण। कल्याण की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब तक इस पत्रिका के कई विशेषांकों (पहले अंक) के पाठकों की मांग पर अनेक संस्करण प्रकाशित करने पड़े। चाहे जैसी स्थितियां आईं, कल्याण अपने लक्ष्य, संकल्प व दायित्वबोध के प्रति पूरी तरह सजग रही। भारत बंटवारे का विरोध किया तो जरूरत पड़ने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मार्गदर्शन किया। भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा कल्याण के रूप में रोपा गया पौधा आज वटवृक्ष बन चुका है। लोगों का धर्म-संस्कृति के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रहा है। भाईजी व गांधीजी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध थे। 'कल्याण' का पहला अंक 1926 में प्रकाशित हुआ था, इसमें गांधीजी का लेख भी छपा था। भाईजी यह अंक गांधीजी को भेंट करने गए थे। उन्होंने न सिर्फ कल्याण की प्रशंसा की, बल्कि यह आग्रह भी किया था कि कल्याण या गीताप्रेस से प्रकाशित होने वाली किसी पुस्तक में बाहरी विज्ञापन न प्रकाशित किया जाए, इससे कल्याण व पुस्तकों की शुचिता बनी रहेगी। इसका पालन आज भी गीताप्रेस करता है। कल्याण के विभिन्न अंकों में गांधीजी के लेख छपते रहे। आज भी गांधीजी द्वारा लिखा गया पत्र गीताप्रेस में सुरक्षित रखा गया है। गांधीजी के जीवन पर इस पत्रिका का अनूठा प्रभाव रहा है और उन्हीं के नाम पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिये गीता प्रेस से अधिक उपयुक्त पात्र कोई और हो नहीं सकता, यह बात जयराम रमेश को भलीभांति समझ लेनी चाहिए। सस्ती राजनीतिक वाह-वाही के लिये ऐसे बयानों से जयराम रमेश ने अपनी ही पार्टी एवं उसकी ऐतिहासिक विरासत को आहत किया है।

- ललित गर्ग

पत्थरबाजी शुरु कर दी और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ओर जहां आए दिन कुछ गिने-चुने लोग औरंगजेब व टीपू सुल्तान को नायक की तरह पेश करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अधिसंख्य जन इन्हें खलनायक की तरह देखते और मानते हैं। अतीत के किसी शासक को नायक या खलनायक मानने के पीछे ऐतिहासिक स्रोतों एवं साक्ष्यों के अलावा जनसाधारण की अपनी भी एक दृष्टि या धारणा होती है। वह दृष्टि या धारणा रातों-रात नहीं बनती, अपितु उसके पीछे उस समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ों, परंपराओं, जीवन-मूल्यों, जीवनादर्शों से लेकर संघर्ष-सहयोग, सुख-दुःख, जय-पराजय, गौरव-अपमान आदि की साझी अनुभूतियों के साथ-साथ, उस शासक द्वारा प्रजा के हिताहित में किए गए कार्यों की भी महती भूमिका होती है। इस देश की आम जनता ने लंबी अवधि तक शासन करने वाले, सफल सैन्य व विजय-अभियानों का संचालन करने वाले या विस्तृत भूभागों पर आधिपत्य स्थापित करने वाले राजाओं की तुलना में उदार, सहिष्णु, समदर्शी, परोपकारी, प्रजावत्सल एवं न्यायप्रिय राजा तथा लोकहितकारी राज्य को अधिक मान एवं महत्त्व दिया है। मजहबी मानसिकता से ग्रसित कट्टरपंथी लोग या क्षद्म पंथनिरपेक्षतावादी बुद्धिजीवी एवं कथित इतिहासकार भले ही औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर भिन्न दावा करें, परंतु आम धारणा यही है कि ये दोनों क्रूर, बर्बर, मतांध एवं आततायी शासक थे। ऐतिहासिक साक्ष्य एवं विवरण भी इसकी पुष्टि करते हैं।

औरंगजेब की कट्टरता एवं मतांधता को दर्शाने के लिए 9 अप्रैल 1669 को उसके द्वारा जारी राज्यादेश पर्याप्त है, जिसमें उसने सभी हिंदू मंदिरों एवं शिक्षा-केंद्रों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को काशी-मथुरा समेत उसकी सल्तनत के सभी 21 सूबों में लागू किया गया था। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक मुहम्मद साफी मुस्तइद्दखां ने अपनी किताब 'मआसिर-ए-आलमगीरी' में भी किया है। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर की पृष्ठ-संख्या 57 पर भी इस आदेश का उल्लेख है। इतिहासकारों का मानना है कि इस आदेश के बाद गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदेव मंदिर, अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, बीजापुर का मंदिर, वडनगर का हथेश्वर मंदिर, उदयपुर में झीलों के किनारे बने 3 मंदिर, उज्जैन के आसपास के मंदिर, चितौड़ के 63 मंदिर, सवाई माधोपुर में मलारना मंदिर, मथुरा में राजा मानसिंह द्वारा 1590 में निर्माण कराए गए गोविंद देव मंदिर समेत देश भर के सैकड़ों छोटे-बड़े मंदिर ध्वस्त करा दिए गए। मजहबी जिद व जुनून में उसने हिंदुओं के त्योहारों एवं धार्मिक प्रथाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया था। 1679 ई. में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक या प्रजा बनकर जीने को विवश कर दिया। तलवार या शासन का भय दिखाकर उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का मतांतरण करवाया। इस्लाम न स्वीकार करने पर उसने निर्दोष एवं निहत्थे हिंदुओं का क़त्लेआम करवाने में भी कोई संकोच नहीं किया। मजहबी सोच व सनक में उसने सिख धर्मगुरु तेगबहादुर

खालिस्तान समर्थकों को नियंत्रित करना जरूरी

कुछ शक्तियां देश के आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने में जुटी है, वहीं कुछ संकीर्ण, साम्प्रदायिक, उन्मादी एवं अलगाववादी शक्तियां देश को तोड़ने एवं धुंधलाने में लगी है। वोटबैंक के नाम पर लोगों को अलग-अलग खेमों में बांटने, तुष्टिकरण एवं उन्मादी काली शक्तियों को प्रोत्साहन देने एवं ज्वाला बनाने का काम देश के लिये घातक एवं नुकसानदेह है। वोटबैंक की राजनीति सभी देशों में होती है, पर ऐसा करते हुए भी मर्यादा एवं देश की एकता का ध्यान भी रखा जाता है। कानून का राज कायम रखने और विश्व शांति के खतरों को कमतर करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जिन देशों में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, वहां जल्दी ही लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है, टूट एवं बिखर कर रसातल में चला जाता है। धार्मिक कट्टरपंथियों एवं उन्माद के आगे नतमस्तक रहे पाकिस्तान को देखकर इस समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है। कनाडा में पिछले कुछ समय से और खासकर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में, वहां बसे सिखों को साधने के लिए जिस तरह खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता की बड़ी वजह है, लेकिन यह कनाड़ा के लोकतंत्र के लिये भी बड़ा खतरा बनने का संकेत हैं।

कनाडा में बेलगाम होते खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं, लेकिन अब उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का खुलेआम जश्न भी मनाने लगे हैं। कनाडा के ब्रैंपटन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह एक परेड निकाली और उसमें इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए दिखाया गया, इसमें दो सिखों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को गोली मारते दिखाया गया। वह बेहद त्रासद, शर्मनाक और घिनौना है। यह परेड करीब पांच किमी तक निकाली गई। स्पष्ट है कि कनाडा की पुलिस आतंक का महिमामंडन करने वाली इस घिनौनी परेड को चुपचाप देखती रही। आतंकवाद का ऐसा खुला, लज्जाजनक और नग्न समर्थन कनाडा के साथ सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। निश्चित ही इससे दुनिया में पनप रहे आतंकवाद को बल मिलेगा। यह आज सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है।

भारत में भी कनाडा की ही भांति वोट बैंक ही पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद एवं जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद पनपने का बड़ा कारण बना था। इस घटना के सामने आने के बाद भारत सरकार की तीखी प्रतिक्रिया जायज है। ऐसी घटनाओं के कारण दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें बगैर किसी राजनीति के पक्ष व विपक्ष दोनों के सुर का एक होना जरूरी है। ऐसा ही दिखा भी, दिखना भी चाहिए। पंजाब में खालिस्तानी स्वर उग्र हो रहे हैं, इसको उग्रता देने में कनाड़ा आदि देशों में रह रहे खालिस्तान समर्थक सिखों से मिल रही आर्थिक मदद एवं अन्य प्रोत्साहन बड़े कारण है। अब एक बार फिर खालिस्तान समर्थक तत्व देश के अंदर और बाहर सक्रिय हो रहे हैं। कनाडा उनके लिए एक बड़ा केंद्र एवं आश्रय-स्थल बनकर उभरा है। और यह वहां अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी वहां से एक अलग देश खालिस्तान बनाए जाने के सवाल पर जनमत संग्रह करवाए जाने की खबर आई थी। खालिस्तान समर्थक कभी भारतीय उच्चायोग को घेरते हैं कभी भारतीयों पर हमले करते हैं और कभी मंदिरों को निशाना बनाते हैं।

कनाडा सरकार हर बार इन खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहकर चुप्पी साध लेती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे ताजा विडियो को हालांकि सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने मुद्दा बनाया, लेकिन फिर सरकार भी इस पर जागरूक हुई है। ऐसी घटनाएं न तो भारत-कनाडा रिश्ते के लिए अच्छी हैं और न कनाडा के लिए। बहरहाल, इससे यह साफ हो जाता है कि कनाडा में हिंसा की वकालत करने वाले अतिवादी और अलगाववादी तत्वों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने हालांकि इस घटना की निंदा की और कहा कि उनके देश में नफरत, द्वेष और हिंसा के महिमामंडन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसे औपचारिक बयान जारी कर देना काफी नहीं है। उनका बयान लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सच यही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता और नफरत को पालने-पोसने का काम बड़ी ही बेशर्मी से किया जा रहा है, वहां की सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी के चलते उनका दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। वैसे तो उग्रपंथी खालिस्तान समर्थक दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं, लेकिन वे जितने कनाडा में बेलगाम हैं, उतने अन्यत्र कहीं नहीं। कनाडा को समझना होगा कि आतंकवाद, अलगाववाद, नफरत और हिंसा की आग सबसे पहले उन देशों को जलाती है जो इसे हवा देते हैं। ऐसे देशों की दुर्गति के उदाहरण सबके सामने हैं। उन देशों के अनुभव से समय रहते सबक लेना चाहिए।

कनाडा में खालिस्तान समर्थन का बड़ा कारण यह है कि कनाडा की वर्तमान सरकार उस राजनीतिक दल के समर्थन के भरोसे सत्ता में है, जिसमें खालिस्तान समर्थक भरे पड़े हैं। कनाडा की सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से खालिस्तान समर्थकों की भारत-विरोधी अराजक, घृणित और नफरत फैलाने वाली हरकतों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट कहा कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी

गतिविधियों के लिए हो रहा है और वहां खालिस्तान समर्थकों को मिल रहे समर्थन से दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। चूंकि इसके आसार कम हैं कि भारत सरकार की आपत्ति के बाद कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक अराजक तत्वों को समर्थन देने से बाज आएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए।

भारत के लिये जरूरी है कि यहां सभी राजनीतिक दल इन अति-संवेदनशील एवं देश तोड़क मुद्दों पर एकमत हो। राजनीति के पोषण के बिना खालिस्तानी आतंक उग्र नहीं हो सकता, उनको भड़काकर राजनीति करने वाले दलों से सावधान होने की जरूरत है। खालिस्तान समर्थक अपनी आतंकवादी गतिविधियों एवं हरकतों से देश की एकता एवं अखण्डता को खंडित करना चाहते हैं, ये तत्व अपनी इस तरह की हरकतों के जरिए उस आतंकवाद की ओर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कदम उठाने पड़े और जिसके चंगुल में पंजाब आगे भी कई साल तक फंसा रहा, त्रासदी झेलता रहा, डरा एवं सहमा रहा। न जाने कितने परिवार इस चक्कर में बर्बाद हो गए, कितने लोगों को जान देनी पड़ी। अनगिनत कुर्बानियों के बाद पंजाब जैसे-तैसे उस मुश्किल दौर से निकला और पहले की तरह अपने पराक्रम से विकास की नई कहानियां लिखने लगा। लेकिन अब पुनः पंजाब को उसी खूनी मंजर एवं खौफनाक दौर की ओर अग्रसर करना आजादी के अमृतकाल को धुंधला देगा। जरूरत है तुष्टिकरण हटे, संकीर्ण दायरों से बाहर आये एवं उन्माद भी हटे। अगर भारत माता के शरीर पर इतना बड़ा घाव करके हम कुछ नहीं सीख पाये, आस्था को उन्माद बनाने से नहीं रोका, वोट के लिये धर्म की राजनीति करना नहीं छोड़ा और सर्वधर्म समभाव की भावना को पुनः प्रतिष्ठापित नहीं किया तो यह हम सबका दुर्भाग्य होगा।

- ललित गर्ग

का सिर कटवा दिया, गुरुगोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, संभाजी को अमानुषिक यातनाएं देकर मरवाया। जिस देश में श्रवण कुमार और देवव्रत भीष्म जैसे पितृभक्त पुत्रों और राम-भरत-लक्ष्मण जैसे भाइयों की कथा-परंपरा प्रचलित हो, वहां अपने बूढ़े एवं लाचार पिता को कैद में रखने वाला तथा अपने तीन भाइयों दारा, शुजा और मुराद की हत्या कराने वाला व्यक्ति सामान्य एवं स्वस्थ जनों का आदर्श या नायक नहीं हो सकता! सम्राट अशोक के अपवाद को उदाहरण की तरह प्रस्तुत करने वाले लोग स्मरण रखें कि लोक में उसकी व्यापक स्वीकार्यता का मूल कारण उसका प्रायश्चित-बोध एवं मानस परिवर्तन के बाद सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जैसे शाश्वत मानवीय सिद्धांतों के प्रति उपजी उसकी दृढ़ निष्ठा थी, न कि साम्राज्य-विस्तार की लालसा या युद्ध-पिपासा।

आश्चर्य नहीं कि टीपू सुल्तान का महिमामंडन करने वाले लोग उसकी क्रूरता, मतांधता एवं कट्टरता के विवरणों से भरे ऐतिहासिक प्रमाणों एवं अभिलेखों आदि पर एकदम मौन साध जाते हैं। 19 जनवरी, 1790 को बुरदुज जमाउन खान को एक पत्र में टीपू ने स्वयं लिखा है, 'क्या आपको पता है कि हाल ही में मैंने मालाबार पर एक बड़ी जीत दर्ज की है और चार लाख से अधिक हिंदुओं का इस्लाम में कंवर्जन करवाया है।' सईद अब्दुल दुलाई और अपने एक अधिकारी जमान खान को लिखे पत्र में वह कहता है, 'पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह के करम से कालीकट के सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है। केवल कोचिन स्टेट के सीमावर्त्ती इलाकों के कुछ लोगों का कंवर्जन अभी नहीं कराया जा सका है। मैं जल्द ही इसमें भी क़ामयाबी हासिल कर लूंगा।' टीपू ने घोषित तौर पर अपनी तलवार पर खुदवा रखा था -'मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से क़ाफिरों (ग़ैर मुसलमानों) को समाप्त कर दूं।' द मैसूर गजेटियर के अनुसार टीपू ने लगभग 1000 मंदिरों का ध्वंस करवाया था। स्वयं टीपू के शब्दों में, 'यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए, तब भी मैं हिन्दू मंदिरों को नष्ट करने से नहीं रुकूंगा' (फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल)। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार में अधिकारी रहे लेखक विलियम लोगान की 'मालाबार मैनुअल', 1964 में प्रकाशित

केट ब्रिटलबैंक की 'लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान' आदि पुस्तकों तथा उसके एक दरबारी एवं जीवनी लेखक मीर हुसैन किरमानी के विवरणों से ज्ञात होता है कि टीपू वास्तव में एक अनुदार, असहिष्णु, मतांध, क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। गैर-मुस्लिम प्रजा पर बेइंतहा जुल्म ढाने, लाखों लोगों का जबरन मतांतरण करवाने तथा हजारों मंदिरों को तोड़ने के मामले में वह दक्षिण का औरंगजेब था। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि उसने अफगान शासक जमान शाह समेत कई विदेशी शासकों को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण भेजा।

क्या यह अच्छा नहीं होता कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे कट्टर एवं मतांध शासकों को नायक के रूप में स्थापित करने या जोर-जबरदस्ती से बहुसंख्यकों के गले उतारने की कोशिशों की बजाय मुस्लिम समाज द्वारा रहीम, रसखान, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर,

क्यों खालिस्तानी सक्रिय हैं कनाडा में

कनाडा में खालिस्तानी ताकतें भारत और हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगल रही हैं। दुख इस बात का है कि मित्र देश होने के बावजूद कनाडा सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब ताजा मामले में खालिस्तानियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर निकाली परेड में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी को आपत्तिजनक रूप में दिखाया। बीती 6 जून, को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने 5 किलोमीटर लंबी परेड निकाली। इसमें एक झांकी में इंदिरा गांधी की हत्या का सीन दिखाया गया। झांकी में इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी पहने दिखाया गया है। उनके हाथ ऊपर हैं। दूसरी तरफ दो शख्स उनकी तरफ बंदूक ताने खड़े हैं। इसके पीछे लिखा है-बदला। कनाडा अपने को एक सभ्य देश होने का दावा करता है। पर वहां अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वाले खुल कर खेल कर रहे हैं। आप इंदिरा गांधी की कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैं, पर यह कोई भी भारतीय सहन नहीं करेगा कि उन्हें आपत्तिजनक तरीके से झांकी में पेश किया जाए। बेशक, इस सारे घटनाक्रम से भारत स्तब्ध है। इस कट्टरपंथ की सार्वभौमिक तौर पर निंदा होनी चाहिए। पता नहीं क्यूं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विदेशों में जाकर जहर उगलने वाले राहुल अपनी दादी के अपमान पर क्यों नहीं बोल रहे। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानियों की गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। वहां पर मंदिरों में भी तोड़फोड़ की जाती है। कनाडा का ब्रैम्पटन शहर तो भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। कनाडा में बार-बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जुलाई 2022 में कनाडा के रिचमंड हिल इलाके में एक विष्णु मंदिर में महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। सितंबर 2022 में कनाडा में स्वामीनारायण मंदिर को कथित खालिस्तानी तत्वों ने भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ विकृत कर दिया था। पर वहां की पुलिस की काहिली और निकम्मेपन के कारण दोषी पकड़ में नहीं आते। कौन भूल सकता है कनिष्क विमान हादसे को। मांट्रियाल से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून 1985 को आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ते समय, 9,400 मीटर की ऊंचाई पर, बम से उड़ा दिया गया था और वह अटलांटिक महासागर में गिर गया था। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे हैं। वे कथित किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तब ट्रूडो कह रहे थे कि 'कनाडा दुनिया में कहीं भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा।' क्या कनाडा की खुफिया एजेंसिया इतनी घटिया हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर खालिस्तानी सक्रिय हैं? उन्हें भारत-विरोधी तत्वों पर कठोर एक्शन लेना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो 2018 में भारत यात्रा पर आए थे। वे अमृतसर से लेकर आगरा और मुंबई से लेकर अहमदाबाद का दौरा करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले तो उन्हें कायदे से समझा दिया था कि 'भारतधर्म के नाम पर कट्टरता तथा अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा।' उनका इशारा कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की नापाक भारत विरोधी गतिविधियों से था। कनाडा की लिबरल पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहने को तो एक उदार देश से हैं। उन्हें भी यह समझ लेना होगा कि भारत भी एक उदार और बहुलतावादी देश है। उनकी उस भारत यात्रा के समय तब तगड़ा हंगामा हो गया था, जब पता चला था कि नई दिल्ली में कनाडा हाई कमीशन ने अपने प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में कुख्यात खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को आमंत्रण भेजा है। अटवाल पर कनाडा में वर्ष 1986 में एक निजी दौरे पर गए पंजाब के मंत्री मलकीत सिंह सिद्धू पर जानलेवा हमला करने का आरोप साबित हो चुका है। कनाडा सरकार की बेवकूफियों के कारण वहां पर खालिस्तानी सक्रिय हैं। ये भारत को फिर से खालिस्तान आंदोलन की आग में झोंकना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कनाडा की ओंटारियो विधानसभा ने 2017 में 1984 के सिख विरोधी दंगों को सिख नरसंहार और सिखों का राज्य प्रायोजित कत्लेआम करार देने वालाएक प्रस्ताव भी पारित किया था।इस तरह की गतिविधियों से स्पष्ट है कि कनाडा में भारत के शत्रु बसे हुये हैं। ये खालिस्तानी समर्थक हैं। समझ नहीं आत कि कनाडा सरकार वहां पर खालिस्तानियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। भारत सरकार इसके चलते कनाडा सरकार से खासी नाराज भी है। भारत इंदिरा गांधी को झांकी में गलत तरीके से दिखाने पर नाराज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को लताड़ लगाते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये मुद्दा दोनों देशों के संबंधों के लिए सही नहीं है और न ही ये कनाडा के लिए ही ठीक है। अब भारत कनाडा से इतनी तो उम्मीद करेगा ही कि वह खालिस्तानियों को कस दे। एक बात माननी होगी कि कनाडा अराजकता के अंधकार में डूब रहा है। वहां पर तीन साल पहले पाकिस्तान फौज की तरफ से बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्मों-सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाली प्रखर महिला एक्टिविस्ट करीमा बलोच की निर्मम हत्या पाकिस्तान की धूर्त और शातिर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने करव दी थी थी। बलोच पाकिस्तान सरकार, सेना और आईएसआई की आंखों की किरकिरी बन चुकी थीं। वह पाकिस्तान सरकार की कालीकरतूतों की कहानी लगातार दुनिया को बता रही थीं। इसीलिए उसे आईएसआई ने ठिकाने लगा दिया। बलोच के कत्ल नेसाफ कर दिया था कि कनाडा एक अराजक मुल्क के रूप में आगे बढ़ रहा है। वहां पर खालिस्तानी तत्व तो पहले से ही जड़ें जमा ही चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि इन सब बातों को जानने के बावजूद भारत के बहुत से लोगों का ख्वाब है कनाडा में जाकर बसना।

आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठसंपादक, स्तभकार और पूर्व सांसद हैं)

अशफाक उल्ला खां, खान अब्दुल गफ़्फार खान, वीर अब्दुल हमीद एवं ए.पी.जे अब्दुल कलाम जैसे साझे नायकों व चेहरों को सामने रखा जाता? इससे समन्वय, सहिष्णुता एवं सौहार्द्रता की साझी संस्कृति विकसित होगी। कट्टर एवं मतांध शासकों या आक्रांताओं में नायकत्व देखने व ढूंढ़ने की प्रवृत्ति अंततः समाज को बांटती है। यह जहां विभाजनकारी विषबेल को सींचती है, वहीं अतीत के घावों को कुरेदकर उन्हें गहरा एवं स्थाई भी बनाती है।

शिक्षाविद एवं वरिष्ठ स्तंभकार

रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान भाजपा की गुटबाजी खत्म करने के लिए क्या संगठन में फिर बदलाव होगा ?

राजस्थान भाजपा गुटबाजी के कारण संकट के दौर से गुजर रही है। अधिकांश कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी अभी भी चुनावी मोड में नहीं आ सकी है। जबकि चुनाव में 4-5 महीने ही बचे हैं। प्रदेश के ज्यादातर नेता अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग की तर्ज पर आंदोलन, प्रदर्शन एवं प्रेस कांफ्रेंस करने में जुटे हैं। प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अधिकांश नेता दूरियां बना रहे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। लेकिन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निजी तौर पर चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल चुके हैं। उनका पूरा फोकस अपनी ब्रांडिंग पर है। वे यह संदेश देने में भी कामयाब रहे हैं कि पूर्व सीएम सचिन पायलट भी उनके आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य की रणनीति को लेकर भ्रमित हैं। उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं।

राजस्थान भाजपा में गुटबाजी खत्म करने के लिए दिल्ली तक मंथन चल रहा है। बताया जा रहा हैं कि पार्टी आलाकमान के ना चाहते हुए भी भाजपा के पास पूर्व सीएम वसुंधराराजे को इलेक्शन कैंपेन कमेटी चेयरमैन के नाते आगे करने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। राज्य में हालात तो फिलहाल यही हैं कि वसुंधरा राजे वहां अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। इसी बीच माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की पसंद एक केंद्रीय मंत्री पर टिकी है। नया नाम सरप्राइज एंट्री है और पीएम नरेंद्र मोदी की भी पसंद है। पार्टी भी उन्हें नई पीढ़ी के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है।

हालांकि, अभी तक नए नाम का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज है। इधर सूचना ये भी है कि दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। जिसमें आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव पर खास फोकस रहा। इस दौरान पार्टी ने आगे की रणनीति पर चर्चा की और कई फैसले भी लिए हैं। हालांकि, सीएम फेस को लेकर पार्टी नेतृत्व किसी फैसले पर पहुंचता नहीं दिख रहा। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी नेताओं ने राज्य में कई अहम बदलाव पर भी विचार किया है। कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं।

राजे समर्थकों का दावा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए उछलकूद करने वाले ज्यादातर नेता बतौर मंत्री अथवा संगठन पदाधिकारी वसुंधराराजे के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। इसलिए उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन, पार्टी हाईकमान को जो भी निर्णय लेना है। वह जल्दी लिया जाना चाहिए। क्योंकि अब धरातल पर काम करने का वक्त बहुत कम बचा है। इसलिए माना जा रहा है कि अगले एक महीने में भाजपा के राजस्थान प्रभारी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी की एक साथ घोषणा करने के साथ ही संगठन महामंत्री भी बदले जा सकते हैं। हालांकि चर्चाएं मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी को भी बदले जाने की भी बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। उस पर यह खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन, भाजपा के ही कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि ऐन चुनाव के मौके पर प्रदेशाध्यक्ष बदलना संभव नहीं है।

भाजपा संगठन से जुड़े लोगों का तर्क है कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी में गुटबाजी खत्म हो जाएगी। लेकिन, पिछले दो-तीन महीनों में वे ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सके। ना ही कोई प्रभाव छोड़ सके। बल्कि कई लोग उन पर हावी होते या मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बताई जा रही है। वे अब खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो आगे फिर शायद ही सीएम बनने का मौका मिले। इसलिए वे पार्टी नेताओं की एकजुटता में कम ही रुचि ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह राज्यवर्धन राठौड़ समेत कई नेता अलग सुर में चुनावी राग अलाप रहे हैं।

भाजपा से जुड़े नेताओं का कहना है कि पार्टी को एकजुट रखने की मूल रूप से अहम जिम्मेदारी संगठन महामंत्री की होती है। वह प्रदेशाध्यक्ष, पदाधिकारियों, केंद्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु की तरह काम करता है। लेकिन, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर खुद ही गुटबाजी में फंस गए। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से उनकी लगभग पूरे समय ही दूरी रही। उससे पहले सतीश पूनिया को इसीलिए पार्टी की कमान सौंपी गई थी कि वे सबको साथ कर साथ लेकर चलेंगे। लेकिन, उन्होंने इतनी बड़ी गुटबाजी पैदा कर दी कि अब तक पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे की बात है तो वसुंधरा समर्थक मंच के नाम से उनका समानांतर संगठन राजस्थान में पहले ही बन चुका है।

दिल्ली में जो मंथन चल रहा है, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई तक भाजपा में बड़े बदलाव होंगे। बहरहाल, कांग्रेस का यह आरोप भी सही लगता है कि भाजपा में मुख्यमंत्री बनने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जबकि कांग्रेस में एकमात्र अशोक गहलोत ही हैं। उनकी भी दिली इच्छा है कि वे एक बार सरकार रिपीट करवाकर लगातार दो टर्म मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएं। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। विधान सभा चुनाव में चार पांच महीने का समय बचा है। भाजपा को सत्ता में लौटने के लिए संगठन स्तर पर सही और सख्त कदम उठाने होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा अगर इस बार सत्ता में नहीं आई तो उसका संघर्ष काफी लंबा हो जाएगा। फिर सत्ता सिंहासन तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। ■

सदी की भीषणतम ट्रेन दुर्घटना

हादसा, लापरवाही या षड्यंत्र और फिर सियासत!

● **मृत्युंजय दीक्षित**

भारतीय रेलवे के इतिहास में ओडिशा के बालसोर और भद्रक के बीच बाहनगा बाजार स्टेशन के पास हुई भीषण रेल दुर्घटना से संपूर्ण भारत दुखी है, जहां भी लोग एकत्र हो रहे हैं वहां इसी दुर्घटना की चर्चा हो रही है और स्थान- स्थान पर एकत्र लोग मृत लोगों के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे है। इस ट्रेन दुर्घटना में 280 से अधिक लोगों की मौत और एक हजार से अधिक लोगों का घायल हो जाना हृदय विदारक है ।

दुर्घटना की भयावहता का पता वहां से आ रही तस्वीरों से ही लग रहा है किंतु इन बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी स्थानीय समुदाय ने जैसे त्वरित रूप से पीड़ित यात्रियों की सहायता की है वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटनास्थल का तत्काल दौरा किया,अस्पतालों में जाकर दुर्घटना में घायलों का हाल जाना और स्थिति की समीक्षा की। रेलवे और भारत सरकार ने भी तत्काल घायलों को 50 हजार व मृतकों के परिजनों को दस लाख की अग्रिम सहायता की घोषणा की है। इस ट्रेन दुर्घटना का समाचार आते ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जिस जीवटता का परिचय दिया है, वह अतुलनीय है।

संघ व समाज ने प्रस्तुत किया मानवता का उदहारण

सदी की भीषणतम ट्रेन दुर्घटना में स्थानीय समाज के लोगों ने जिस प्रकार सेवा की वह अप्रतिम है ।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच गये। जहां पर दुर्घटना हुई थी उसके पास स्थित गांव बाहनगा में संघ की शाखा होने के करण वहां के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचे और फिर उनकी सूचना पर सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक वहां पर पहुंच गये,अस्पतालों में रक्तदान के लिए भारी भीड़ पहुंच गयी। स्वयंसेवकों ने 550 यूनिट रक्तदान किया। स्थानीय मेडिकल स्टोर के मालिकों ने पीड़ितों के लिए अपना मेडिकल स्टोर पूरी तरह से फ्री कर दिया। युवाओं ने पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के लिये अपनी बाइक, टेंपो, टैक्सी आदि निजी वाहनों का भी इस्तेमाल किया। आम जनता ने पीड़ितों के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की।

ओड़िशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना की सीबीआई जांच भी प्रारम्भ हो गयी है क्योंकि प्रारम्भिक जांच के दौरान ऐसी जानकारियां सामने आयी हैं जो किसी षड्यंत्र की दिशा में जाती लग रही हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम में जानबूझकर हस्तक्षेप के बिना ये संभव नहीं है कि ट्रेन के लिए निर्धारित मार्ग को मुख्य लाइन से लूप लाइन में बदल दिया जाये।

कैसे हुयी थी दुर्घटना ?

बालासोर में बाहनगा बाजार स्टेशन के पास चेन्नई से हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गयी थी इसके बाद कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गये थे ये डिब्बे पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गये थे।

भारतीय रेलवे के अमृतकाल में जिन परिस्थितियों में यह ट्रेन दुर्घटना हुई उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिनसे प्रतीत हो रहा है कि यह महज एक हादसा नहीं अपतु सोची-समझी साजिश है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे में ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस का कार्य अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का भी विपक्ष द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों पर विरोधी दलों के कर्यकर्ता कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं और कहीं रेलवे ट्रैक पर जानवर घुसाकर वंदेभारत को डिरेल करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में रेलवे में बड़ा बदलाव आया है इसके अंतर्गत अब स्टेशनों का अधुनातन तरीके से कायाकाल्प किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेने पूरी तरह से स्वदेशी है उस पर भी विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार पुराने डिब्बों को नया कर वंदेभारत के नाम पर चला रही है। यह भी कहा गया कि सरकार अब केवल वंदे भारत ट्रेन में चलने वाले यात्रियों को यात्री मानकर काम कर रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना के बाद वंदे भारत एक बार फिर निशाने पर आ गयी।

मोदी सरकार में भारतीय रेलवे

कैसे रुके रेल हादसे और पुलों के टूटने के मामले

पहले उड़ीसा में हुई दर्दनाक रेल दुर्घटना और उसके बाद बिहार में एक पुल का टूटना। इन दोनों घटनाओं के कारण सारा देश उदास भी है और गुस्से में भी है। उदासी मासूमों के मारे जाने पर है और गुस्सा इसलिए है कि ये हादसे थम ही नहीं रहे। पिछली 2 जून को उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गईं। इनमें लगभग तीन सौ मासूम यात्री मारे गए और ना जाने कितने हजार घायल हो गए। यह दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे घातक रेल दुर्घटनाओं में से एक है। ऐसा माना जाता था कि पहली ट्रेन पटरी से उतर गई थी और इसके कुछ डिब्बे पलट गए और विपरीत ट्रैक में गिर गए थे, जहां वे दूसरी ट्रेन से टकरा गए थे। हादसे में एक मालगाड़ी भी चपेट में आ गई। देखिए, यह तो कोई भी मानेगा कि दुनिया भर में हर क्षण कहीं न कहीं कोई न कोई हादसा हो ही रहा है। तेज रफ्तार की जिंदगी में यह अनहोनी भले हो मगर हो रही है, तो हो रही है। असल में 'जीरो एक्सीडेंट' एक आदर्श है एक गोल है। लेकिन, इसे हासिल करना तो असंभव है। जरूरत इस बात की है कि हादसों को न्यूनतम किया जाए। इसके अलावा कितनी जल्दी से जल्दी हादसे के शिकार लोगों तक उचित मदद पहुंचाई जाए।

रेल दुर्घटनाओं में प्रायः देखा गया है कि घटनास्थल पर सरकारी मदद, डॉक्टर नर्स, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, हेलीकाप्टर, नेताओं से पहले वहां पर तमाशबीन खड़े हो जाते हैं। ये बचाव कार्यों को बाधित भी करते हैं। हां, इन्हीं में से समझदार लोग आनन-फानन में कुछ घायलों की मदद को भी आते हैं। दिल से मदद करते भी हैं। अपनी जी-जान लगा देते हैं। जबकि तमाशबीन सिर्फ वहां पर मदद करने वालों के काम में व्यवधान डाल रहे होते हैं और अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं ।

इस बीच,एक बात यह भी जान लें कि जीरो एक्सीडेंट की स्थिति तक पहुंचना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। रेल हादसे कहां नहीं होते। दुनिया के हरेक देश में रेल हादसे होते हैं। पर इन्हें रोका जाना चाहिए। इस लिहाज से कोशिशें भी होती हैं। पर सफलता तो नहीं मिलती। चीन में जुलाई 2011 में हुई रेल दुर्घटना की बात करेंगे। दरअसल, चीन के शहर वेनजुओ में दो हाई-स्पीड ट्रेनों के आमने-सामने से टकराने पर 40 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस रेल दुर्घटना में 172 लोग जख्मी भी हुए थे। हादसे के तुरंत बाद चीन के रेल मंत्री को पद से हटा दिया गया। नए रेल मंत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य संभाला। इसके बाद दुर्घटना की जांच की गई।

रेल हादसे की जांच में पाया गया कि दुर्घटना रेलवे सिग्नल सिस्टम में खामी की वजह से हुआ। आगे की जांच में पाया गया कि सिग्नल सिस्टम का कॉन्ट्रैक्टर देने के लिए रेल मंत्री और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया था। इसके लिए ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता तक किया गया। इसी कारण यह हादसा हुआ और यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

बहरहाल, उड़ीसा रेल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए सी.बी.आई. जांच शुरू हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को भी उम्र कैद या मौत की सजा मिलनी चाहिए। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इस लिहाज से किसी भी तरह की किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए।

अब बिहार में भागलपुर जिले में हुए हादसे का रुख कर लेते हैं। सबको पता है कि गंगा नदी के ऊपर बन रहा एक बड़ा पुल गिर गया। इसका एक स्लैब भी एक साल पहले ही टूट कर गिर गया था। उसी समय सख्त कारवाई होनी चाहिये थी, जो किसी कारण से नहीं की गई। खगड़िया के अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। लेकिन पुल निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसी का नतीजा है कि यह पुल गंगा नदी में गिर गया। पुल के तीन पिलर भी नदी में समा गए। अब इस केस की भी जांच होगी। यह दूसरी बार है जब पुल गिरा है। बस इतनी सी गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त काम बंद हो चुका था। इस वजह से पुल पर कोई मजदूर नहीं था। जैसे ही पुल ताश के पत्तों की तरह गंगा में गिरा, नदी के पानी की कई फीट ऊंची लहरें उठीं। इधर भी उसी नियम के तहत दोषियों पर कार्रवाई हो जैसी रेल हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी। देखिए अब देश को करप्शन के मसले पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। करप्शन और काहिली देश को दीमक की तरह से खाए जा रही है। जो भी करप्शन करता पकड़ा जाए या अपने काम में काहिली करे उसे तो सीधे टांग देना चाहिए। आखिर कब तक देश भ्रष्ट और निकम्मे लोगों को लेकर मानवीय रवैया अपनाता रहेगा। यह नहीं चल सकता। इसका अंत तो होना ही चाहिए। करप्शन के सवाल पर देश को जीरो टोलरेंस की नीति पर चलना ही होगा। दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं हैं। पिछले साल गुजरात के मोरबी जिले में पुल टूटा था। हादसे के वक्त पुल पर 300 से अधिक लोग मौजूद थे। 233 मीटर लंबा यह पुल करीब सौ वर्ष पुराना था। हादसे में बहुत से लोगों की जानें चली गईं थीं। जिनमें अधिकांश महिलाएं एवं बच्चे थे। यह जान लें कि जब तक देश करप्शन के मामलों पर सख्ती नहीं दिखाएगा तब तक इस तरह के जानलेवा हादसे होते ही रहेंगे।

अगर बात इन मामलों से हटकर करें तो करप्शन के कारण हमारे सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ का लोन फंस गया। केन्द्र में मोदी सरकार के सत्तासीन होने के बाद बैंकिंग क्षेत्रों में लंबे समय से व्याप्त अराजकता और अव्यवस्था को रोकने की जब सार्थक पहल हुई तो एक के बाद घोटालों का पर्दाफाश भी तेजी से होने लगा। बैंकिंग सिस्टम तो साख पर ही चलती है्य साख ही नहीं रहा तो फिर बच क्या गया ? दरअसल बैंकों में उल्टे-सीधे लोन दिलवाने का काला धंधा चलता रहा है। लोन दिलवाने के नाम पर कुछ बैंक कर्मी भी फंसे। चूंकि, पहले कोई इस तरह की जवाबदेही नहीं होती थी, इसीलिए चौतरफा लूट जारी थी।

यह स्वीकार करना होगा कि रेल हादसों से लेकर पुल टूटने के मूल में करप्शन ही बड़ा कारण होता है। इसलिए इस पर ही चोट करनी होगी।

आर.के. सिन्हा
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

शासन-तंत्र की भ्रष्टता से खोखले होते निर्माण

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल के ढह जाने की घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है। उसमें दुराग्रही इतना तेज चलते हैं कि ईमानदारी बहुत पीछे रह जाती है। जो सद्प्रयास किए जा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। पुल के गिरने से जितने पैसों की बर्बादी हुई, उसकी भरपाई आखिर किससे कराई जाएगी? बिहार में पुल गिरने की ताजा घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले पिछले साल भर में सात पुलों के ढह जाने की खबरें आईं। पुलों के गिरने के लिए उसे बनाने वाली कंपनी की लापरवाही और भ्रष्टाचार जितनी जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी शासक एवं प्रशासक की है।

आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भ्रष्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। गनीमत यह रही कि ताजा हादसे के समय पुल पर मजदूर काम नहीं कर रहे थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। करीब सात महीने पहले हुए गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लोग अब भी नहीं भूले हैं। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। सात साल पहले कोलकाता में विवेकानंद पुल के ढहने से 26 लोगों की मौत की घटना भी सबको याद होगी। अचरज इस बात का है कि बिहार में रविवार को जो पुल ढहा वह पिछले साल भी ढह चुका था। इसके बावजूद सरकार ने न तो कोई सबक लिया और न ही किसी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की। यह जाहिर करता है कि सरकार, प्रशासन एवं ठेकेदारों के बीच कितनी सुदृढ़ मिलीभगत है।

बिहार में गंगा नदी पर बन रहे इस पुल का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और इसे 2019 में ही पूरा हो जाना था। चार साल बाद भी वह पूरा बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ, यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। देश का दुर्भाग्य है कि हादसे में अगर किसी की जान चली जाए तो हाय तौबा

मच जाती है, अन्यथा ऐसे हादसों पर चर्चा तक नहीं होती। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों को दरकिनार कर दिया जाए, तो हादसे कमोवेश हर राज्य में और हर दल की सरकार के कार्यकाल में होते रहते हैं। विकसित देशों में भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि भारत में ऐसे हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है। हैरानी की बात यह है कि जब पुल के गिरने की घटना उसके वीडियो सहित सुर्खियों में आ गई तब सरकार की ओर से यह सफाई आई कि चूंकि इस पुल का डिजाइन गलत था और जोखिम से भरा था, इसलिए इसे गिराया जाना तय था। इतना तय है कि एक ही पुल अगर दो बार भरभरा कर गिरा तो यह डिजाइन गलत होने से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सामग्री के घटिया होने का भी साफ संकेत है। लेकिन जिस तरह सरकार उस पुल की गुणवत्ता और जोखिम का अध्ययन करा रही थी, क्या उसके निर्माण के दौरान या उससे पहले डिजाइन सहित उसके हर कसौटी पर बेहतर होने के लिए जांच कराना सुनिश्चित नहीं कर सकती थी?

दूसरी बार गिर गये इस पुल को लेकर सरकारी दावे सामने आते रहे कि जल्दी ही इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जबकि बनने से पहले दो बार गिर चुका पुल कैसे जनता के लिये सुरक्षित हो सकता है? अगर उस पर वाहनों और लोगों की आवाजाही रहती तो अंजाम की त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद सच को झूठ साबित करने में जुटी सरकार इसको जानबूझकर गिराये जाने की बात कह कर भ्रष्टाचार को ढंकने की नाकाम कोशिश कर रही है। फिर भी इसे स्पष्ट किए जाने की जरूरत है कि पुल खुद ढह गया या फिर उसे गिराया गया। दोनों ही स्थितियों में यह तय है कि पुल के निर्माण में व्यापक खामियां थीं और वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को पुल निर्माण की जिम्मेदारी सौंप रही थी, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय-सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा गया था?

देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, विशेषत: राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश के विकास को अवरूद्ध कर रखा है। यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण-कार्यों के लिए रखे गए बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन-रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसके धराशायी होने की आशंका भी बनी रहती है। हादसों का एक बड़ा कारण जांच में दोषी और जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का न होना भी है। मोरबी हादसे के दोषियों को बचाने के प्रयास भी सबके सामने हुए हैं। हर हादसे के बाद लीपापोती के प्रयास खूब होते हैं। हादसे में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा बांटकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी समझने वाली सरकारों को इससे आगे बढ़ना होगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की पारदर्शी नीति नियामक केन्द्र बनाने के साथ उस पर अमल

भी जरूरी है।

हादसों की जांच से काम नहीं चलने वाला। ऐसे निर्माण कार्यों में कमीशन-रिश्वतखोरी रोकने पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ठेकेदार एक बड़ी राशि कमीशन के तौर पर दे देता है, तो फिर वह निर्माण कार्य भी गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति लापरवाह हो जाता है। लापरवाही की परिणति ऐसे हादसों के रूप में सामने आती है। प्रगतिशील कदम उठाने वाले नेतृत्व ने अगर भ्रष्ट व्यवस्था सुधारने में मुक्त मन से सहयोग नहीं दिया तो कहीं हम अपने स्वार्थी उन्माद एवं भ्रष्टता में कोई ऐसा धागा नहीं खींच बैठें, जिससे पूरा कपड़ा ही उधड़ जाए। राजनीति के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले में एक-दूसरे के पैरों के नीचे से फट्टा खींचने का अभिनय तो सभी दल एवं नेता करते हैं पर खींचता कोई भी नहीं। रणनीति में सभी अपने को चाणक्य बताने का प्रयास करते हैं पर चन्द्रगुप्त किसी के पास नहीं है। घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए हल्ला उनके लिए राजनैतिक मुद्दा होता है, कोई नैतिक आग्रह नहीं। कारण अपने गिरेबान में तो सभी झांकते हैं वहां सभी को अपनी कमीज दागी नजर आती है, फिर भला भ्रष्टाचार से कौन निजात दिरायेगा? ऐसी व्यवस्था कब कायम होगी कि जिसे कोई 'रिश्वत' छू नहीं सके, जिसको कोई 'सिफारिश' प्रभावित नहीं कर सके और जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सके। ईमानदारी अभिनय करके नहीं बताई जा सकती, उसे जीना पड़ता है कथनी और करनी की समानता के स्तर तक। आवश्यकता है, राजनीति के क्षेत्र में जब हम जन मुखातिब हों तो प्रामाणिकता का बिल्ला हमारे सीने पर हो। उसे घर पर रखकर न आएं। राजनीति के क्षेत्र में हमारा कुर्ता कबीर की चादर हो। तभी इन भ्रष्ट पुलों का भर-भराकर गिरना बन्द होगा।

- ललित गर्ग

आत्मनिर्भरता की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। रेलवे अब चीनी उत्पादों पर निर्भरता को कम कर रहा है जिसका असर दिखायी पड़ रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम भी गति पकड़ चुका है। यही कारण है कि चीन परस्त विरोधी दल लगातार मोदी सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं।

अब यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है कि जिस विपक्ष ने कभी कुछ किया ही नहीं और जिन लोगों ने नकारात्मक ढंग से केवल रेलवे को भ्रष्टाचार का अडडा बना दिया वहीं लोग आज रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और पूरी तरह से गलत व झूठ पर आधारित बयानबाजी कर रहे हैं।

विपक्ष के हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व रेल मंत्रियों नीतीश कुमार, लालू यादव और ममता बनर्जी के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार जो आजकल वर्तमान रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं अपना इतिहास भूल गये है। जब वह रेल मंत्री थे तब 79 बार दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई और सर्वाधिक एक हजार बार ट्रेनें बेपटरी हो गयीं जिसमें 1,527 मौतें हुई वहीं लालू प्रसाद यादव जो दुर्घटना के बाद अनाप- शनाप बयानबाजी कर रहे हैं उनके कार्यकाल में 51 बार ट्रेनों की टक्कर हुई और 550 बार पटरी से उतरी तथा 1,159 मौतें हुई वहीं ममता बनर्जी जो आजकल मोदी विरोधी मोर्चा बनाकर 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है उनके कार्यकाल में 54 बार ट्रेनों की टक्कर हुई 839 बार बेपटरी हुई और 1451मौतें हुयी है।

विपक्ष के जितने भी नेता अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं उन सभी को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए। यह लोग कभी घटनास्थल पर नहीं जाते थे और केवल दुख व्यक्त कर देने की खानापूरी कर देते थे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की असली नाराजगी यह है कि उन्होंने आने कार्यकाल में रेलवे में जो घोटाला किया है अब वह जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और गर्मी के अवकाश के बाद संभव है कि रेलवे में घोटाला करने वाला लालू परिवार जेल चला जाये।वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनकी सरकार के कई मंत्री घोटालों में बुरी तरह से फंस रहे हैं जिसमें कुछ जेल जा चुके हैं और कुछ जाने की तैयारी में है। इन सभी मंत्रियों ने रेल बजट तो कई बार पेश किया है लेकिन कभी उसमें कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका है और यही नाकाम व नकारा लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि, 'ट्रेन में कवच सिस्टम क्यों नहीं था?'

सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदी की भीषणतम दुर्घटना की जांच सीबीआई ने प्रारम्भ कर दी है और वह दुर्घटनास्थल पर पहुंच गयी है तब इन्हीं दलों ने सीबीआई जांच का भी विरोध शुरू कर दिया है जिससे इन दलों का विकृत दोमुंहापन उजागर हो रहा है और इन सभी दलों पर संदेह उठना स्वाभाविक भी है की कहीं यह सभी दल साजिशकर्ता देशद्रोही ताकतों के हाथों में तो नहीं चले गये हैं।

आज यह विपक्षी दल जिस सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं वह वर्ष 2022 के बजट में आया और अभी देश के दो फीसदी हिस्सों में ही है तथा संपूर्ण भारत में यह सुरक्षा कवच पहुंचने में लंबा समय लेगा। विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से लगता है कि वह केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने का असफल प्रयास कर रहे हैं और उन्हें रेलवे तकनीक का ज्ञान ही नहीं है। आज का विपक्ष आपदा में केवल अपने लिए अवसर की खोज कर रहा है। रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सुरक्षा कवच लगा भी होता तो भी दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता था। ट्रेन दुर्घटना ट्रेन के बेपटरी होने की वजह से हुई है और वहीं दूसरी ओर उसके साथ भारत का विपक्ष भी बेपटरी हो गया।

अमेरिका दौरे पर गये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस की सरकारों में ट्रेन दुर्घटनाएं होती थीं उसके मंत्री अपनी जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा दे देते थे किंतु अबकी बार इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चहा रहा। संपूर्ण विपक्ष केवल 'इस्तीफा दो, इस्तीफा दो' का नारा लगाता रहा जबकि मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्राउंड जीरो पर लगातार काम करते रहे और जब तक पूरा ट्रैक खाली नहीं हो गया और स्थितियां सामान्य नहीं हो गयी तब तक वह वहीं अपने कर्तव्यपथ और सेवापथ पर डटे रहे। यहां पर सबसे ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि रेल मंत्रालय के अब तक इतिहास में वह सबसे पढ़े लिखे रेल मंत्री बने हैं और वहां के हालातों को अच्छी तरह से समझते भी हैं। यही कारण है कि भीषणतम संकट और चुनौतियां आने के बावजूद वह वहां पर डटे रहे जिसकी आज सोशल मीडिया पर जमकर प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने एक-एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया और कई बार वह भावुक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लिया। तत्परता से सथियों को सामान्य बनाने का यह संयुक्त प्रयास था। ■

ERA UNIVERSITY

Winner of the prestigious SKOCH Award (Gold) 2022, for Innovations in Medical Education & Healthcare

Era's Lucknow Medical College and Hospital Has Been Ranked Among the Top Medical Colleges of India

RESEARCH OPPORTUNITIES AVAILABLE FOR STUDENTS

INTERNATIONAL ACADEMIC & RESEARCH COLLABORATIONS

- American University of Barbados, School of Medicine
- Universität Rostock, Germany
- Warwick, The University of Warwick

NATIONAL ACADEMIC & RESEARCH COLLABORATIONS

- CSIR-Indian Institute of Toxicology Research
- King George's Medical University
- Institute of Nano Science & Technology
- National Institute of Pharmaceutical Education and Research
- Central Drug Research Institute, Lucknow
- Centre Of Biomedical Research Lucknow

COURSES OFFERED

MEDICAL

- M.B.B.S
- M.D and M.S
- Fellowship and PDCC
  Register on www.elmcindia.org

NURSING

CERTIFICATE COURSE

- Infection, Prevention and Control

DIPLOMA

- Auxiliary Nursing and Midwifery (A.N.M. 2 Yrs)
- General Nursing and Midwifery (G.N.M. 3 Yrs)

BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)

- Bachelor of Nursing (B.Sc. 4 Yrs)
- Post Basic Bachelor of Science in Nursing (P.B.B.Sc. 2 Yrs)

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

- Medical Surgical Nursing
- Child Health Nursing (Paediatrics)
- Obstetrics and Gynaecology Nursing
- Mental Health Nursing (Psychiatric)
- Community Health Nursing

PHARMACY

- Diploma in Pharmacy (D.Pharm)
- Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)

MANAGEMENT

- Master in Hospital Administration (MHA)

SCIENCES

BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)

- Food and Nutrition
- Biotechnology

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

- Clinical Psychology
- Food and Nutrition
- Biotechnology
- Medical Physiology
- Medical Biochemistry
- Medical Microbiology
- Medical Pharmacology
- Medical Anatomy

COMPUTER SCIENCE

- Bachelor in Computer Application (B.C.A. 3 Yrs)

LIBERAL ART & SCIENCES

- B.Sc. / B.A. Multidisciplinary Liberal Education

MEDICAL & ALLIED SCIENCES

DIPLOMA

- C.T. Scan
- M.R.I. Technician
- Cardiology Technician
- Lab Technician
- OT Technician
- Dialysis Technician
- X-Ray Technician
- Optometry
- Anesthesia and Critical Care Technology
- Audio and Speech Therapy Technician
- BCG Technician and Tuberculosis Programme Management
- Respiratory Technician
- Minimal Access Surgical Technician
- Neonatal Care Technician
- Orthopaedic and Plaster Technician
- Prosthetic and Orthotic Technician
- Emergency and Trauma Care
- Intervention Radiology Technician
- Physiotherapy
- Clinical and Therapeutic Nutritionist

UNDERGRADUATE COURSES

- Bachelor of Physiotherapy (BPT)
- B.Sc. in Optometry (B.OPT)
- B.Sc. in Radiological Imaging Techniques (BRIT)
- B.Sc. in Medical Laboratory Techniques (BMLT)

POST GRADUATE COURSES

- Master in Physiotherapy

Ph.D PROGRAMMES

- Medical Anatomy
- Medical Biochemistry
- Medical Microbiology
- Medical Physiology
- Medical Pharmacology
- Molecular Medicine
- Molecular Biology and Genetics
- Pathology
- Biotechnology
- Biochemistry
- Nursing
- Pharmacy
- Physiotherapy
- Public Health
- Food and Nutrition
- Clinical Psychology
- Nanoscience and Nanotechnology
- Stem Cell Biology and Regenerative Medicine
- Chemistry
- English

The First Indian University to Establish Department of Happiness & Department of Personalised & Molecular Medicine

erauniversity.in admissions@erauniversity.in

0522 6672100, 8957926677, 9044050047, 72338 00901. Sarfarazganj, Hardoi Road, Lucknow - 226003

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE GHAZIABAD

AKGEC

College Code 027

SCALING THE ZENITH OF EXCELLENCE

Unmatched Record Breaking Performances

Accredited by NAAC A++ (Highest Grade)

Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow
Accredited by NBA for 5 Engineering Branches

24 YEARS OF EXCELLENCE

B.Tech.

- CSE • CSE (Hindi) • CSE (AI&ML)
- CSE (Data Science) • CS
- IT • CS&IT • ECE • ME • EN • CE

M.Tech.

- CSE • EN • ECE • ME

MCA

Master of Computer Applications

MBA (AKGIM -Code: 820)

- MKT • FIN • HR • IB • OM • IT

ACADEMIC EXCELLENCE TROPHY BEST ENGINEERING COLLEGE IN UPTU FOR TWO SUCCESSIVE YEARS

BEST INDUSTRY INSTITUTE ASSOCIATION AWARD BY ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING, U.K

TOP MOST RATING BY INSTITUTION INNOVATION COUNCIL (IIC) 2020-21 RANKINGS, MINISTRY OF EDUCATION (MOE), GOVT. OF INDIA

HIGHLIGHTS

- Silver Medal at India Skills 2021 National Competition in Additive Manufacturing Skills
- AKTU Chancellor's Medal for securing maximum marks across all branches bagged by AKGEC students for five consecutive years
- Distinguished Alumnus Award by AKTU bagged by AKGEC students for two consecutive years since its inception
- AKGEC Alumni at top positions in private and public sector and as successful entrepreneurs in India and abroad
- Students selected for higher education in IITs, IISc Bangalore, NITs, IIMs, IMT, XLRI and many other eminent institutions in India and abroad
- The only Institution in U.P. to have established the Common Facility Center for General Engineering Industry under "One District One Product (ODOP)" scheme of the Government of U.P.
- The only Institution in U.P. to have received approval from DST, Govt. of India, for establishment of Centre of Relevance and Excellence (CORE) in the field of Industrial Automation & Robotics
- Skill Development Centre established in partnership with National Skill Development Corporation (NSDC)
- Advance Technology Centres of Excellence in collaboration with eminent multinational companies for industry oriented training

PLACEMENTS

- Our recruiters include Infosys, TCS, Wipro, Accenture, Adobe, IBM, Amazon, Amdocs, Grofers, Airtel, Capgemini, Cognizant, Ericsson Global, Byju's, DLT Labs, HCL Technologies, Hitachi Consulting, HSBC Technology, Lohia Group, Microsoft Global Services Center (India), Newgen Software, NIIT, Reliance Jio, Samsung India Electronics, The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), Walmart Global Tech India and many more.

Placements (2021-22):
2008 offers (with 767 exclusive offers)

HIGHEST PACKAGES ACHIEVED BY AKGECians (2021-22)	
> = 25 LPA	30
> = 20 LPA	38
> = 10 LPA	79

HIGHEST Salary package drawn ₹1.13 Crore PA

This issue Published on 1st July, 2023 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2020-22, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089